खण्ड-355, अंक-4
गुरूवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(25 फरवरी, 1982 ई0)

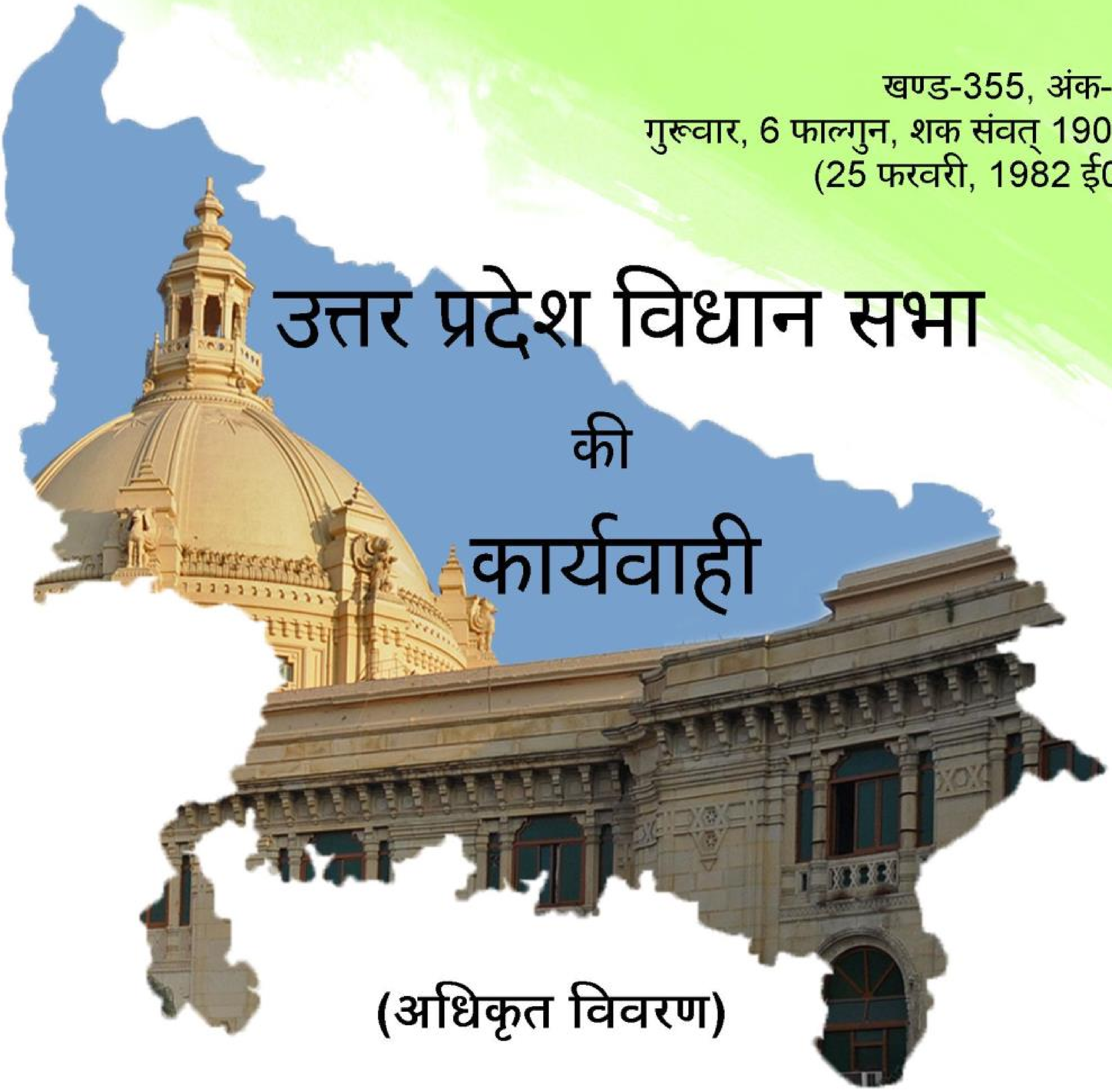

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	415–418
प्रश्नोत्तर	418–453
जनपद चमोली में जोशीमठ में विष्णु–प्रयाग परियोजना हेतु इन्टरनल सड़क के निर्माण में डायनामाइट के प्रयोग से जोशीमठ नगर को खतरा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	453–454
एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में छात्रों द्वारा अनशन के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	454
लिफ्ट सिंचाई विभाग जनपद जालौन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	454–455
प्रदेश के पर्वतीय जिलों में खरीफ की फसल में कुरमुला रोग का प्रकोप व सूखे से फसल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .	455
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्वारा चिकित्साधिकारियों के चयन में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	455–456
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 (संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखा गया)	456
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 (संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया)	456
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	457
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	457
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	457
कारागार मंत्री, श्री राम सिंह खन्ना के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	457–458
विधान सभा सदस्य, श्री ए0 सी0 ग्राइस द्वारा दल परिवर्तन की सूचना ..	458
श्री शंकर सिंह द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के संबध में जानकारी की मांग	458–459
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	459–460
मानिकपुर सतना रेल लाइन पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे से कारतूसों की चोरी के विषय में नियम 51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों में भिन्नता के संबंध में औचित्य का प्रश्न	460–462

1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 69–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या–71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निमण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) 462–520

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 520

हल्द्वानी में एक हरिजन बस्ती पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा हमला करके क्षति पहुंचाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 521–523

नत्थियां 524–529

विधान सभा प्रदेश उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 25 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--313

अकबर हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री .. गोंडा
अजहर ईमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीत कुमार सिह, श्री .. कानपुर
अजीत सिह सेठी, श्री .. मेरठ
अनवार खां, श्री .. अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री .. फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री .. आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री कानपुर
अमरनाथ सिह, श्री .. फतेहपुर
(उर्फ अनिल सिह)
अमीरुद्दीन, श्री .. बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री .. बरेली
अम्बिका सिह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री .. सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी .. बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
इन्द्र प्रताप सिह श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री .. इलाहाबाद
उदयवीर सिह, श्री .. शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिह, श्री .. खीरी
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिह, श्री .. गोंडा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री .. नाम निर्देशित
.. आग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री .. आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री ललितपुर
कन्हैया लाल श्री .. मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री .. लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती कानपुर
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिह, श्री .. जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्यान सिह सोलंकी, श्री .. बरेली
कल्लूराम, श्री .. मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री .. बलिया
किरनपाल सिह, श्री .. बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती .. गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री .. हमीरपुर
कुंवर सिह नेगी, श्री .. चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती .. हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री .. देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री .. रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण मगन सिह, श्री .. बाराबंकी
कृष्णवीर सिह, श्री .. बदायूं
कृष्णवीर सिह कौशल, डाक्टर आगरा
केदारसिह, श्री .. आजमगढ़
केदारनाथ सिह, श्री .. गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री .. जौनपुर
कैलाश चन्द्र, श्री .. एटा
कैलाश टण्डन, श्री .. वाराणसी
खरपत, श्री .. वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री .. फतेहपुर
खुशहाल सिह रांगड़, श्री .. टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री .. आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री .. कानपुर
गजेन्द्र सिह, श्री .. बाराबंकी
गया सिंह श्री . उन्नाव
गुलाम नबी, श्री .. आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती .. बस्ती
गोपाल राम दास, श्री .. अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री .. उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री .. फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री .. इटावा
गौरी देवी, श्रीमती .. गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री .. इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री .. बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 .. बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री .. आजमगढ़

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री .. लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री .. पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री .. पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री .. बरेली
छत्तर सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
छदा लाल चौधरी, श्री .. खीरी
छेदी लाल, श्री .. गोंडा
जंग बहादुर, श्री .. जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री .. इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री .. बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री .. गोरखपुर
जमना प्रसाद, श्री .. बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री .. अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री .. मुरादाबाद
झगड़ सिंह, श्री .. मेरठ
झिलमिट राम, श्री .. गाजीपुर
तपेश्वर, श्री .. आजमगढ़
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री .. खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री .. जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री .. पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री .. आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री .. बिजनौर
दलगजन सिंह, श्री .. जालौन
दामोदर शर्मा, श्री .. मेरठ
दीना नाथ, श्री .. बस्ती
दीपक कुमार, श्री .. मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री .. देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री .. आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री .. बहराइच
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री .. कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री .. देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती .. वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर .. अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री .. मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री .. मुजफ्फरनगर
धर्मसिंह, श्री .. बुलन्दशहर
ध्रुपराय, श्री .. देवरिया
नकली सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री .. हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री .. देवरिया
नन्द राम, श्री .. बरेली
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री .. पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री .. हरदोई
नाजिर अली, श्री .. शाहजहांपुर
नेत्रपाल सिंह, श्री .. एटा
पंचानन राय, श्री .. आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री .. गोरखपुर
परमाई लाल, श्री .. हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री .. बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री .. सीतापुर
पहलवान, श्री .. जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती .. बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री .. अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री .. हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री .. बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री .. प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री .. जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री .. प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री .. फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती .. बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती .. लखनऊ
फखरे आलम, श्री .. बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर, श्री .. रामपुर
बंशीधर राज, श्री .. खीरी
बच्चा पाठक, श्री .. बलिया
बनवारी राम, श्री .. वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री .. बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री .. इटावा
बलबीर सिंह, श्री .. फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री .. रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री .. उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री .. पीलीभीत
बाबूलाल, श्री .. गोंडा
बाबू लाल, श्री .. हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री .. अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री .. नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री .. फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा० .. देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती .. झांसी
भगवती सिंह विशारद, श्री .. उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री .. कानपुर
भागीरथ, श्री .. झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री .. बरेली
भीखा लाल, श्री .. उन्नाव
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .. गोरखपुर

भोला पांडेय, श्री .. बलिया
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री .. बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री .. मेरठ
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री एटा
मसरूर जाफरी, श्री .. गोंडा
(उफशबरोज)
महाबीर सिंह, श्री .. सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री .. आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती .. इटावा
महेश प्रसाद श्री .. देवरिया
माधव प्रसाद, श्री .. फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री .. गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री .. गोरखपुर
मित्रसेन, श्री .. फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री .. बदायूं
मुईद अहमद, श्री .. सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री .. सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री .. मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री .. गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री .. रामपुर
मेंहदी असगर, श्री .. मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री .. कानपुर
मोहन लाल, श्री .. हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री .. देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर .. गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री .. बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री .. लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान .. वाराणसी
अन्सारी, श्री
यदुनाथ सिंह, श्री .. मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री .. सहारनपुर
योगेश चन्द्र, श्री .. वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री .. मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री .. झांसी
रती राम, श्री .. बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री .. इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री .. रायबरेली
राज किशोर राव, श्री .. बहर इच
राज कुमार राय, श्री .. आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती .. सुल्तानपुर
राजमंगल पांडेय, श्री .. देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री .. सीतापुर
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री .. फर्रुखाबाद
राधेश्यम पटेल, श्री .. इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री .. फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री .. बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री .. हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री .. हरदोई
राम करन, श्री .. वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री .. आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री .. सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 .. जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री .. मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री .. बलिया
राम चन्द्र, श्री .. वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री .. मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री .. वाराणसी
रामजी राम, श्री .. फैजाबाद
राम धनी, श्री .. गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री .. कानपुर
राम प्यारे पांडेय, श्री .. फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री .. जालौन
राम प्रसाद, श्री .. मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री .. खीरी
राम रतन सिंह, श्री .. सीतापुर
राम लाल, श्री .. सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री .. हरदोई
राम शिरोमणि , श्री .. जौनपुर
राम समुझावन, श्री .. जौनपुर
राम सागर, श्री .. बाराबंकी
राम सिंह, श्री .. सहारनपुर
राम सिंह, श्री .. सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री .. बरेली
राम सिंह रावल, श्री .. एटा
राम सेवक, श्री .. सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री .. सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री .. कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री .. बहराइच
राम हर्ष राय, श्री .. गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री .. बांदा
रियासत हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
रुप राम, श्री .. शाहजहांपुर
लटूरी सिंह, श्री .. एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री .. मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
लालसा, श्री .. आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री .. मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री .. प्रतापगढ़

विजय कुमार, श्री .. लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री .. गाजीपुर
विजय सिंह, श्री .. मिर्जापुर
विद्याभूषण, श्री .. मुजफ्फरनगर
विद्यासागर नौटियाल, श्री .. टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री .. फर्रुखाबाद
विशन लाल, श्री .. बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री .. बांदा
विश्राम दास, श्री .. इलाहाबाद
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री .. सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर .. गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री .. वाराणसी
शंकर सिंह, श्री .. जालौन
शम्भूनाथ, श्री .. आजमगढ़
शिरोमणि, श्री .. बांदा
शिव दर्शन, श्री .. रायबरेली
शिव नरेश, श्री .. बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिव बालक, श्री .. रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री .. मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री .. फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री .. गोरखपुर
श्यामलाल बाजपेयी, श्री .. बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री .. बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री .. इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री .. बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री .. वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री .. सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री .. वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री .. खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री .. इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री .. नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री .. लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती .. बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री .. प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री .. मथुरा
साहब सिंह, श्री .. गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री .. शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती .. इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री .. देवरिया
सुन्दर सिंह, श्री .. बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी .. कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री .. सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री .. बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री .. अलीगढ़
सुरेशदत्त पालीवाल श्री .. जालौन
सूबेदार सिंह, श्री .. मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री . जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री .. मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री .. हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री .. एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री .. सीतापुर
हरदेव, श्री .. बलिया
हरिद्वार पांडेय, श्री .. गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री .. उन्नाव
हरिवंश सहाय , श्री .. देवरिया
हरि सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री .. हरदोई
हुकम सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में पेयजल हेतु लगाये गये हैन्ड पम्पों में किये गये भ्रष्टाचार संबंधी पत्र

*1—श्री मित्रसेन तथा श्री राम गोविन्द—

क्या सरकार को जानकारी है जनपद फैजाबाद में पेयजल राहत कार्यों के अधीन लगाये गये हैण्ड पम्पों में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में नेता पार्टी के भू0 पू0 विधायक एवं "भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन" की संघर्ष समिति के संयोजक श्री रवीन्द्र

नाथ तिवारी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 7-9-81 तथा 22-9-81 को पत्र लिख कर शिकायत किया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

जी हां, पत्र में हैण्ड पम्पों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। आरोपों पर जांच की जा रही है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह स्थगित प्रश्न है और अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं मालूम हो सकी है। तो इस मामले की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और अभी तक की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, एस0 डी0 एम0 अकबर पुर के द्वारा जांच की गयी है। हैण्ड पम्पों के निर्माण में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में बोरिंग मैकेनिक रामधनी यादव तथा सहायक विकास अधिकारी श्री फजल हसन खां को आरोपित किया गया है।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, आक्षेप कौन-कौन से हैं और क्या जांच की कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुयी है ? यदि हां,तो कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

खास आरोप यह है कि जितना लम्बा पाइप बोरिंग करना था उससे कम लम्बाई का पाइप डाला गया है। यह मुख्य आरोप है।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, जांच की अंतरिम रिपोर्ट अभी तक शासन के पास आयी है कि नहीं आयी है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, जितनी सूचना आ गयी है वह मैंने सदन के सामने रख दी है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप पाये गये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कृष्ण गोयल--

दोनों को आरोप-पत्र (चार्जशीट) दे दिये गये हैं।

जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में मरीजों को एक्स-रे की सुविधा न मिलने से संबंधित शिकायती पत्र

*2--श्री किरनपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में मरीजों को एक्सरे की सुविधा न मिलने से संबंधित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 12 मार्च, 81 को प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उ0 प्र0 को उक्त शिकायत की जांच करने के आदेश मन्त्री जी द्वारा निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

जी हां। जी हां। मण्डलीय संयुक्त निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा जांच कराई गई। यह शिकायत सही नहीं है कि माह सितम्बर, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक नगण्य एक्स-रे चित्र लिये गये। न यह सही है कि उपरोक्त तीन महीने में चिकित्सालय में एक्स-रे प्लेट्स थी ही नहीं। उपरोक्त अवधि में 666 एक्स-रे चित्र लिये गये और स्टाक में विभिन्न साइजों के 1,163 एक्स-रे प्लेटस मौजूद भी थी। शेष शिकायतों की कोई पुष्टि नहीं हो सकी।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, 22 मार्च, 81 के पत्र में मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया था कि वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे और आपसे भी सम्पर्क करेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस वरिष्ठ अधिकारी ने जांच की है उसने क्या प्रश्नकर्ता से सम्पर्क किया है। अगर नहीं किया तो मंत्री जी के आदेशों के बावजूद क्यों नहीं किया ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, ज्वाइंट डाइरेक्टर, मेरठ मंडल ने जांच की थी और जांचकर्ता ने रिपोर्ट दी है कि माननीय विधायक से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की लेकिन विधायक जी मिल नहीं पाये।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने भी कई बार जांचकर्ता से संपर्क करने की कोशिश की। मैंने स्वयं टेलीफोन पर संपर्क किया। मैं पिछले दिनों 12 से 16 तारीख तक अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल से मैंने टेलीफोन किया कि मैं यहां भर्ती हूं बाहर न मिल सकता, लेकिन अस्पताल में तो मिल सकूंगा, यहां आ जांय लेकिन वह नहीं आये। उसके बाद उन्होंने कहा कि इतवार को संपर्क करुंगा मैंने कोशिश की लेकिन संयुक्त निदेशक मेरे पास नहीं आये। जो जांच रिपोर्ट आयी है उसमें असत्य बात बतायी गयी है। एक रोज मैं एक मरीज अस्पताल में भर्ती कराने गया था। एक मरीज वहां पर बाहर की दूकान में एक्स-रे कराने आ रहा था। मान्यवर, जितनी एक्स-रे प्लेट्स वहां पर बतायी गयी हैं, उतनी तो उन दिनों इंडेंट भी नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है कि इन चार-पांच महीने में कोई भी एक्स-रे नहीं हुआ है अगर हुआ होगा तो बड़े अधिकारियों या रूलिंग पार्टी के एम0 एल0 ए0 या मिनिस्टर्स का हुआ होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे जानबूझकर संपर्क क्यों नहीं स्थापित किया गया और क्या जांच के आदेश आप फिर से देंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, विधायक जी से संपर्क नहीं हो पाया है तो विधायक जी से संपर्क हमारे जांच करने वाले अधिकारी कर लेंगे।

तालकटोरा आवास योजना में श्री राज कुमार बख्शी की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा वर्तमान गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी को दिया गया मुआवजा

*3--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जनपद लखनऊ में सन् 1962 की ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत जो भूमि श्री राज कुमार बख्शी की अधिग्रहीत की गयी थी उसका मुआवजा वर्तमान गृह मन्त्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने अपने पति राजा राज कुमार बख्शी के वारिसान के रूप में 3 मई, 1976 को प्राप्त किया ? यदि हां, तो श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने प्रथम बार कब मुआवजा प्राप्त किया और उनके पति श्री राज कुमार बख्शी की मृत्यु कब हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

तालकटोरा योजना में समाविष्ट भूमि के मुआवजे के प्रतिकर वितरण में अनियमितता पाई गई है तथा यह मामला समस्त अभिलेखों सहित सी0 आई0 डी0 को जांच के लिये सौंप दिया गया है। सी0 आई0 डी0 की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो यह रहा है कि आपके निर्देश के बावजूद अनुपूरक प्रश्नों का असंगत और गोलमाल उत्तर आता रहा है। आपने कई बार निर्देश भी दिया, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इसका लिखित उत्तर जो मुझे दिया गया है वह भी असंगत और बिल्कुल गोलमाल है। आप देखें, हमने पूछा था कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जनपद लखनऊ में सन् 1962 की ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत जो भूमि श्री राजकुमार बख्शी की अधिगृहीत की गयी थी उसका मुआवजा वर्तमान गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने अपने पति राजा राज कुमार बख्शी के वारिसान के रुप में 3 मई, 1976 को प्राप्त किया? यदि हां, तो श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने प्रथम बार कब मुआवजा प्राप्त किया और उनके पति श्री राजा कुमार बख्शी की मृत्यु कब हुयी।" मान्यवर, इसकी जांच तो होगी नहीं कि माननीय गृह मंत्री के पति की मौत कब हुयी ?

मान्यवर देखिए, उत्तर क्या दिया गया है। कहीं इसका जवाब नहीं दिया गया है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में मामले की जांच सी0 आई0 डी0 को दी गयी ? क्या यह सही है कि प्रागदर्शन में माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध अभियोग बना और तब सी0 आई0 डी0 को जांच दी गयी ? दूसरी बात सी0 आई0 डी0 को यह जांच कब दी गयी ? इसका जवाब दे दें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

तालकटोरा योजना से संबंधित जो आवास विकास परिषद् ने भूमि अधिग्रहीत की थी, उसमें सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ तक रुपया जिलाधिकारी के यहां जमा किया था और भी जिन विभागों ने भूमि अधिगृहीत की होगी, जिलाधिकारी के यहां रुपया जमा किया होगा। शासन के सामने यह मामला आया कि 3-3 1/2 करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ। सन् 1978 में यह मामला सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द किया गया कि इसकी छानबीन करें, उसी के तहत सी0 आई0 डी0 के पास सारे अभिलेख वगैरह हैं और वह उसकी विवेचना कर रहें हैं। शासन निदेश दे चुका है सी0आई0 डी0 को कि जो लोग दोषी हों उन पर मुकदमा चलायें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, प्रश्न गृहमंत्री के विरुद्ध है। उनसे संबंधित जो मामला है, वह सी0आई0 डी0 को कब दिया गया ? क्यों दिया गया ? किन परिस्थितियों में दिया गया, सारे मामले से हमारा मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

प्रश्न की आखिरी दो लाइनों में जो दो विषय हैं कि क्या 3 मई, 1976 को मुआवजा प्राप्त किया गया? उसका उत्तर "हां" या "नहीं" में दें। दूसरा प्रश्न यह है कि पहले मुआवजा कब वसूल किया गया ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर "हां' या "नहीं" में माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, सारे अभिलेख सी0 आई0 डी0 के पास हैं और वह उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर; मुआवजा कब दिया गया, इसके तो अभिलेख होंगे ही।

श्री हुकम सिंह--

सी0 आई0 डी0 में जो अभिलेख हैं, वह तो इस सारे मामले की फौजदारी के संबंध में हैं कि कोई आफेन्स बनता है या नहीं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 के अभिलेखों को नजरअन्दाज करते हुये केवल इतना बता दें कि 3 मई, 1976 को कोई मुआवजा इन्होंने लिया या नहीं? अगर लिया, तो कितना? अभिलेख कहीं भी हों।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, सारे अभिलेख सी0 आई0 डी0 के पास हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि सारे अभिलेख सी0आई0डी0 के पास हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि सवाल के अन्त में लिखा है कि मा0 गृहमन्त्री जी के पति श्री राजकुमार बख्शी की मृत्यु कब हुई है? यह तो मा0 मन्त्री जी बता सकते हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इसके महत्व को देखते हुये इसे स्थगित कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि यह अभिलेख सी0 आई0 डी0 में नहीं गये कि उनके पति श्री राज कुमार बख्शी की मृत्यु कब हुई है, यह बात तो म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में अंकित होनी चाहिये। यह सी0 आई0 डी0 का विषय नहीं है। यह तो जन्म-मृत्यु का रजिस्टर जो होता है, उसमें दर्ज होती है। मान्यवर, यदि मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो इसे आप स्थगित कर दें, अगली बार ये बता देंगे।

श्री ऊदल--

अगर प्रश्न में यह बात उल्लिखित है तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को म्यूनिसिपैलिटी से मंगा लेना चाहिये था, परन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के पति राजा राज कुमार बख्शी की मृत्यु की सूचना मंत्री जी द्वारा न मंगाये जाने के क्या कारण है?

श्री मोहन सिंह--

क्या इसकी भी जांच सी0 आई0 डी0 कर रहा है कि वह जिन्दा है या मर गये ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, राजा राज कुमार बख्शी की मृत्यु हो चुकी है, वह कब हुई है, यह सूचना म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर से मंगा कर सदन को सूचित कर दूंगा ।

(व्यवधान)

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर जोर-जोर से बोलने लगे ।)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत रहस्यमय है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जाइये ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले सुन लें कि जितनी भूमि वहां अधिगृहीत की गयी उसके लिये इन्होंने बताया कि सब में घोटाला है और यह भी बताया कि सबके संबंध में सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है और इस संबंध में जितने अभिलेख हैं वह सब सी0 आई0 डी0 के पास हैं । इसके बाद आपने एक प्रश्न किया कि उनकी मृत्यु कब हुई ? जाहिर है कि यह अभिलेख यहां नहीं है । कहीं अन्यत्र वह अभिलेख हैं, उसके लिये उन्होंने उत्तर दे दिया है कि उस सूचना को वे म्यूनिसपेलिटी के रजिस्टर से मंगा कर सदन को बता देंगे ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 प्रदेश के बाहर है क्या ?

श्री मोती लाल देहलवी--

किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है त्री मंजी ने । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसे स्थगित कर दें ।

श्री हुकम सिंह--

इसको स्थगित कीजिये, मान्यवर ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, इसका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है, इसको आप स्थगित कीजिये ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, ये आपकी उदारता का फायदा उठा रहें हैं । इस प्रदेश का गृह मंत्री लाखों, करोड़ों रुपयों का घपला करें और गलत तरीके से रुपया ले, मरे हुये आदमी के नाम पर । गृह मंत्री ने लाखों रुपया लिया है अपने पति के नाम पर और मंत्री जी तथ्य को छिपा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

अब आगे, प्रश्न संख्या 4 लें रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सारे कागजात मिनिस्टर होने के नाते टेम्पर किये जा रहे हैं। मान्यवर, यह गृह मंत्री का मामला है, इसमें सी0 आई0 डी0 से इनक्वायरी निष्पक्ष नहीं होगी, जब तक वे गृह मंत्री रहेंगी।

श्री हुकम सिंह--

पहले उन्हें पद से हटाइये, तब जांच कराइये सी0 आई0 डी0 से।

श्री अध्यक्ष--

बस हो गया, अब आप बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आप सिर्फ एक प्रश्न मुझे कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष--

पूरा प्रश्न पुनः आप सुनें, प्रश्न है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जनपद लखनऊ में सन् 1962 की तालकटोरा आवास योजना के अन्तर्गत जो भूमि श्री राज कुमार बख्शी की अधिग्रहीत की गयी थी उसका मुआवजा वर्तमान गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने अपने पति राजा राज कुमार बख्शी के वारिसान के रूप में 3 मई, 1976 को प्राप्त किया? यदि हां, तो श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने प्रथमवार कब मुआवजा प्राप्त किया और उनके पति की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर यह आया है कि तालकटोरा योजना में समाविष्ट भूमि में मुआवजे के प्रतिकर वितरण में अनियमितता पाई गई है तथा यह मामला समस्त अभिलेखों सहित सी0 आई0 डी0 को जांच के लिये सौंप दिया गया है। सी0 आई0 डी0 की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो प्रश्न में क्या सरकार कृपया बतायेगी से ले कर 3 मई, 1976 को प्राप्त किया? यदि हां, तो श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने प्रथम बार कब मुआवजा प्राप्त किया, यहां तक का सारा उत्तर जो दिया है--तालकटोरा योजना में समाविष्ट से लेकर सी0 आई0 डी0 को जांच के लियें सौंप दिया गया है। अब बाद का प्रश्न है कि श्री राज कुमार बख्शी की मृत्यु कब हुई, तो यह निश्चित है कि यह उत्तर में सम्मिलित नहीं था, यह उस से अलग था और उसके लिये उन्होंने (मंत्री जी ने) सदन में सूचना देने के लिये कहा है। अब इसके बाद आप, मोती लाल जी, जो प्रश्न करना चाहें करें।

(व्यवधान)

हां, यह भी आया कि सी0 आई0 डी0 किसकी है, वह शासन की है। उस से आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो जो मांग पेश करना चाहते हैं, करें प्रश्न से उसका क्या संबंध है।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह जानते हुये कि यह मामला गृह मंत्री से संबंधित है और जांच कौन कर रहा है, सी0आई0डी0, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कहीं सुन रहें हों, माननीय गृह मंत्री जी का (गृह मंत्री के पद से) इस्तीफा ले कर सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे? अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो क्या इसकी जांच सी0 बी0 आई0 को देने के लिये तैयार हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, जब इसकी आवश्यकता होगी, इस पर विचार किया जायेगा।

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

गृह मंत्री के पद पर रहते हुये जांच सी0 आई0 डी0 से कतई निष्पक्ष नहीं हो सकती और मेरी जानकारी के अनुसार पेपर टेम्पर किये जा रहें हैं। 3-3 सी0 आई0 डी0 इन्स्पेक्टर बदल गये क्योंकि वे निष्पक्ष...

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे कि क्या इस परिस्थिति में उनका इस्तीफा लेगें या जांच सी0 बी0आई0 को देगें, मंत्री जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता होगी तो इस पर विचार किया जायेगा। आपने आवश्यकता तत्काल समझी है और इन्होंने (मंत्री जी ने) आप की बात सुनी है और कहा है कि हम भी (सरकार) विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह सम्पूर्ण रूप से हेरा-फेरी का मामला है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह सारा मामला गोल-माल करने के लिए सी0आई0 डी0 को दिया गया है और सरकार इस औचित्य को भी स्वीकार नहीं कर रही है कि या तो गृह मंत्री का. . . .

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

श्रीमन्, जनता पार्टी की सरकार सन् 78 से 79 तक रही और उसी सरकार ने सी0 आई0 डी0 को इसे दिया था जिसकी विवेचना चल रही है। उनकी सरकार ने ही सी0 आई0 डी0 को इसे सौंपा था ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

उस वक्त वे गृह मंत्री नहीं थीं। अब स्थिति बदल गयी है। अब वे आज गृह मंत्री के बड़ी जिम्मेदार पद पर हैं।

(व्यवधान)

यह सरकार अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। हमें विश्वास है कि सी0आई0डी0 से गृह मंत्री के खिलाफ जांच कराने से सही न्याय नहीं हो सकेगा ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मोतीलाल देहलवी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

संस्थापक व महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का विभागीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र

*4--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि संस्थापक व महासचेतक, आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा, शाखा, उ0 प्र0 द्वारा दिनांक 23-2-81 को स्वास्थ्य निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ को विभागीय घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई पत्र प्रेषित किया है? यदि हां, तो उक्त में उल्लिखित अनियमितताओं में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह--

स्वास्थ्य सेवा निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायती पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामनारायन तिवारी--

जो उत्तर आया है उसमें लिखा है कि कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ कि नहीं, ऐसा-प्रतीत नहीं होता है मान्यवर, मेरे पास पत्र के प्राप्ति की कापी मौजूद है और इस पर हस्ताक्षर भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब इससे प्रतीत होता है कि पत्र की प्राप्ति हुई तो मुझे इसका उत्तर दिलवायेंगे ? और यदि नहीं, तो मुझे अब इस संबंध में क्या करना होगा, यह बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बतलाया कि पत्र की प्राप्ति नहीं हुई।

श्री श्यामनारायन तिवारी--

रसीद की कापी हमारे पास है, पत्र की कापी भी है।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको दिखला देंगे तो फिर वे उसे दिखवा लेंगे।

श्री हरिसिंह--

अगर कोई शिकायत उनकी है तो मैं बाद में उसे दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि आपने अपने पास पत्र की कापी या रसीद होने की बात कही, उसकी माननीय मंत्री जी पुनः जांच करा लेंगे।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मैं जानना चाहता हूं कि कापी और रसीद के होते हुए भी जिस अधिकारी ने उनको गुमराह किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष--

जब जांच करायेंगे तो बतला देंगे।

*5--श्री विजय सिंह राना--

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

*6--श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

[7 वें शुक्रवार मे तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

(बृहस्पतिवार 25 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की मांगें

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा प्रदेश भर में सामूहिक हड़ताल 2 जुलाई, 1981 तथा उसके आसपास की गयी ? उनकी मांगें क्या थीं ? इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह --

जी नहीं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की निम्नलिखित मांगें हैं:

1--वर्दी का दिया जाना।

2--वर्दी धुलाई भत्ते का दिया जाना।

3--12 घन्टे रात्रि ड्यूटी करने पर चार नाईट आफ के स्थान पर आठ नाइट आफ नर्सिंग स्टाफ की भांति दिया जाना।

4--अस्पतालों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पर्वों एवं त्योहारों, अराजपत्रित अवकाश की अवधि में पुलिस कर्मचारियों एवं जेल कर्मचारियों की भांति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का वेतन दिया जाना। संघ की उक्त मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये मांगे शासन के सामने बहुत दिनों से विचाराधीन हैं, करीब एक डेढ़ वर्ष से और नीचे स्तर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित हैं तथा इनमें कुछ मांगें ऐसी हैं जिनसे शासन पर कोई वित्तीय व्यय भार भी आता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन मांगों पर कोई वित्तीय व्यय नहीं है, उनको तत्काल स्वीकार न करने का क्या कारण है? साथ ही जिन का वित्तीय मामले से संबंध है उन पर अंतिम विचार कब तक हो जायेगा ?

श्री हरि सिंह--

जैसा कि मैंने कहा, तमाम प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कुछ मांगें ऐसी हैं जिनका वित्तीय भार से विशेष कोई ताल्लुक नहीं है, उनके तथा अन्य सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कुछ मांगें जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि मैंने ठीक कहा है कि वित्त से कोई संबंध नहीं है, क्या सिद्धांतः ये चारों मांगें शासन स्वीकार करता है और उसके बाद भी वह कब कैसे पूरा किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ? अगर इसकी विवेचना करना बाकी है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि सिद्धांतः इन चारों मांगों को शासन स्वीकार करता है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, इन सभी मांगों पर शासन विचार कर रहा है। जहां तक सिद्धांत का सवाल है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में हमेशा हमारी सरकार की सहानुभूति पूर्ण भावना रहती है।

साधन सहकारी समिति के चुनाव तथा निर्वाचन क्षेत्र

*2--श्री रियासत हुसैन--

क्या सहकारिता मन्त्री को विदित है कि जुलाई, 81 में जो चुनाव साधन सहकारी समितियों के होने वाले थे और बाद में स्थगित कर दिये गये उनमें ब्लाक मूण्डा पाण्डे, जिला मुरादाबाद की 5 सहकारी समितियों में तो नम्बर 4, 5 निर्बल वर्ग और नम्बर 6 हरिजनों के लिए रिजर्व की गयी, परन्तु एक सहकारी समिति सरकड़ा खास, जिला मुरादाबाद में 4 व 5 निर्बल वर्ग के लिए और 6ठी सोसायटी को छोड़कर 7वीं सोसायटी (रामपुर भिला) को हरिजनों के लिये रिजर्व किया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--
जी नहीं

सरकड़ा खास साधन सहकारी समिति में भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 व 5 निर्बल वर्ग के लिए तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 हरिजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं। क्र0 सं0 6 पर अंकित निर्वाचन क्षेत्र, मुहम्मदपुर कुलीपुर उर्फ नगला का नाम बहुत बड़ा था और उसके सम्मुख स्थान कम होने से आरक्षित की मुहर नीचे लग गई थी। जब यह पता चला कि इस मुहर को छठे निर्वाचन क्षेत्र के बजाय सातवें के लिए माना जा रहा है, तो निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आप स्वयं देखें कितने भोंड़ेपन से अनियमितता छिपायी गयी है नाम बड़ा था इसलिए मोहर नीचे लग गई और वह बाद में दुरुस्त कर दी गई। बहरहाल, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मुहम्मदपुर कुलीपुर उर्फ नगला आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए आप के उत्तर के अन्तर्गत, इसमें जो नामिनेशन फाइल किया गया वह नामिनेशन आरक्षित की हैसियत से फाइल किया गया या साधारण क्षेत्र के हैसियत से फाइल किया गया।

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, जो नामिनेशन दाखिल किये गये थे उनमें केवल मुहर गलत लग गई थी। इसका पता लगा लेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

अब चूंकि आप पता लगायेंगे, इनक्वायरी करेंगे तो मैं चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में पूरी जांच करायेंगे कि मुहम्मदपुर कुलीपुर उर्फ नगला का जो आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए आपके उत्तर के मुताबिक इसमें जो नामिनेशन फाइल किये गये थे वह आरक्षित क्षेत्र के नहीं फाइल किये गये बल्कि साधारण क्षेत्र के फाइल किये गये। बाद में इलेक्शन स्थगित हो गये। इसमें जिन अधिकारियों ने साधारण तरीके से नामिनेशन लिये हैं उनके विरुद्ध जांच करा कर कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

हम तो पहले ही कहे उसका पता लगाकर जांच करा लेंगे।

*3--श्री केदारनाथ सिंह--

[4-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 101 द्वारा उत्तरित]

धुधली विकास क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा मिट्टी के तेल एवं चीनी वितरण में अनियमितता संबंधी पत्र

*4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने धुधली विकास क्षेत्र, धुधली (गोरखपुर) की सहकारी समितियों द्वारा मिट्टी का तेल एवं चीनी वितरण में अनियमितता संबंधी कोई पत्र उन्हें दिनांक 15 मई, 1981 को दिया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में क्या कोई जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कब की गई और जो मैंने शिकायती पत्र दिया था उसमें लिखा था कि जांच की सूचना मुझे भी दी जाय ताकि मैं कुछ अन्य साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत कर सकूं, जांच कब की गई, क्या उसकी सूचना आरोपकर्ता यानी मुझे दी गई ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, 15-5-81 का आप का पत्र रहा, 26-10-81 को मिला, जांच करायी गयी, जांच के समय विधायक जी को भी खोजा गया परन्तु नहीं मिले। जांच के बाद जो बात हुई वह की गई।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मेरी तलाश कहां की गई ? मैं निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जाता। यह निरर्थक उत्तर है। जांच अधिकारी वही व्यक्ति थे जिनके बारे में मेरा आरोप है। क्या इस मामले की खुली जांच करा कर गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो पुनः लिख देंगे तो जांच करा देंगे।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

यह गलत बात होगी। मैं पुनः लिख कर नहीं दूंगा। क्या माननीय मंत्री जी खुद संतुष्ट हो गये ? सदन संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे संतोष नहीं हुआ, माननीय मंत्री जी कैसे संतुष्ट हो जायेंगे। मेरे लिखकर देने का प्रश्न नहीं है। क्या जिस अधिकारी ने गलत सूचना देकर आपको गुमराह किया उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए पुनः इस मामले की खुली जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

माननीय सदस्य जिससे कहेंगे, मैं उससे जांच करा दूंगा।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं नहीं कहता कि आप किससे जांच करायें। मैं तो यह कह रहा हूं कि जिस अधिकारी ने आपको यह गलत सूचना दी कि मुझ से सम्पर्क स्थापित किया गया किन्तु मैं नहीं मिला, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे और फिर से पूरी जांच कराने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, जांच की गई थी। जो लोग दोषी पाये गये, उनको सजा दी गई। अगर आप पुनः जांच कराना चाहते हैं तो वह भी करा ली जायेगी।

जनपद पौड़ी गढ़वल के रेलवे स्टेशन कोटद्वार में रेल के वैगन में अवैध रूप से पकड़ी गयी चीनी

*5--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के रेलवे स्टेशन कोटद्वार में रेल के वैगन में कितनी अवैधरूप से ली जा रही चीनी पकड़ी गयी तथा किनके आदेश से वह चीनी पुनः रिलीज कर दी गयी थी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)---

वर्ष 1980 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के रेलवे स्टेशन कोट द्वार में रेलवे वैगन में अवैध रूप से ले जा रही चीनी नहीं पकड़ी गई। अतः पकड़ी गई चीनी के रिलीज किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन को वर्ष 1980 में कोटद्वार से यह शिकायत मिली थी कि रेलवे के एक वैगन में अवैध रूप से चीनी पाकिस्तान जा रही है जिसके फलवरूप वह वैगन जब्त कर लिया गया था परन्तु बाद में उस वैगन को यह कहकर कि उसमें चीनी नहीं सल्फर या खांडसारी है, रिलीज कर दिया गया। क्या यह सत्य है? यदि हां, तो क्या इसका कहीं परीक्षण कराया गया?

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, यह बात सही है कि वहां पर हमारे जो मौजूदा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मधुर शास्त्री हैं उन्होंने पर्वतीय विकास मंत्री श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी को सूचना दी कि कोटद्वार से इस तरह से चीनी जा रही है। वह पकड़ी गई औरउस पर कार्यवाही की गई। मान्यवर, जब यह मामला हमारे विभाग को मालूम हुआ तो जिलाधिकारी को कहा गया कि वह इसको देखें। खांडसारी पर प्रतिबन्ध नहीं है। उन्होंने देखा तो वह खांडसारी सिद्ध हुई। इसलिये उसको छोड़ देना पड़ा।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या उसका परीक्षण कराया गया?

श्री वासुदेव सिंह---

जिलाधिकारी ने उसको देखा और पाया कि वह खांडसारी थी, इसलिये उसको छोड़ दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस समय शासन के ज्ञान में यह बात आ गई कि वह मिल की चीनी न होकर खांडसारी की चीनी है, जिस पर बाहर जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है, क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि वह कौन व्यक्ति था जिसने उसको भेजा और किसको वह भेजी जा रही थी और किससे वह खरीदी गई थी? क्या उस व्यापारी के पास उसका लाइसेन्स था? यदि नहीं था, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, पूरा मामला यह है कि जब शासन को यह मालूम हुआ कि इस तरह से चीनी जा रही है तो यहां से रेडियोग्राम गया। वह चीनी महालक्ष्मी उद्योग फैक्टरी नजीबाबाद तथा शुगर फैक्टरी, नजीबाबाद की ओर से उनके 19 सितम्बर, 1980 के आवेदन-पत्र पर (454 बोरी खांडसारी गिलावट और सलावट) जा रही थी और कोटद्वार से अमृतसर के करीब महाबला जा रही थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैंने दो बातें पूछी कि जो आदमी भेज रहा था उसके पास लाइसेंस था क्योंकि बिना किसी लाइसेंस के कोई व्यापार नहीं कर सकता है। मैंने यह भी जानना चाहा कि चूंकि शासन को संदेह था कि यह चीनी हैऔर इसको खांडसारी में परिवर्तित कर दिया गया है,तो वह चीनी प्राईवेट थी या किसी के पास बेचने के लिए भेजी जा रही थी?

श्री वासुदेव सिंह---

लाइसेंस था, उसमें खांडसारी भेजी जा रही थी और उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित वह चीनी महाबला जो पाकिस्तान के बिल्कुल बार्डर पर है, जा रही थी। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह बिजनैसमैन जो महाबला में चीनी डील करता है उसका नाम क्या है और क्या वह लाइसेंस होल्डर था, वह कितना बड़ा बिजनेसमैन है जो चार सौ बोरी चीनी वहां जा रही थी ?

श्री वासुदेव सिंह---

महावला में जो डीलर है उसका डिटेल मुझे मालूम नहीं है। यह मालूम है कि वह अमृतसर के नजदीक महाबला जा रही थी।

श्री अकबाल हुसैन---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह चीनी महाबला में किस व्यापारी के पास जा रही थी और क्या उसके पास लाइसेंस था ?

श्री अध्यक्ष---

वह बता दिया है।

श्री रियासत हुसैन---

उसके बोनाफाइडी जानने के बाद ही चीनी रिलीज की होगी तो यह तो मालूम होगा।

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, किसके पास जा रही थी वह सूचना नहीं है, हां स्थान हमारे पास है। जब यहां खबर आई तो रेडियोग्राम से जिलाधिकारी से कहा गया कि उसका पता लगायें कि चीनी है या खांडसारी है। तो जिलाधिकारी ने पता लगाया उसकी रिपोर्ट है। उन्होंने पता लगाया कि वह खांडसारी है और खांडसारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि नजीबाबाद से जो चीनी महाबला को जा रही थी वह कोटद्वार कैसे पहुंच गयी। कोटद्वार से तो केवल गढ़वाल को रास्ता है, कोटद्वार से महाबला के लिए कौन सा रास्ता है। तो सिवाय इसके कि वह चीनी चोरी की थी अब विभाग उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस केस की सी0आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे ? कोटद्वार तो उल्टा रास्ता नजीबाबाद से महाबला के लिए होता है ?

श्री वासुदेव सिंह---

यह जो प्रश्न माननीय सदस्य पूछ रहे हैं यह मुझसे तो संबंधित नहीं है। कौन रास्ता है और कहां से भेजता है यह मैं नहीं जानता।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मेरी स्पष्ट जानकारी है कि यह खांडसारी नहीं चीनी थी, बाद में यहां मंत्रिमंडल के किन्हीं मंत्रियों के प्रभाव से चीनी के बदले खांडसारी में परिवर्तित कराया गया। तो मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए इसकी फिर से जांच कराने के आदेश देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को मालूम होता है शासन से ज्यादा जानकारी रहती है। यह अगर जानकारी दे देंगे तो और पता लगायेंगें यदि खांडसारी बना कर इसे रिलीज किया गया तो अवश्य कठोर कदम उठाया जायगा।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ दिनों तक वह चीनी रही, उसके बाद खांडसारी में बदल गई, अगर वह शुरू में चीनी थी तो उसको बदला क्यों गया और वह चीनी कितने दिनों तक रही और खांडसारी कितने दिनों तक रही ? और पकड़ा क्यों गया और निर्दोष लोगों को जिन अधिकारियों ने पकड़ा उनको क्या वह सजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, पहले इतिहास में पढ़ा था कि नमक चीनी कैसे बन जाता है, अब यहां चीनी को खांडसारी बना दिया गया है, तो मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि उस खांडसारी को किसके नाम रिलीज किया गया, उसका नाम क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

वह तो स्टेशन पर पकड़ा, जिसके नाम थी, जो भेज रहा था उसने उसको भेजा। यह चीनी और खांडसारी में जितना फर्क माननीय सदस्य समझ रहे हैं, उतना नहीं होता है, जो प्रथम प्रोसेस है....

श्री मुख्तार अनीस--

आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि उसको किसके नाम रिलीज किया गया ? रिलीज किया गया होगा तो किसी के नाम रिलीज किया गया होगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो माल स्टेशन पर पकड़ा जाता है वह किसी के जरिये भेजा गया होता है और जो भेजी जा रही थी उसे छोड़ दी गई। अब यह कल्पना है कि....

श्री मुख्तार अनीस--

आप सारी बात छिपा रहे हैं, इसमें चन्द्रमोहन सिंह नेगी जी का स्पष्ट हाथ है, आप...

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

यह सब सरासर गलत है, आधारहीन है। इसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पकड़ा और सूचना दी थी.....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

उस चीनी को इधर-उधर करने में लाखों का धंधा कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया है।

*6--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[28-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या-56 द्वारा उत्तरित]।

*7--श्री राम आसरे पासवान--

[5 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

नगरपालिका फैजाबाद द्वारा लालबाग पानी की टंकी तैयार होने पर कतिपय ग्रामों में पेयजल की सुविधा

*8—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग ने नगरपालिका, फैजाबाद द्वारा लालबाग पानी की टंकी तैयार होने पर मुदहा, खोजनपुर, घोसियाना तथा पहाड़पुर में पानी की पूर्ति का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि चूंकि उक्त टंकी तैयारी के करीब है तो उपरोक्त स्थानों में पाइप लाइन बिछवा दी जाय ताकि टंकी चालू होते ही उन स्थानों में पानी की आपूर्ति जारी हो सके ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं।

प्रश्नगत क्षेत्र नगरपालिका के बाहर है।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना इसी शासन का उत्तरदायित्व है, दूसरे शहर जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं—अनेक ग्राम शहरों से मिल गये हैं, इसको देखते हुए क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह उन क्षेत्रों में भी पेय जल की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, जो शहरी पेयजल योजना है उसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था करते हैं और जो ग्रामीण पेयजल योजना है, उसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करते हैं। जो समस्या ग्रस्त गांव हैं, पहले सर्वप्रथम उन्ही में व्यवस्था की जा रही है।

मस्वासी, स्वार एवं रामपुर नगर की समस्याओं से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

*9—श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-6-81 को प्राप्त हुआ, जो मस्वामी, स्वार एवं रामपुर नगर की समस्याओं के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां,

पत्र में इंगित बातों के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन समस्याओं के संबध में मेरा पत्र था और उस पर क्या निर्देश जारी किये गये और उस पर क्या कार्यवाही आज तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

समस्याओं के बारे में तो आपका पत्र था, उसे आप जानते हैं, सिर्फ कार्यवाही के बारे में बता दें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उसमें यह था कि मुख्य-मुख्य मार्गो पर ट्यूब लाईट्स लगाई जाएं जो प्रति दिन जले, उसका आदेश दिया गया है। प्रति दिन सफाई की जाए और समय-समय पर सफाई अभियान चलाया जाए, इसके बारे में भी आदेश दे दिये गये हैं। सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय का निर्माण कराया जाए, यह कार्य अभी तक धन के अभाव में न कराया जा सका है। स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बारे में स्वास्थ्य विभाग को लिख दिया गया है। यही इनकी मुख्य-मुख्य बात हैं।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

निर्देश जारी करने से काम नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें क्या कार्यवाही हुई ? आज तक भी उसमें कुछ नहीं हुआ है, यह क्यों ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

जनपद चिकित्सालय, आजमगढ़ में औषधियों की आपूर्ति

*10--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चिकित्सालय, आजमगढ़ को वर्ष 1980-81 में कितने धनराशि मूल्य की दवाओं की आपूर्ति कराई गयी ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री हरिसिंह--

जनपद चिकित्सालय, आजमगढ़ को वर्ष 80-81 में कुल पांच लाख सतहत्तर हजार सात सौ पचासी रुपये उन्तालीस पैसे (रु0 5,77,785.39 पैसे) की औषधियों की आपूर्ति कराई गई।

श्री दूधनाथ राजभर--

मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री बताने कीकृपा करेंगे कि जो धनराशि आवंटित की गयी थी उसको जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वापस कर दिया था और इस समय वहां चिकित्सालय में दवा की एक भी टिकिया उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मरीज वापस चले जाते हैं और चारों तरफ हा हाकार मचा हुआ है ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर कोई कार्यवाही करायेंगे ?

श्री हरिसिंह--

वास्तव में अगर इस अस्पताल में दवाइयों की कमी है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा और यदि वहां पर दवाइयों की व्यवस्था नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था करा दूंगा।

श्री राज कुमार राय--

वहां पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भी दवा नहीं मिलती, वहां के सी0एम0ओ0 की रिपोर्ट है तो कैसे कहते हैं कि जांच करा लेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

जिला चमोली व गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम साहज कोट (कुनीगाड़) को पेयजल सुविधा की योजना

*11--श्री बनवारी राम (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चमोली गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम साहज कोट (कुनीगाड में) पेयजल की जो योजना सन् 1963-64 में वहां के ग्रामवासियों की सुविधा हेतु बनाई गई थी उस संबंध में अब तक कार्यवाही की गयी ? तथा उक्त योजना के माध्यम से ग्रामवासियों को सुविधा न देकर वहां के ग्राम प्रधान ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं वह सुविधा प्राप्त की ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सूचना को सही मानकर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा वहां के ग्रामवासियों के पेयजल की शीघ्र सुविधा प्रदान करेंगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

ग्राम साहजकोट (कुनीगाड़) में जल निगम अथवा जल संस्थान द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई।

जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में दवाओं की चोरी की दर्ज रिपोर्ट

*12—श्री हुकम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुख्य चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में 17/18 जुलाई, 1981 की रात्रि में 50,000 रुपये से भी अधिक मूल्य की दवाओं की चोरी हुई ? क्या उपरोक्त घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस में कोई केस पंजीकृत कराया गया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री हरि सिंह—

जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में दिनांक 17/18 जुलाई, 1981 की रात्रि में 45,062.68 रुपये (रुपये पैंतालीस हजार बासठ और पैसेअड़सठ) के मूल्य की दवाइयों की चोरी हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट दिनांक 18-7-81 को स्थानीय पुलिस में दर्ज करा दी गई थी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस घटना की कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है। जिन दिनों में चोरी हुई थी उन दिनों में कितना स्टोर कम था और कौन जिम्मेदार व्यक्ति हैं ? वास्तव में वहां पर चोरी नहीं हुई थी बल्कि आपके अस्पताल में जो शार्टेज थी उस बात को छुपाने के लिए फर्जी रिपोर्ट लिखायी गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

माननीय सदस्य का सुझाव मैं मान लेता हूं। मैं इस सारे मामले की सी0आई0डी0 द्वारा जांच करवा लूंगा।

परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एम0 एन0 सक्सेना के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*13—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक, श्री एम0 एन0 सक्सेना के विरुद्ध किसी विधायक का आरोप-पत्र 17 दिसम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आरोप क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरि सिंह—

जी हां, डा0एम0एन0सक्सेना के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 17-12-1981 को प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित पांच शिकायतें बताई गई हैं।

(1) डा0 सक्सेना का एक्स-कैडर प्रमोशन।

(2) अपने विषय में दिलचस्पी नहीं लेना तथा विदेश जाने के अवसर निकालना।

(3) शासनादेशों की अवहेलना करते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृति स्वयं करना।

(4) सरकारी टेलीफोन अपने घर पर लगवाना।

(5) 21 वर्ष से लखनऊ में ही नियुक्त रहना।

उपरोक्त आरोपों की विभागीय जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच उन्होंने किस अधिकारी द्वारा करायी और कब उनको जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ?

श्री हरिसिंह--

मान्यवर, यह पत्र शासन को 17-12-81 को प्राप्त हुआ था और शिकायतों की जांच अतिरिक्त निदेशक डाक्टर वाई0के0 जैन द्वारा करायी गयी। जांच रिपोर्ट शासन को 4 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी थी।

श्री रियासत हुसैन--

यह संयुक्त निदेशक जो 21 साल से यहां पर हैं, इनकी सेवा शुरू से किस कैडर से शुरू हुई जो 21 साल में ही तरक्की करके संयुक्त सचिव के पद पर पहुंच गये ?

श्री हरि सिंह--

यह 1967-76 तक राज्य कल्याण ब्यूरो में रहे। 1976 से संयुक्त निदेशक का कार्य कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

इस बात की जांच क्या माननीय मंत्री जी करवायेंगे कि मिस्टर सक्सना को आऊट आफ दि वे जाकर ऐसे पदों पर ही सदा रखा जाता रहा जिससे कि वे हैडक्वार्टर लखनऊ में ही बने रहे ?

श्री हरि सिंह--

इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है।

विकास क्षेत्र डोमी बहरी संघ के परिवेक्षक (श्री दया शंकर दुबे) का स्थानान्तरण

*14--श्री जंगबहादुर--

क्या सहकारिता मन्त्री को यह ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र डोमी बहरी संघ के परिवेक्षक (श्री दयाशंकर दुबे) का स्थानान्तरण तीन मास पूर्व कर दिया गया और वह अब तक कार्य मुक्त नहीं किए गये तथा उनके स्थान पर नियुक्त परिवेक्षक को अब तक चार्ज न दिला कर दोनों व्यक्तियों को वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पद-मुक्त न किए जाने तथा दूसरे को चार्ज न दिलाए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

श्री दयाशंकर दुबे का स्थानान्तरण दिनांक 22-8-81 के आदेश द्वारा विकास खंड बदलापुर में किया गया और उनके स्थान पर श्री विजय शंकर मिश्र की नियुक्ति की गई जिन्होंने 28-8-81 को विकास खण्ड डोमी में योगदान किया। परन्तु उन्हें चार्ज न मिल सकने के कारण श्री मिश्र को 23-11-81 को डोमी से सहायक निबंधक के कार्यालय, जौनपुर में वापिस कर दिया गया। बाद में उनकी तैनाती विकास क्षेत्र सिकरारा में कर दी गयी। 18-12-81 को श्री दयाशंकर दुबे को कार्यमुक्त कर दिया गया है। दोनों व्यक्तियों को वेतन नियमानुसार दिया जा रहा है।

सहायक विकास अधिकारी, (सह0) डोमी को आदेशों का पालन सुनिश्चित न करने के लिये कठोर चेतावनी दे दी गयी है।

श्री जंगबहादुर--

मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री दयाशंकर दुबे का ट्रांसफर जब कर दिया गया तो किन कारणों से 4 महीने तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया और किस आधार पर तथा किस स्थान पर उनका ट्रांसफर किया गया था ?

श्री बच्चा पाठक--

इनका ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर किया गया था, जितने दिनों जिसके कारण चार्ज देने में देरी हुई उसके लिये उस अधिकारी को सजा दी गयी ।

*15--श्री हरिवंश सहाय--

[7 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीदने हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्र

*16--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में धान खरीदने हेतु वर्ष 1981-82 में कहां-कहां क्रय केन्द्र खोले गये हैं ? क्या यह सही है कि इन क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान न खरीद कर बनियों से धान खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद देवरिया में वर्तमान खरीफ वर्ष 1981-82 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीदने हेतु उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 द्वारा 25 तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा तीन धान-क्रय-केन्द्र स्थापित किए गये हैं, जिनके नामों की सूची संलग्न है ।

जी नहीं । शासन के निर्देशों के अनुरूप धान की सीधे किसानों से ही खरीद की जा रही है । बनियों से धान की खरीद की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिस पर जांच कराने की आवश्यकता हो ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 524 पर ।)

आवास स्थल निर्माण हेतु नगरपालिका तिलहर में इच्छुक सेवारत सैनिकों को पट्टे पर दी गयी भूमि

*17--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि शासन ने शासनादेश संख्या 120 एन/9-ए-50एन/82 स्वायत्त शासन (क) विभाग, लखनऊ, दिनांक 8 अप्रैल, 1963 एवं शासनादेश संख्या एल0एस0जी0ए0विभाग एम0एम0नं0128 ए0एन0 9ए-58-ए0एन0-1962, दिनांक 8 अप्रैल, 1965 तथा शासनादेश संख्या एम0एन0 406/9 नजूल 511 नं0 78, दिनांक 8 जनवरी, 1981 के आधार पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे आवास स्थल निर्माण हेतु नगरपालिका अथवा नजूल की भूमि प्राथमिकता आधार पर इच्छुक सेवारत सैनिकों को पट्टे पर प्रदान करें ? यदि हां, तो इस संबंध में 30-11-81 तक नगरपालिका तिलहर (शाहजहांपुर) में किन-किन सैनिकों के कितने-कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? उनमें से किन-किन सेवारत सैनिकों को कितनी-कितनी भूमि पट्टों पर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

जी हां, ये शासनादेश जारी किये गये थे। दिनांक 30-11-1981 तक नगर-पालिका तिलहर में भूमि आवंटन हेतु केवल एक प्रार्थना-पत्र श्री अरविन्द कुमार का प्राप्त हुआ परन्तु उन्हें भूमि पट्टे पर नहीं दी गयी क्योंकि आवेदित भूमि पट्ट पर देने के लिये उपलब्ध नहीं थी।

राम सागर मिश्र नगर का नाम 'इन्दिरा नगर' करने का औचित्य

*18--श्री मोहन सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राम सागर मिश्र नगर कालोनी, लखनऊ का नाम पुनः बदलकर इन्दिरा नगर कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जन-भावना का समादर करते हुए "राम सागर मिश्र नगर" का नाम "इन्दिरा नगर", किया गया जो पूर्व में था।

श्री मोहन सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जन-भावना का वैरोमीटर इनके पास क्या है ? क्या स्थानीय नेता ने कोई प्रदर्शन किया, इनको ज्ञापन दिया ? बर-खिलाफ इसके मेरी जानकारी के अनुसार वहां की जनता उसके लिये संघर्षरत है कि उसका नाम राम सागर मिश्र नगर ही रखा जाय। क्या वहां की जनता ने या निवासियों ने कोई ज्ञापन दिया कि उसका नाम राम सागर मिश्र नगर रखा जाय और उसका नाम राम सागर मिश्र नगर क्या माननीय मंत्री जी रखेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, इसका नाम शुरू में जब श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा यहां पर मुख्य मंत्री थे, तब इंदिरा नगर रखा। जब जनता शासन आया, तो उसने बदलकर उसका नाम रामसागर मिश्र नगर रख दिया। तो मान्यवर, जो इसमें किया गया है, वह जन-भावना का सम्मान रखते हुए ऐसा किया गया है।

विकास खण्ड मिहीपुरवा, जनपद बहराइच में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

*19--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मिहीपुरवा, जनपद बहराइच का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लाक हेडक्वार्टर मिहीपुरवा में अब तक नहीं बनाया गया है और इस पी0एच0सी0 निर्माण हेतु क्षेत्र समिति चकबन्दी एवं गांव सभा द्वारा कई वर्षों पूर्व प्रदत्त सम्पूर्ण भूमि पर अभी तक विभाग ने अपना कब्जा नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जी हां। क्षेत्र समिति चकबन्दी एवं ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त भूमि पर विभाग द्वारा कब्जा ले लिया गया है।

*20--श्री राम आसरे वर्मा--

[12-2-82 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद अल्मोड़ा में नये विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

**1--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा में पांच नये विकास खंड खोलने के प्रस्ताव जिलाधिकारी, अल्मोड़ा से शासन को 1981 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष क्षेत्र समितियों के चुनाव से पूर्व उक्त विकास खंडों को खोलने का निर्णय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां। छः नये विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रसंगगत मामला शासन के विचाराधीन है।

नये विकास खण्ड खोलने के प्रस्ताव पर पूर्ण परीक्षण के पश्चात ही निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले तो जैसा प्रस्ताव विकास खंडों के जो आये हुए हैं, उनका क्या नाम है ? दूसरा प्रश्न है कि जो प्रश्नगत मामला है, वह कब से शासन के विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो 6 ब्लाक्स प्रस्तावित किये गये हैं, उसके नाम इस प्रकार हैं:--

(1) लोहार खेत,
(2) विजयपुर,
(3) जैती,
(4) मछोड़,
(5) जालली,
(6) मझ खाली।

और यह मामला शासन के विचाराधीन 28 दिसम्बर, 1981 से है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी इस मामले में परीक्षण करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जिलाधिकारी से जो प्रस्ताव आया था, वह प्रस्ताव पूर्ण नहीं था इसलिए दूसरा प्रस्ताव जो है उनसे मांगा गया है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे थे, उसके बाद ब्लाकों के चुनावों की घोषणा आपने कर दिया है। क्या उसके पहले इन विन्दुओं पर विचार करके निर्णय ले लिया जायगा ताकि उनका समावेश हो जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह प्रश्न विचारणीय है कि विकास खंड, नये बनाये जा सकते हैं या नहीं, यह विचाराधीन है और अगर बनाये जा सकते हैं, तो सरकार जो है, उस पर निर्णय शीघ्र ले लेगी।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि शासन ने दुबारा क्लीयरीफिकेशन मांगा है जिलाधिकारी से, तो इस बात को ध्यान में रख कर मांगा है कि आने वाले जो प्रमुखों के चुनाव होंगे बरसात बाद, उस वक्त तक अलग ब्लाकों की स्थापना करके चुनाव करा देंगे? जैसा आपने यह कहा कि इसको दुबारा जिलाधिकारी से, कुछ कमियां रह गयी थीं, क्लीयरीफिकेशन्स मांगे थे, क्या शासन के पास यह बात विचाराधीन है, वह बात जुड़ी हुई है कि आने वाले जो प्रमुखों के चुनाव होंगे, जो बरसात के बाद होंगे, उस वक्त तक इसको क्लीयर करके अलग स्थापना कर देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

उस समय तक निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नई जन गणना जो हुई है इसको आधार मानकर क्षेत्र समितियों के क्षेत्र का पुनः परिसीमन करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

नया प्रश्न है।

श्री अकबाल हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नये विकास खंड खोलने की नीति है शासन को उसमें बताया की कुछ त्रुटियां रह गई हैं। क्या कोई प्रोफार्मा है जिसके आधार पर सूचना मांगी जाती है?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है उसमें कुछ बातें स्पष्ट करके भेजना चाहिये। जो प्रस्तावित मामला है उसमें विकास खंड की जन संख्या और क्षेत्रफल की सूचना नहीं है जिनसे नये विकास खंड बनाने हैं। पूर्ण निरीक्षण मानचित्र नहीं प्राप्त हुआ है, मण्डल आयुक्त की संस्तुति आवश्यक है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह सूचनायें आवश्यक हैं इसलिये इनको प्राप्त किया जा रहा है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नये विकास खण्ड खोलने के संबंध में जिलाधिकारी को शासन के निर्देश दिये गये हैं क्या उसमें यह है कि वहां के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से राय ले लें, क्या जन प्रतिनिधियों को पूछा गया?

श्री बलराम सिंह यादव--

जन प्रतिनिधियों से पूछने का कोई नियम नहीं है न परम्परा है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र में नये विकास खण्ड बनाने हैं उसमें वहां भी भौगोलिक परिस्थिति का आधार रखा जायगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह बात सही है पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास खण्ड बनाने का मानक है वह मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है। पर्वतीय क्षेत्रों में कम जन-संख्या पर बनाया जाता है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरी जानकारी जहां तक है जब जिलाधिकारी, अल्मोड़ा से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था उसमें आदेश दिया गया कि न्याय पंचायतों को आधार मानकर नये विकास खंड का पुनर्गठन किया जाय। उसी आधार पर अल्मोड़ा के स्थानीय जन प्रतिनिधियों और भूतपूर्व प्रमुखों को बुलाया गया और न्याय पंचायतों के आधार पर वह प्रस्ताव बनाया गया। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि न्याय पंचायतें दूर-दूर तक फैली हुई हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ग्राम सभाओं को आधार मान लें तो नये विकास खंड बनाने से जनता को अधिक लाभ रहेगा। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इन विकास खंडों को बनाने का प्रस्ताव बहुत पहले से चल रहा है इसी के साथ के नैनीताल और पिथौरागढ़ मे नये विकास खंड खुल गये हैं लेकिन अल्मोड़ा में नहीं खुला और जैसा रियासत हुसैन साहब ने सुझाव दिया ब्लाक प्रमुखों के चुनाव के पूर्व गठन करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस पर जो उचित निर्णय होगा, शासन ब्लाक प्रमुखों के चुनाव से पूर्व ले लेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास खण्ड 100-100 किलोमीटर पर स्थित है। मैं जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छोटे-छोटे विकास खण्ड बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो प्रस्ताव आये हैं उन पर शासन विचार कर रहा है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिया था कि क्या पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ग्राम सभाओं को आधार मानकर वहां विकास खंडों का पुनर्गठन करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, न्याय पंचायतों का आधार तो रहता ही है। लेकिन आपके सुझाव पर भी विचार कर लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी के ग्राम पटरंगा मण्डी में स्थित खाद्य गोदाम के निर्माण के फाइनल बिल का भुगतान

1--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पटरंगा मण्डी में स्थित खाद्य गोदाम का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 1979 में टेंडर देकर करवाया गया ? यदि हां तो वेरीफिकेशन के बाद भी उसका फाइनल पेमेन्ट अब तक न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां।

नोट:--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार द्वारा ग्रामीण गोदाम कार्य 26-11-1979 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु ठेकेदार द्वारा इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण में गोदाम के निर्माण में कतिपय कमियां पाई गयीं जैसे प्लास्टर खराब था, छत की लाईन टैरेसिंग खराब होना, लकड़ी के दरवाजे एवं खिड़कियां निर्धारित मानकों के अनुसार न होना आदि। इन्हें ठीक कराने के लिये ठेकेदार से अनुरोध किया गया था, परन्तु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में पायी गयी त्रुटियों को ठीक न कराने के कारण फाईनल बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

नगर महापालिका, लखनऊ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

2--श्री मोहन सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ में तीन वर्षों से अधिक या तीन वर्षों से निरन्तर कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? उन्हें अभी तक क्यों नियमित नहीं किया गया? उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगर महापालिका लखनऊ में ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 245 हैं। इनको नियमित किये जाने के संबंध में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

पटवाडांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट, नैनीताल में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री हरीश सिंह के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति रिकवरी के आदेश

3--श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि विभाग के पटवाडांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट, नैनीताल में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री हरीश सिंह के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग आदि के कारण सन् 80 के अन्तिम तथा सन् 81 के प्राथमिक महीनों में शासन अथवा निदेशालय से कुछ रुपयों की रिकवरी आदेश हुए थे तथा कुल कितने हजार की रिकवरी होनी थी और कितनी हो चुकी है? यदि नहीं हुई है, तो क्यों?

श्री लोकपति--

जी हां, प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा मार्च, 1981 में रुपये 6000 की रिकवरी के आदेश दिये गये थे किन्तु राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर के सम्बन्धित अधिकारी को यह आदेश प्राप्त न होने के कारण यह रिकबरी अब तक नहीं की जा सकी। रिकवरी आदेश की एक प्रति अब विशेष पत्रवाहक द्वारा भेज दी गई है।

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा बेची गई नजूल की भूमि

4--श्री छत्तर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ नजूल की जमीनें बेच रही है? यदि हां, तो किस दर पर? यदि नहीं, तो प्लाट नं0 256 ग्राम जियामऊ नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत का विक्रय श्री फ्रांसिस एप के पक्ष में क्यों किया गया है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा नजूल की जमीन नहीं बेची जा रही हैं। भूखण्ड संख्या-256, ग्राम जियामऊ नजूल भूमि नहीं है और न ही इसका विक्रय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

बांदा नगरपालिका, मल्लाखाईपार में नजूल की भूमि पर नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

5—श्री छत्तर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की बांदा नगरपालिका, मल्लाखाईपार में नजूल (नगरपालिका) की कई एकड़ भूमि पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा जबरन नाजायज कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मुजफ्फरनगर की कैराना व शामली नगरपालिकाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जांच

6—श्री हुकम सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की कैराना व शामली नगरपालिकाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 20–5–81 का पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ जिसके आधार पर पत्रांक नं0 1043, दिनांक 25–5–81 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया ? पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच जिस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

हां।

शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के माध्यम से से कराई गयी। जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

वरिष्ठ अधीक्षक, जिला अस्पताल, गोरखपुर द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत माह वरिष्ठ अधीक्षक, जिला अस्पताल, गोरखपुर ने एक ही बिल का दुबारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोतवाली, गोरखपुर में कोई मुकदमा दर्ज कराया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में राइस मिलों द्वारा धान की सप्लाई

8—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में निगोही क्षेत्र में 3 राइस मिल्स हैं परन्तु निगोही के धान विक्रय केन्द्रों द्वारा केवल 2 राइस मिल्स को ही धान सप्लाई होता है? यदि हां, तो तीसरे को सप्लाई न करने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में निगोही क्षेत्र में स्थापित निम्नलिखित तीनों राइस मिलों को उनके नाम के सामने अंकित मात्रा में वर्तमान खरीफ वर्ष 1981–82 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीदे गये धान को कस्टम मिलिंग हेतु दिया गया है:—

1—जिलानी राइस मिल, निगोही	..	10,064 कु0
2—चौहान राइस मिल, निगोही	..	4,970 कु0
3—निगोही इण्डस्ट्रीज निगोही	..	16,634 कु0

नगरपालिका, सीतापुर में जनरेटर सेट की व्यवस्था कराने के संबंध में विचार

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर में जलकल विभाग के लिए जनरेटर सेट की व्यवस्था कराने में बिलम्ब के बारे में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 24–11–81 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जा हां,

जनरेटर सेट की व्यवस्था कराने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को विभिन्न आवास योजनाओं में आरक्षण

10—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि महानगरों, नगरों और टाऊन एरिया के अन्तर्गत रहने वाले हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सीलिंग व नजूल की भूमि आवंटित करके उनके आवास की व्यवस्था हेतु अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नहीं । विभिन्न आवास योजनाओं में उनके लिये आरक्षण कर दिया गया है ।

कोआपरेटिव बैंक की देवरिया में शाखायें तथा कार्यरत कर्मचारी

11—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोआपरेटिव बैंक, देवरिया में बैंक की कितनी शाखायें हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

कि देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया उ0 प्र0 की कुल 31 शाखायें हैं । इन शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय में कुल मिलाकर 229 कर्मचारी कार्यरत है ।

रिफ्रेक्सनिष्ट व फिजियोथेरेपिष्ट के वेतनमानों में अन्तर की असमानता को दूर करने की मांग

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 7वें गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय क्या है ? यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जो हां । रिफ्रेक्सनिस्ट के पद पर फिजियोथिरेपिस्ट के पद के समान वेतनमान स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के कार्यकाल में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत

13—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया द्वारा 1–1–81 से 31–12–81 के बीच कितनी नियुक्तियां तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी में की गई ? उनमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ? इस समय इस विभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं उनमें हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के कितना प्रतिशत है ?

श्री लोकपति—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 525 पर)

सहारनपुर शहर की नगरपालिका द्वारा समस्त चावल मिलों की असेसमेन्ट से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

14—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर शहर की नगरपालिका द्वारा समस्त चावल मिलों को 158 का नोटिस न भेजकर सीधा असेस्मेन्ट कर शासन के नियमों क विरुद्ध कार्य किया गया है जिससे पालिका को लगभग 20 लाख की क्षति हुई है? क्या सरकार इसका कारण बतायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जो नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहारनपुर में नगरपालिका द्वारा विशाल चन्द्र जैन कोल्ड स्टोरेज का असेसमेन्ट

15—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि वर्ष 1981 में जिला सहारनपुर के सहारनपुर शहर में नगरपालिका द्वारा विशाल चन्द्र जैन एक कोल्ड स्टोरेज का असेसमेन्ट 40 हजार रुपये के बजाय घटा कर 11 हजार रुपया कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सहारनपुर नगर में विशाल चन्द्र जैन का कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है । जिसका एसेसमेन्ट किया हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, मऊनाथ भंजन में लेखाकार (अनर्ह) पद पर कर्मचारी का स्थायीकरण

16—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नगरपालिका मऊनाथ भजन में एक अनर्ह व्यक्ति को लेखाकार के पद पर स्थायी कर दिया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अध्यापकों के प्राविडेन्ट फंड के 4 हजार रुपये के गबन का मामला अभी भी अनिस्तारित है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को लेखाकार के पद पर स्थायी किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। उन्हें लेखाकार (अनर्ह) पद के लिये अनुमन्य वेतनमान में स्थायी किया गया। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम दरश सिंह, पूर्ति निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध सीमेन्ट वितरण में अनियमितताओं की जांच

17--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दरश सिंह, पूर्ति निरीक्षक जिला पूर्ति कार्यालय, देवरिया को अप्रैल, 1981 में निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या आरोप थे? क्या आरोपों की कोई जांच करवाई गई तथा जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। श्री राम दरश सिंह के विरुद्ध सीमेंट वितरण में अनियमितताओं से संबंधित आरोप थे। प्रश्न गत आरोपों की जांच परगनाधिकारी, देवरिया द्वारा कराई गई जिसमें आरोप सिद्ध पाये गये।

नगरपालिका, बस्ती के गांधी नगर में नलकूपों की बोरिंग

18--कु0 अलमेलू अम्माल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बस्ती के गांधी नगर (पक्का बाजार) में कितने नलकूप बोर हो चुके हैं कितने बोर होने हैं तथा पुरानी बस्ती में नलकूप जलकल विभाग, गोरखपुर, (रिग्स प्रखण्ड) द्वारा कब तक बोर करा दिये जायेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका, बस्ती के गांधी नगर (पक्का बाजार) में चार नलकूप बोर हो चुके हैं, अब कोई अन्य नलकूप बोर नहीं होना है। पुराने बस्ती में एक नलकूप बोर कर दिया गया है।

19--श्री मोतलाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के अन्तर्गत चल रहे क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र में ओवरहेड टैंक का निर्माण

20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के अन्तर्गत चल रहे क्षेत्रीय नगर एवं पर्यायवरण अध्ययन केन्द्र को शासन द्वारा वर्ष 1972 में 23000 रुपये की धनराशि "ओवर हड" टैंक बनाने के लिये तत्कालीन लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की संस्तुति पर दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त डिपार्टमेन्ट ने इस सम्बन्ध में इस्टीमेट दिया था? यदि हां, तो क्या उस अनुमान के आधार पर ही उक्त टैंक बनाने सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह टैंक क्या वास्तव में बना है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। टैंक का निर्माण हो चुका है परन्तु न्यायालय में एक वाद के सिलसिले में भी टैंक के निर्माण का विषय संदर्भित है अतः इस सम्बन्ध में विस्तुत सूचना देना अभी सम्भव नहीं है।

श्री अवध नारायण सिंह, सेवा निवृत्त फार्मेसिस्ट के पेंशन तथा ग्रेच्युटी संबंधी समस्त अभिलेखों की स्वीकृति तथा धनराशि का अविलम्ब भुगतान

21--श्रीमती गौरी देवी--

वर्ष के 1981 के प्रथम सत्र के 1 ले गुरवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री अवध नारायन सिंह, पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह (सेवा निवृत फार्मेसिस्ट), मुहल्ला छोटे काजीपुर, जनपद गोरखपुर को सेवा समाप्ति के बाद उनको मिलने वाली सभी प्रकार की धनराशि ग्रुप इन्श्योरेंस, ग्रेच्युटी तथा पेंशन आदि का भुगतान इस कारण नहीं किया गया कि श्री सिंह को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भटहट द्वारा अभिलेख पूर्ण कराने हेतु बुलाये जाने पर श्री सिंह उपस्थित नहीं हुए ? यदि हां, तो दिनांक 20-5-81 को श्री अवध नारायण सिंह द्वारा पेंशन व ग्रेच्युटी से सम्बन्धित सभी अभिलेख पूर्ण करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटहट, गोरखपुर में जमा करने के बाद उनको मिलने वाली सभी धनराशि में अब विलम्ब का कारण क्या है और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

जी हां। श्री अवध नारायणसिंह के पेन्शन तथा ग्रेच्युटी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेज दिये गये हैं तथा सामूहिक बीमा से सम्बन्धित अभिलेख निदेशक, राज्य कर्मचारी सामुहिक बीमा, लखनऊ को स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं। उक्त सभी धनराशियों का भुगतान अपेक्षित स्वीकृतियों के प्राप्त होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

22--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री अवध नारायण सिंह, पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह (सेवा निवृत्त फारमेसिस्ट), मुहल्ला छोटे काजीपुर, जनपद गोरखपुर ने दिनांक 21-11-81 को एस0पी0एम0, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को अपने सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाली सभी प्रकार की धनराशि के भुगतान के संबंध में विलम्ब होने का शिकायती-पत्र दिया है? क्या यह सच है कि दिनांक 1-5-81 को एस पी0 एम0 पत्र संख्या 663, दिनांक 4-5-81को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ने भटहट, गोरखपुर को यह आदेश दिया कि श्री अवध नारायण सिंह के अवशेष वेतन का बिल बना कर वेतन सगइना के बाद उनके निर्धारित प्रपत्र में पेंशन के कागजात शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर अधोहस्ताक्षरी (एस0पी0एम0) के पास प्रस्तुत करें ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हां। जी हां। श्री अवध नारायण सिंह, सेवा निवृत्त फार्मेसिस्ट का वेतन निर्धारण कर दिया गया है। चूंकि श्री सिंह जनपद गोरखपुर विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात रहे हैं अतः संबंधित स्थानों से पूर्ण विवरण प्राप्त कर बिल बनाने की कार्यवाही करके पूर्व सम्प्रेक्षा हेतु महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में गृह जनपदों में नियुक्त सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता तथा उनका स्थानान्तरण

23--श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता अपने गृह जनपदों में नियुक्त हैं ? क्या उनको जनपदों से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

उत्तर प्रदेश जल निगम में 98 सहायक अभियन्ता एवं 10 अधिशासी अभियन्ता अपने गृह जनपदों में नियुक्त हैं। इन्हें सामान्य स्थानान्तरणों के समय अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

जल निगम में कार्य प्रभार अधिष्ठान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को मासिक वेतन तथा अन्य भत्तों के संबंध में निर्णय

24---श्री नन्द किशोर तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में उ0 प्र0 जल निगम में कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का मासिक वेतन, दैनिक भत्ता व अन्य भत्तों के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने का आधार क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

जी हां। यह निर्णय जल निगम द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर लिया गया है। दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं पारित किये गये हैं।

रिंग मशीनों के जे0 डी0 एच0, ए0 डी0 के वेतनमानों में संशोधन

25---श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह---

उपरोक्त सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि रिंग मशीनों के जे0 डी0 एच0, ए0 डी0 का वेतन कम्प्रेशर ड्राइवरों व ट्रक व ट्रैक्टर ड्राइवर से कम रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनके वेतनों में शासन द्वारा कोई संशोधन किए जाने का प्रश्न शासन के विचराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

जल निगम द्वारा सृजित पदों में रिंग मशीनों के जे0 डी0 एच0, ए0 डी0 पदनाम से कोई पद नहीं है।

अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में वरिष्ठ पम्प आपरेटरों का वेतन

26---श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में वरिष्ठ पम्प आपरेटरों को नये अधिशासी अभियन्ता द्वारा पम्प अटेंडेंट बनाकर कम वेतन दिया जा रहा है व नये भर्ती व्यक्तियों को अधिक वेतन दिया जा रहा है जो कि कम शिक्षित है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

किसी भी वरिष्ठ पम्प आपरेटर को पम्प अटेन्डेन्ट बनाकर कम वेतन नहीं दिया जा रहा है और नहीं नये भर्ती कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में विभिन्न पदों पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों का कार्यकाल तथा वरिष्ठता सूची

27---श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में विभिन्न विद्युत यांत्रिक शाखाओं में कार्य प्रभारी अधिष्ठान में कुल कितने पम्प आपरेटर, पम्प अटेन्डेन्ट, जे0डी0एच0 व ए0 डी0 रिंग मशीन, ट्रैक्टर व ट्रक ड्राइवर, जीप ड्राइवर तीन साल से अधिक

समय से कार्यरत हैं व उनकी वरीष्ठता सूची क्या है तथा क्या यह भी बतायेंगे कि गत दो तीन वर्षों में उपरोक्त कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों को रेगुलर करने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो निर्णय क्या था वह कुल कितने कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारी रेगुलर किये गये और नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को रेगुलर न करके कनिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची का उल्लंघन करके रेगुलर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व वरिष्ठ कर्मचारियों को कब तक रेगुलर कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की अभी वरिष्ठता सूची बनायी जा रही है । सूची बन जाने के पश्चात् ही वास्तविक रुप से यह बताना सम्भव हो सकेगा कि प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने कार्य प्रभारित कर्मचारी तीन साल से अधिक समय से कार्यरत हैं । जल निगम द्वारा विभिन्न श्रेणी के 822 पद का कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नियमित किये गयें हैं इन पदों पर अभी किसी को नियमित नहीं किया गया है । वरिष्ठता सूची बन जाने के बाद ही इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जायगा ।

नगर क्षेत्र बांदा में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय

28--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बांदा के नगर क्षेत्र बांदा में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् ने आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय अभी हाल में लिया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

हां । भूमि अधिग्रहण के लिये प्रथम विज्ञप्ति का प्रकाशन 20-11-81 को किया गया है । भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

गाजीपुर नगरपालिका द्वारा राजकीय कन्या इण्टर कालेज की चार दीवारी के पास दुकानों का गलत निर्माण पर कृत कार्यवाही

29--श्री राम नारायण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका द्वारा राजकीय कन्या इन्टर कालेज के चार दीवारी एवं मुख्य द्वार से सटे दुकानें बनाई जा रही हैं और उक्त गलत निर्माण को सदैव के लिये रोकने के लिए उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संरक्षक समिति ने जिलाधिकारी, गाजीपुर को दिनांक 30-6-81 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? क्या सरकार उक्त विद्यालय के शुद्ध वातावरण को बनाये रखने के लिए इस गलत निर्माण को तत्काल रोकने के लिए कौन सा कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, गाजीपुर की चारदीवारी के पश्चिम की तरफ दुकानें बनवाई जा रही थी परन्तु कालेज के प्रधानाचार्य आदि की आपत्ति पर जिलाधिकारी/प्रशासक, नगरपालिका ने निर्माण कार्य रोक दिया । इसी बीच मुन्सिफ, गाजीपुर की अदालत में श्री अनवर आलम आदि बनाम आलोक दुबे आदि नामक बाद संख्या 210/81 दायर हुआ और अदालत से अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर दिये जाने के फलस्वरूप भी निर्माण कार्य बन्द है । कालेज के मुख्य द्वार के पास दुकानें बनाने की कोई योजना नहीं थी ।

गोरखपुर नगर क्षेत्र में मन्दिरों व मस्जिदों के निर्माण हेतु सीमेन्ट का वितरण

30—श्रीमती गौरी देवी—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोरखपुर नगर और बांसगांव तहसील में मस्जिदों व मन्दिरों के निर्माण के लिए जनवरी, 81 से 30 सितम्बर, 81 तक कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया ? किन-किन अभ्यर्थियों को सीमेन्ट उपलब्ध कराई गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

गोरखपुर जनपद के गोरखपुर नगर क्षेत्र में जनवरी, 81 से 30 सितम्बर, 81 तक मन्दिरों व मस्जिदों के लिये कुल 187 अभ्यर्थियों ने सीमेन्ट हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे जिसमें से कुल 95 अभ्यर्थियों को सीमेन्ट की परमिट दी गयी ।

तहसील बांस गांव में कुल 131 अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें से 49 अभ्यर्थियों को सीमेन्ट की परमिट दी गयी । जिन-जिन लोगों को सीमेन्ट के परमिट दिये गये, उनके नाम की सूची की एक प्रतिलिपि खाद्य मन्त्री के कक्ष में उपलब्ध है, जहां देखी जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मथुरा में अल्प आय वर्ग हेतु आवास निर्माण की योजना का क्रियान्वयन

31—श्री कन्हैयालाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत मथुरा में अल्प आय वर्ग हेतु जो योजना सन् 1979 में आरम्भ की गई थी और जिसमें लगभग 1300 अल्प आय वाले गरीब लोगों का धन जमा है उसकी क्या प्रगति है ? इस योजना के अन्तर्गत सदस्यों को कब तक आवास देने का सरकार का इरादा है ? अब तक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत योजना में प्रस्तावित भूमि के कुल क्षेत्रफल 64 एकड़ में से दिनांक 19—8—79 तक 28.25 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया है तथा परिषद् ने उक्त भूमि पर 920 भवनों के निर्माण की योजना भी स्वीकृत कर दी है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

डा0 एस0 सी0 सक्सेना, डी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध जांच

32—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979 में सिटी मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ ने एक शिकायत के आधार पर डा0 एस0 सी0 सक्सेना डी0 एम0ओ0 के विरुद्ध जांच की थी ? यदि हां, तो शिकायत में क्या आरोप थे और जांच के परिणाम स्वरूप क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां । श्रीमती बीना ने डा0 एस0सी0 सक्सेना के विरुद्ध एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था । जांच के परिणाम स्वरूप आरोप सत्य पाया गया । इस पर डा0 सक्सेना का स्पष्टीकरण मांगा गया था जिस पर उन्होंने सूचित किया है कि श्रीमती बीना ने सप्तम अतिरिक्त मुन्सिफ कानपुर के न्यायालय में वाद दायर कर रक्खा है, जो लम्बित है ।

जनपद रामपुर के स्वार नगर तहसील चिकित्सालय के भवन का नवीनीकरण

33—श्री बलवीर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद रामपुर के स्वार नगर तहसील चिकित्सालय के भवन का नवीनीकरण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषदों में कार्यरत समस्त डाक्टरों, कम्पाउन्डरों तथा सेनेट्री इन्स्पेक्टरों का प्रान्तीयकरण

34—श्री राम आसरे पासवान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों में कार्यरत समस्त डाक्टरों, कम्पाउन्डरों तथा सेनेट्री इन्सपेक्टरों का प्रान्तीय करण प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हो गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जिला परिषद् के स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेटर तथा ए0एन0 बी0 (सहायक टीका अधीक्षक) का प्रान्तीयकरण स्वास्थ्य विभाग में नहीं किया जा रहा है ?

श्री लोकपति—

जिला परिषदों में कार्यरत समस्त डाक्टरों कम्पाउन्डरों का प्रान्तीयकरण नहीं किया गया है। केवल सेनेट्री इंस्पेक्टरों का प्रान्तीयकरण किया गया है। जिला परिषद् जिन अस्पतालों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव पास करती है उन अस्पतालों को निर्धारित शर्तों के अधीन प्रान्तीय कृत किया जाता है और उनके स्टाफ को, निर्धारित मानक के अनुसार, सरकारी सेवा में ले लिया जाता है ।जिला परिषद् के स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेटर तथा ए0एन0बी0 (सहायक टीका अधीक्षक) का प्रान्तीयकरण किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों का प्रमोशन तथा शर्तें

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81में कितने परिवार कल्याण से स्वास्थ्य सहायकों का कब-कब स्केल प्रमोशन किया गया? क्या यह वरिष्ठता सूची के आधार पर किया गया ? यदि हां, तो वरिष्ठ सहायकों को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री लोकपति—

उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 में 98 वें परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को निम्न विवरणानुसार निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया गया:—

माह पदोन्नति		पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या
अप्रैल, 1980	..	8
मई, 1980	..	12
जून, 1980	..	10
जुलाई, 1980	..	4
अगस्त, 1980	..	12
सितम्बर, 1980		1
अक्टूबर, 1980	..	16
नवम्बर 1980	..	2
दिसम्बर, 1980	..	..
जनवरी, 1981	..	5
फरवरी, 1981	..	..
मार्च, 1981	..	..
अन्य	..	28
कुल	..	98

उक्त पदोन्नतियां निम्नांकित शर्तों के आधार पर की गयी:--

1--7 वर्ष का, प्रसार कार्य का अनुभव, (किसी भी राजकीय विभाग में) ग्रामीण क्षेत्र में रह कर प्राप्त किया हो तथा उक्त अवधि में सेवा का रिकार्ड अच्छा रहा हो अथवा कर्मचारियों ने परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुए उपरोक्त अवधि में प्रशंसनीय कार्य किया हो।

2--कम से कम एक वर्ष तक परिवार कल्याण संगठन में कार्य करने का अनुभव और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, दिये गये अपने लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति की हो।

3--हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चूंकि उक्त स्वास्थ्य सहायकों की वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है अतः अभी वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायकों को पदोन्नति न देने का प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति, भौगतापुर, जिला हरदोई में स्व0 श्री चन्द्र भाल के नाम से फर्जी अंगूठा लगाकर उर्वरक की प्राप्ति तथा सचिव का निलम्बन

36--श्री हरीशंकर --

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है साधन सहकारी समिति, भौगतापुर, ब्लाक बिलग्राम, जिला हरदोई द्वारा दिनांक 14-2-81 को चन्द्रभाल व रघुनन्दन प्रसाद के नाम 3,000 रु0 की चेक सं0 सी0 ए0/बी0 न0 128876 बनाई गयी और उस चेक से दिनांक 15-2-81 को चन्द्रभाल द्वारा खाद लेना दिखाया गया ? क्या यह सही है कि उक्त चन्द्रभाल, दिनांक 14-2-81 को जीवित नहीं थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, हरदोई ने जांच की है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक --

जी हां। किसी व्यक्ति ने स्व0 श्री चन्द्रभाल के नाम से निशानी अंगूठा लगाकर उक्त समिति से उर्वरक प्राप्त कर लिया था। सहायक निबन्धक द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य के लिये समिति के सचिव दोषी हैं। अतः उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज में स्थापित किये गये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक अस्पताल

37--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खंड जहानागंज में अब तक कितने अस्पताल आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक स्थापित किये गये है तथा स्थापित अस्पतालों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री लोकपति--

उक्त क्षेत्र में एक चार शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, एक चार शैय्यायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित किया जा चुका है। उनके उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

महामन्द जलालनगर हाउसिंग स्कीम, शाहजहांपुर में अर्जित की गई भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

38—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर शहर वर्ग महामन्द जलालनगर हाउसिंग स्कीम में 22-6-68 के नोटीफ़िकेशन के आधार पर जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी थी उनके नाम व पते क्या हैं तथा उन लोगोंको जिला जज, शाहजहांपुर के एवार्ड दिनांक 29-4-80 के आधार पर अभी तक मुआवजा न दिये जाने के उत्तरदायी कौन है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास की शाहजहांपुर महामन्द जलालनगर हाउसिंग स्कीम में जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उनका नाम व पता संलग्न सूची में अंकित है ।

मुआवजा वितरण का कार्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (द्वितीय) कमलानगर आगरा द्वारा किया जाना था किन्तु उन्हें जजमेन्ट व डिग्री की प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके कारण डिग्री के अनुसार बढ़े दर पर मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 526 पर ।)

जनपद चमोली में जोशीमठ में विष्णु प्रयाग परियोजना हेतु इन्टरनल सड़क के निर्माण में डायनामाइट के प्रयोग से जोशीमठ नगर को खतरा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

[12 बजकर 10 मिनट]

आज नियम 301 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और सबसे पहली सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की है ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जनपद चमोली में जोशीमठ के ठीक नीचे अलकनन्दा के किनारे पैनी बैण्ड से मारवाडी तक सिंचाई विभाग द्वारा विष्णु प्रयाग परियोजना क लियें इन्टरनल सड़क का निर्माण डी0जी0वी0आर0 द्वारा करवाया जा रहा है, जोशीमठ अत्यन्त ही संवेदनशील क्षेत्र है और भू-स्खलन की समस्या से गम्भीर रूप से प्रभावित है । भू-वज्ञानिकों की राय के अनुसार यहां पर डायनामाईट विस्फोट पर रोक है । इस सड़क के जोशीमठ के नीच से निर्माण किये जाने पर जोशीमठ के जनता ने घोर आपत्ति की थी तथा जन प्रतिनिधियों की मांग पर शासन ने पूर्व इस सड़क निर्माण पर रोक लगा दी थी परन्तु हाल ही में यह रोक हटाकर पुन: निर्माण कार्य इस सड़क पर शुरू करवा दिया है और सड़क निर्माणमें शासन क स्पष्ट आदेशों के विरुद्ध डायनामाईट विस्फोट अन्धाधुन्धरूप से किया जा रहा है जिससे जोशीमठ के अस्तित्व को भयंकर खतरा पैदा हो गया है। जोशीमठ धार्मिक पर्यटन सामरिक व्यापारिक महत्व का नवोदित नगर है तथा तहसील एवं पुलिस संगठनों एवं सेना का प्रमुख केन्द्र है । इस सड़क को बजाय जोशीमठ के नीचे से बनाये जाने के पैनी बैण्ड के पास से पुल देकर अलकनन्दा की दूसरी ओर उर्गम की तरफ से बनान हेतु शासन से निवेदन किया गया था । इस प्रकार सड़क बनन से नदी पार वाले ग्रामों उर्गम चाई-थाई आदि को सड़क की सुविधा मिल जाती तथा जोशीमठ को खतरा नहीं होता । सड़क के इस प्रकार निर्माण से लोगों में भयंकर आक्रोश भय एवं निराशा व्याप्त हो गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कुबर सिंह नेगी]

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मा0 मंत्री सिंचाई से निवेदन करते हैं कि जोशीमठ की सुरक्षा की दृष्टि से अविलम्ब ही इस सड़क निर्माण कार्य को रोका जाय तथा सड़क निर्माण पैनी बैण्ड पास से पुल देकर अलकनन्दा की दूसरी ओर से कराया जाय तथा डायनामाईट विस्फोट पर रोक लगाई जाय तथा भू-वैज्ञानिकों की राय की अवहेलना न की जाय ।

एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में छात्रों द्वारा अनशन के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

महोदय, कानपुर स्थित एच0वी0टी0आई0 इस प्रदेश का महानतम तकनीकी शिक्षा संस्थान है। इस संस्थान में छात्रावास की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है । छात्रों को अपने साधनों से संस्थान जाने में विशेष कठिनाई है । संस्थान की ओर से चलने वाली बस बन्द कर दी गयी है । छात्रावास में चिकित्सा और टेलीफोन सुविधा नहीं है । इस कालेज में छात्रों को परीक्षा फल घोषित करने के बाद भी अनुत्तीर्ण करने की घटनायें हो चुकी हैं। एक छात्र तो लिखित परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किया किन्तु सेशनल परीक्षा में उसे शून्य अंक देकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया । संस्थान में पुराना नियम था कि जो छात्र 50 प्रतिशत अंक पाते थे उन्हें कैरीओवर देकर अगली कक्षा में तैनात कर दिया जाता था लेकिन इस वर्ष उस पद्धति को भी समाप्त कर दिया गया । इससे इस संस्थान के छात्रों में घोर असंतोष और उत्तेजना है। इन्हीं सब अनियमितताओं के विरुद्ध इस संस्थान के छात्र देवेन्द्रसिंह सचान ने एक ज्ञापन संस्थान के निदेशक को दिया । निदेशक ने 15-2-82 को इनका ज्ञापन लेकर रख लिया और उसके विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाहियां प्रारम्भ की । परिणाम यह हुआ कि 18-2-82 को जब देवेन्द्र सिंह सचान खाना खाकर संस्थान की ओर चले तुरन्त बेहोश होकर गिर पड़े और चिकित्सा सुविधा न होने से उनकी मृत्यु हो गयी । छात्रों का आरोप है कि स्वर्गीय सचान को उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने की सजा के रूप में संस्थान के निदेशक ने जहर दिलाया । इसके विरोध में संस्थान के छात्र अनशन पर बैठ गये हैं । संस्थान में स्थिति विस्फोटक है । इस प्रदेश का प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान अव्यवस्था का शिकार है ।

अतः हमारी मांग है कि स्वर्गीय देवेन्द्र सिंह सचान के मृत्यु की तत्काल उच्च स्तरीय जांच हो । उसकी विधवा पत्नी और बच्चों को शासकीय सहायता दी जाय । संस्थानों की अव्यवस्था को समाप्त करने हेतु एक जांच दल जाय और उसके उपाय सुझायें । संस्थान के निदेशक जो कभी इंजीनियरिंग के अध्यापक नहीं रहे और इक्सटेंशन के ऊपर कार्यरत हैं उन्हें अपने पद से तत्काल हटाया जाय ।

लिफ्ट सिंचाई विभाग जनपद जालौन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद जालौन के लिफ्ट सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार तथा नकारापन तो चरम सीमा पर पहले से ही था परन्तु उनके द्वारा किये जा रहे कुछ नये कुकृत्यों की ओर मैं सरकार व सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी हाल ही में लिफ्ट सिंचाई विभाग जनपद जालौन में एक नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के अनुसार ऐसे सभी नलकूप चालकों जिनके नलकूपों पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम घंटों की अवधि पूरी नहीं हुई है यह आदेश दिया गया है कि वे तुरन्त इस निर्धारित अवधि को पूरा करें। इसके लिये पानी चाहे नालों में क्यों न बहाना पड़े। जहां नाले नहीं हैं वहां किसानों के खेतों में जबरदस्ती पानी काटा जा रहा है। भले ही उसमें ऐसी फसलें हों जिन्हें पानी लगने से क्षति पहुंचेगी। नलकूप चलने के बिल किसानों के खातों में डाले जा रहे हैं। किसानों द्वारा स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने पर यह उत्तर दिया जाता है कि अधीक्षण अभियन्ता के इसी आशय के आदेश हैं। इसी क्रम में नलकूप सं0 13 कालपी ग्राम मेड़ी पर श्रद्धा नामक हरिजन का पूरा 6 बीघे का खेत जबरदस्ती भरा गया जिसमें चना बोया हुआ था पूरी फल नष्ट हो गयी इस प्रकार के बहुत से किसान अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते घूम रहे हैं परन्तु सुनवाई करने वाला कोई नहीं।

दूसरी ओर इसी विभाग के अधिकारियों ने किसानों से रुपया वसूलने का एक और नया तरीका ढूंढ निकाला है जो नलकूप नये स्वीकृत भी हैं उनको भी वे उस समय तक बोर छिद्रण नहीं होने देते जब तक उक्त गांव के किसानों से उनको भारी रकम नहीं मिल जाती। इन अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा यह नीति अपनाई गयी है कि जिन नलकूप बनने के स्थान से बिजली की लाईन डेढ़किलोमीटर से अधिक दूरी पर है वहां नलकूप नहीं लग सकता, अपना हिस्सा पाकर वहीं बिजली की लाइन नजदीक दिखा दी जाती है। मैंने सिंचाई विभाग के सचिव से इस सम्बन्ध में जानकारी की तो उन्होंने सूचना दी कि इस प्रकार का कोई भी आदेश अथवा नीति सरकार ने नहीं अपनायी है। मेरा आग्रह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन तुरन्त कार्यवाही करे तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करें।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में खरीफ की फसल में कुरमुला रोग का प्रकोप व सूखे से फसल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान वर्ष 1981 की खरीफ की फसल में पर्वतीय क्षेत्र में कुरमुला के प्रकोप व सूखा पड़ने से असिंचित भूमि में बिल्कुल भी खरीफ की फसल नहीं हुई है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। समय-समय पर मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 कृषि मंत्री जी को इस सम्बन्ध में राहत कार्य चलाने एवं कुरमुला विनाश योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु लिखा गया है तथा व्यक्तिगत रूप से कहा गया, किन्तु खेद है कि शासन की ओर से न तो राहत कार्य ही पर्वतीय अंचलों में चलाये गये हैं और न ही कुरमुला विनाश योजना प्रभावी ढंग से चलाई गयी है। इस समय कृषकों द्वारा खरीफ की बोवाई की तैयारी की जा रही है। कृषकों के पास बोने के लिये बीज उपलब्ध नहीं है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को विधान सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा शासन का ध्यान आकर्षित कर मांग करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क बीज देने की व्यवस्था करें, जनता को भुखमरी से बचाने हेतु राहत कार्य चलाये जायं तथा कुरमुला विनाश कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाया जाय।

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्वारा चिकित्साधिकारियों के चयन में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी द्वारा उपरोक्त विषय में की जा रही गम्भीर अनियमिततायें लाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबर हुसैन---]

दिसम्बर 13, 1981 को एक लिखित परीक्षा चिकित्साधिकारियों के पद पर चयन हेतु हुई थी जिसके लिये 12 दिसम्बर, 1980 को विज्ञापन निदेशक द्वारा दिया गया था। इस प्रकार एक वर्ष बाद परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि प्रदेश में चिकित्साधिकारी क पदों पर चयन हेतु आज तक कभी भी इस प्रकार की परीक्षा नहीं ली गयी। यदि निदेशक चाहते तो मेरिट के आधार पर चयन कर सकते थे लेकिन निदेशक ने लोक सेवा आयोग से नाम मात्र का पत्राचार किया क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिये वे स्वयं चयन कराना चाहते थे, जबकि शासन ने इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। फिर भी निदेशक ने शासन के नियुक्ति करने के आदेश प्राप्त कर परीक्षा कराई। इस परीक्षा में परीक्षाफल 4 जनवरी, 1982 को घोषित किया गया और सफल अभ्यर्थियों को गोपनीय ढंग से 27 से 29 दिसम्बर, 1981 तक उत्तीर्ण होने और साक्षात्कार का पत्र भेज दिया गया तथा 9 जनवरी, 1982 को साक्षात्कार लिया गया। सबसे हास्यप्रद बात तो यह है कि आजतक कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें सफल अभ्यर्थी को पहले परीक्षाफल गोपनीय ढंग से भेज दिया जाय और परीक्षाफल साक्षात्कार के 5 दिन पहले ही घोषित कर दिया जाय, यह सब केवल व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिये ही किया गया। इसके अतिरिक्त निदेशक ने गलत अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया क्योंकि शासन ने अपने पत्र दिनांक 13-12-81 में निदेशक को आदेश दिये थे कि एक स्थान के लिये 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाय परन्तु निदेशक ने शासन के आदेशों का उल्लंघन करके मनमाने तौर पर आयुर्वेद के 168 पदों के लिये 663 और यूनानी के 25 पदों के लिये 93 व्यक्ति ही बुलाये गये जबकि क्रमश: 340 और 120 व्यक्ति बुलाये जाने चाहिये थे। आश्चर्य का विषय है कि इसमें 5 ऐसे अभ्यर्थी बुलाये गये जिनका नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची तक में नहीं था जिसमें से एक माधो सिंह रोल नम्बर 1602 है। इससे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि अपने इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये निदेशक ने 20 जनवरी, 1982 को एक रिपोर्ट थाना वजीरगंज, लखनऊ में लिखाई है कि उनकी नियुक्ति संबंधी पत्रावलियां चोरी चली गयी हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 में किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधन के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 527 पर।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 में किये गये शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधनों एवं मुद्रण की त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 528-529 पर।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

कारागार मंत्री श्री राम सिंह खन्ना के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा का विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में एक निर्णय है। श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा, ने दिनांक 2 फरवरी, 1982 को माननीय कारागार मन्त्री श्री रामसिंह खन्ना के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी है। माननीय सदस्य श्री वर्मा का कहना है कि माननीय कारागार मन्त्री ने दिनांक 20 जनवरी, 1982 को सदन में हड़ताली जेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री गौरी शंकर भैय्या के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर एवं पूरक प्रश्नों के उत्तर में तथ्यों को छिपाया है तथा गलत बयानी की है। माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत में माननीय कारागार मन्त्री द्वारा दिये गये सम्बन्धित उत्तरों को उद्धृत किया है, जिनमें एक उत्तर यह था कि मंत्री जी की जानकारी के अनुसार जो लोग काम करना चाहते हैं उनमें से किसी को बाहर नहीं रखा गया है। श्री राम आसरे वर्मा के कथनानुसार वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने अपने उक्त कथन की पुष्टि में विभिन्न जेलों के ऐसे कर्मियों की सूचियां प्रस्तुत की हैं जो विभिन्न जेलों पर जा कर ड्यूटी देने गये परन्तु जिन

[श्री अध्यक्ष]

को अभी तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की फोटो स्टेट प्रतियां संलग्न की हैं जिन के ट्रान्सफर दण्डात्मक कार्यवाही के तहत किये गये हैं।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय कारागार मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय कारागार मंत्री ने मुझे अपने पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1982 द्वारा सूचित किया है कि 20 जनवरी, 1982 को तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दते समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "मेरे पास पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनके आधार पर यह बतलाया जा सके कि जेल कर्मियों की हड़ताल के वापस लिये जाने के बाद कितने जेल कर्मी बचे हैं जिन को ड्यूटी नहीं दी गयी या जिनका निलम्बन समाप्त नहीं हुआ है।" माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि उन का सम्बन्धित उत्तर इस बात का बोधक नहीं था कि जिस कर्मचारी की सेवा में बहाली के औपचारिक आदेश नहीं हुए और वह योगदान करने के उत्सुक हैं उन्हें भी ड्यूटी दे दी गई। उनका आगे कहना है कि निलम्बित कर्मचारी मुअत्तली के बावजूद सरकारी सेवक बना रहता है, यह बात और है कि उससे काम न लिया जाय तथा जहां तक उन अस्थायी कर्मचारियों का प्रश्न है, जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, उन्हें फिर से सेवा का अवसर देने के इरादे से ही जेल पर जा कर अपना नाम दर्ज कराने की अनुमति दी गई है और यह कहा गया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर उन्हें पद की अर्हता रखने पर वापस ले लिया जाय, अतः ऐसी स्थिति में अनेक कर्मचारियों को तत्काल सेवा में वापस नहीं लिया जा सकता।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत नामावली के बारे में माननीय मंत्री श्री खन्ना का कहना है कि ऐसा सम्भवतः उत्तरों का यह अर्थ लगा कर किया गया है कि निलम्बन आदेश समाप्त कर दिये गये हैं और सभी अस्थायी कर्मचारी ड्यूटी पर वापस ले लिय गये।

उक्त प्रश्न से सम्बन्धित दिनांक 20 जनवरी, 1982 की कार्यवाही का अवलोकन करने तथा उसके सन्दर्भ में माननीय श्री वर्मा की शिकायत और माननीय कारागार मंत्री के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में माननीय मन्त्री जी ने जानबूझ कर कोई गलत बयानी नहीं की है और इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न निहित नहीं है। अतः मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

विधान सभा सदस्य, श्री ए० सी० ग्राइस द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना सदन को देनी है। मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री ए० सी० ग्राइस, सदस्य, जिला कानपुर, जो कि नाम निर्देशित सदस्य हैं, उन्होंने विधान सभा में कांग्रेस (आई०) दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तद्नुसार श्री ए० सी० ग्राइस को अब कांग्रेस (आई०) दल के सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री शंकर सिंह द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में जानकारी की मांग

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैंने कल एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी और वह.....

श्री अध्यक्ष—

आपके विशेषाधिकार की सूचना.....

श्री मोहन सिंह—

जो विधान सभा की एक सदस्या के साथ दुर्व्यवहार हुआ.....

श्री अध्यक्ष--

वह संबंधित स्थान पर भेज दिया गया है आने पर उत्तर दिया जायेगा।

श्री शंकर सिंह--

सब कुछ सदन के सामने हुआ। यह हम लोगों से संबंधित नहीं है। जो कुछ हुआ कांग्रेस (आई0) के दो सदस्यों के मध्य का मामला है।

(व्यवधान)

हम लोगों ने देखा, पत्रकार लोगों ने देखा।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मा0 शंकर सिंह, आप बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं। कृपया आप बैठ जाइये।

श्री शंकर सिंह--

क्या सदन में यह सब हो सकता है। इससे सदन की गरिमा गिरी है।

श्री कुबेर भण्डारी--

यह प्रश्न बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

जितनी गम्भीरता से आप यह प्रश्न ले रहे हैं वह आपकी मुस्कराहट से पता चल रहा है।

श्री शंकर सिंह--

यह सदन की गरिमा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

कल सदन में इस विषय पर निर्णय दिया जा चुका और जो विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दिया गया है वह संबंधित जगह भेज दिया गया है। उसका उत्तर आने के बाद उसका भी निर्णय दिया जायेगा।

श्री मोहन सिंह--

क्या मा0 सदस्या महारानी दोहरे ने भी कुछ लिखकर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, उन्होंने कुछ लिखकर नहीं दिया है।

(सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

कृपया मा0 सदस्यगण शान्त रहें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में केवल एक सूचना प्राप्त हुई थी मा0 शंकर सिंह, सरदार सिंह, कुबेर भंडारी, दलगंजन सिंह और राधेश्याम वर्मा की दिनांक 25-2-1982 को जनपद मैनपुरी के ग्राम नगलावर में दस्यु सरगना छविराम की शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं एक मन्त्री से हुई गुप्त वार्ता से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में। इसको नियम 56 के अन्तर्गत अस्वीकार किया गया है।

श्री शंकर सिंह--

यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इसको आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। इस प्रश्न को लेकर चाहे कितना भी अविलम्बनीय रहा हो, लोक महत्व का रहा हो, सदन का अधिक से अधिक समय इस प्रश्न पर लिया गया। इस पर अनेकों बार सदन में चर्चा, वक्तव्य आदि सब हो चुके हैं। इसलिये अब मैं पुनः इसको उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री शंकर सिंह--

आप कम से कम दो मिनट का समय दे दें। मैं वह कोई बात नहीं कहूंगा जो पहले कही जा चुकी है। यह मामला इतना गम्भीर है कि कांग्रेस (आई) के विधायक के निवास स्थान पर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री त्रिपाठी जी और प्रदेश के गृह सचिव टकरू साहब और डी0 आई0 जी0 मुकर्जी साहब यह सब लोग वहां पर मौजूद थे।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मैंने आपको इजाजत नहीं दिया है। मा0 शंकर सिंह अब जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री शंकर सिंह--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आप इस सदन में किसी प्रश्न को बार-बार लाना चाहते हैं। यह सदन इस पूरे प्रदेश की, जिस प्रदेश की अनेकों समस्यायें और अनेकों कार्य हैं, उसके सबके निराकरण के लिये, हर बात के निर्णय के लिये और विचार के लिये है। एक ही विषय को लेकर सदन में बार-बार विचार करना न तो सदन के गौरव की बात है और न सदन अपने कार्य को पूर्ण रूप से पूरा कर पायेगा अगर एक ही बात को बार-बार लिया जायेगा।

श्री कुबेर भंडारी--

फूलन देवी भी नहीं पकड़ी गई।

श्री शंकर सिंह--

आप केवल दो मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मा0 शंकर सिंह, आप बैठ जाइये।

श्री शंकर सिंह--

मैं बैठ गया। आज्ञा शिरोधार्य है, मान्यवर।

मानिकपुर सतना रेल लाइन पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे से कारतूसों की चोरी के विषय में नियम 51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों में भिन्नता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जो मैंने औचित्य का प्रश्न आपको दिया था। मैं चाहता तो यह था कि अगर मुख्य मन्त्री जी मौजूद होते और वह उत्तर देते परन्तु वह है नहीं। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से

नोटः--[* * * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न किया था कि जो वक्तव्य मा0गृह मन्त्री जी ने रेलवेलाइन के ऊपर 31-1-82 को कारतूसों की चोरी के सम्बन्ध में जो घटना हुई उस सम्बन्ध में 2-2-82 को नियम 51 के अन्तर्गत दिया था। उसके ऊपर 11-2-82 को उत्तर मिला मा0 सदन के अन्दर उसमें मा0 गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सिर्फ यह बात कही है कि दो कारतूस मिले। यह सूचना उन्होंने 11-2-82 को इस मा0 सदन के अन्दर दी है और उसके बाद 24-2-82 को जब फिर अग्रेतर वक्तव्य आया तो उसके अन्दर गृह मंत्री जी ने यह बात कहीं है कि रेलवे लाइन के करीब-करीब जब देखा गया तो 7698 कारतूस बरामद हो गये। अब यह घटना 31 तारीख की है। 2 तारीख को हमने नोटिस दिया। पहली सूचना मा0 गृह मंत्री जी ने 11 तारीख को सदन में रखी और दूसरी सूचना 24 तारीख को मा0 गृह मन्त्री जी ने रखी और यह दोनों सूचनायें उनको एक ही स्रोत से मिलीं तो जब पहली तारीख को 7698 कारतूस बरामद हो गये तो क्यों पहले केवल दो कारतूस मंत्री जी ने बरामद होने दिखाये। माननीय सदन की कार्यवाही में दोनों स्टेटमेन्ट आये हैं।

यह इस तरह से माननीय सदन के अन्दर भ्रम पैदा हो गया है।एफ0 आई0 आर0 लार्ज कराई गई 31-1-82 को शामको साढ़े सात बजे अगर पहली तारीख सुबह से, छानबीन शुरू हो गई और 7698 कारतूस बरामद हो गये तो जो 7698 कारतूस बरामद हुए उनको कहीं रखा भी गया होगा। उसका कहीं रेकार्ड में इन्दराज हुआ होगा। जब 7698 कारतूस बरामद हुए तो माननीया गृह मंत्री को इसकी जानकारी देनी चाहिये थी। माननीय गृह मंत्री ने 11 तारीख को केवल 2 कारतूस पानी में पाये जाने की सूचना दी जब कि यह पहली तारीख को ही 7 हजार से ज्यादा कारतूस बरामद हो चुके थे। मेरा निवेदन है कि माननीया गृह मंत्री ने दो दिन यहां विभिन्न स्टेमेन्ट्स दिये जिससे सदन के अन्दर भ्रम पैदा होता है। इसलिये मैं यह औचित्य का प्रश्न उठाता हूं।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में यदि कोई सूचना अपूर्ण हो, अधूरी हो तो उसका शोधन वक्तव्य हो जाता है या आपकी पीठ से करण 218 धारा के तहत कार्यवाही कर दी जाती है। लेकिन नियम 51 के अन्तर्गत सूचना के लिये स्पष्ट प्राविधान है। दिक्कत यह है कि माननीय गृह मंत्री दो दिन परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये हैं। एक में सूचना कुछ थी, दूसरे में दूसरी सूचना थी। ऐसी स्थिति में जब सदन के सामने मंत्री लोग परस्पर विरोधी वक्तव्य देने लगते हैं तो सदन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। अगर माननीया गृह मंत्री ने स्वयं दोनों वक्तव्यों को पढ़ लिया होता तो स्वतः उनको मालूम हो जाता कि जो सूचना दी गयी है वह परस्पर विरोधी है और वे अपने को ठीक कर लेती आप 218 करण के तहत ऐसे मामले में कार्यवाही करते हैं। गलत सूचना मिलने पर इसी तरह से उन्नाव के जिलाधिकारी और एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी सदन के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है जिससे इस तरह के विरोधाभासी वक्तव्य न आवें। इसीलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं और आपसे मेरा आग्रह है कि आप की पीठ से गृहमंत्री को प्रताड़ना दी जाय कि वे अपने इस रवैये में सुधार करें और साथ ही मुख्य मंत्री जी से आप कहें कि गृह मंत्रीजी से उनका विभाग छीन लिया जाय और ताकि इस तरह का वक्तव्य सदन के सामने उनकी तरफ से न आया करे। आपकी तरफ तो बहुत योग्य विद्वान सदस्य हैं, काशीनाथ मिश्र जो सूचना में सुधार नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं को कामचलाऊ गृह मंत्री बना दिया जाय ताकि वे सदन में सही ढंग से प्रश्नों के उत्तर तो दे दिया करें। जिनकी बातों से प्रदेश की जनता गुमराह नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन और माननीय मोहन सिंह जी ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर बल दिया है। 11-2-82 को एक वक्तव्य हुआ था। कार्यवाही देखने से स्पष्ट नहीं होता है कि इस वक्तव्य में उन्होंने कोई विषेष बात कही हो। उन्होंने यह कहा था कि विवेचना जारी है। विवेचना जारी होने की वजह से पूरी सूचनायें प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि सदन को पूरी सूचना नहीं दी जा सकी थी, इसीलिये फिर यह आदेश आया था कि अग्रेतर वक्तव्य दिया जाय और अग्रतर वक्तव्य में पूरी सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह आप कह सकते हैं कि पहले जो उनका वतक्व्य आया था उसमें उन्होंने पूरी सूचना नहीं दी, लेकिन बाद के वक्तव्य में सारी बातें आ गयी।

श्री रियासत हुसैन---

ये कारतूस जो 7 हजार से अधिक थे नाले से पहली तारीख को ही बरामद हुए तो ये किसी की जेब में तो होंगे नहीं, कहीं न कहीं तत्काल जमा हुए होंगे। 11 दिन तक ये 7 हजार से अधिक कारतूस छिपे कहां रहे, मेरा बल इस चीज के ऊपर है।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये अग्रेतर वक्तव्य देने को कहा गया। यह जानकारी उसी समय होनी चाहिये थी लेकिन उस समय चूंकि सूचना नहीं थी इसीलिये उन्होंने अपने पहले बक्तव्य में इतने कारतूस बरामद होने की बात नहीं कहीं। बाद में उनको सूचना मिली कि बरामद हुये तो उन्होंने बतलाया। इसलिये इसको उठाने की अनुमति मैं नहीं देता।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 69-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

(12 बजकर 45 मिनट)

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 69-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,63,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक निर्माण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,66,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,30,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माक विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,21,82,000 रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,21,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जिस समय 1947 में भारतवर्ष नब्बे साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजाद हुआ उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 15,113 किलोमीटर सड़कें थी। आज इस समय जो स्थिति है 63,655 किलोमीटर पूरे उत्तर प्रदेश में मेटल्ड रोड्स पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा बनायी जा चुकी हैं।

एक सदस्य––

कागजों में हैं.....

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, इस समय जो हमारी छठी फाइव इयर प्लान है इस में पूरे उत्तर प्रदेश के लिये जो योजना तैयार की गई थी, जिसमें गांवों की सड़कें भी शामिल थी, एक स्तर तक पूरे प्रदेश के सड़कों और पुलों को लाना था, जो कच्चे रास्ते थे, दूर दराज के स्थान थे उनको जोड़ना था, वह 1333 करोड़ रुपये की थी। उसकी स्वीकृति प्लानिंग कमीशन से 415 करोड़ रुपये की मिली। इस 415 करोड़ में से 290 करोड़ मैदानी इलाके के लिये और 125 करोड़ जो है वह पहाड़ों के लिये मिला। इसी तरह से इस समय 410 करोड़ रुपये की जो है हम लोगों को आवश्यकता है अगर हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जो गांव हैं उनको जोड़ना है। गांव हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं हमारे समाज की 85 प्रतिशत से अधिक लोग गावों में रहते हैं। 410 करोड़ हमें चाहिये। उन तमाम सड़कों को जोड़ना होगा, गांवों को मेन रोड से जोड़ना होगा। पहले हमने

[श्री अम्मार रिजवी—]

प्रयास इस बात का किया था कि 1985 तक यह कार्य हो जाय लेकिन धन के अभाव की वजह से 1985 तक न हो कर 1990 तक यह पूरा हो सकेगा ।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 45 करोड़ रुपये छठी पंच वर्षीय योजना में रखे गये हैं जो कि हमें 415 करोड़ रुपये मिले हैं उसके अन्दर यह है । इस धन को हमें उन स्थानों पर खर्च करना है जहां हमारे हरिजन भाई रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं । 188 ब्लाक प्रभावित होंगे । इसके अन्तर्गत जो पहले ब्लाक लिये गये थे, वे बहुत कम थे । इसमें साढ़े आठ करोड़ रुपया इस साल का खर्चा आयेगा । इसके अतिरिक्त इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जहां जनजातियां हैं, जहां पर वे बसते हैं वहां पर 9 करोड़ 82 लाख रुपये इस काम के लिये रखे गये हैं कि उन इलाकों को सड़कों और पुलों से जोड़ दिया जाय । इस वक्त केन्द्र से हमें जो योजना के लिये सहायता दी जा रही है उसमें 50 प्रतिशत वे दे रहे हैं और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को लगाना पड़ रहा है । इस प्रकार से जिन सड़कों का महत्व आर्थिक रूप से ज्यादा है उसके लियें भी ज्यादा प्राविधान किया जा रहा है और केन्द्र से इस हेतु हमें ज्यादा सहायता मिल सकेगी । हम इसका प्रयास कर रहे हैं । इस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत् योजना में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काम कराया जा रह है और बहुत सी स्कीमें इसके तहत ली गई हैं । 81--82 में जो स्थिति थी और हमारे पास जो 84 करोड़ इस स्कीम के लिये था उसमें से 59 करोड़ रुपया हिल्स के लिये रखा गया है ।

इस तरह से हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण कर सकें और जितने हमारे साधन हैं उनको देखते हुये कार्य करें । इस समय हमारी एक बड़ी भारी उपलब्धि यह रही है कि हमारे साधन सीमित होते हुये भी इस साल अर्द्धकुम्भ मेले का कार्य पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा किया गया । यह पहली बार है जब कि अर्द्धकुम्भ मेले के सारे कार्य को इस विभाग द्वारा सम्पन्न कराया गया । इसमें 8 पैंटून ब्रिज, 16 पाइप कल्वर्ट्स, एक ओवर हेड ब्रिज 86 किलोमीटर कैम्पबर रोड, 41 किलोमीटर पीलारोड्स, शास्त्री ब्रिज के लिये एक दूसरी गली का निर्माण, मेला एरिया रोड का इम्प्रूवमेंट किया गया । मान्यवर, जैसा आप स्वयं जानते हैं यह अर्द्ध कुम्भ मेला सन् 83 में होने वाला था किन्तु यह इसी साल 82 में हो गया । हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे थे । चूंकि यह इसी साल हो गया लिहाजा हमने इस कार्य को समय पर कर दिया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि विभाग की है । बहुत एजेन्सियां इस कार्य को करती थीं, उसे हमारे विभाग ने ही करके दिखाया है और कामयाबी हासिल की है ।

इसके अतिरिक्त हमारी 82--83 की प्लान वर्क्स की स्थिति इस प्रकार है कि 68 करोड़ रुपया हम रोड्स और ब्रिजेज के लिए दिया गया था जिसमें से 43.65 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में दिया गया है । इस तरह से हमने प्लान का विकेन्द्रीकरण किया है । इसी स्तर पर हम हर साल का प्लान बना रहे हैं और सारा निर्णय वहां के स्थानीय जन-प्रतिनिधि बैठकर करते हैं । 25 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर के लिये रखा गया है और बाकी विकेन्द्रीयकरण के द्वारा जिलों को रुपया दे दिया गया है । स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में पहाड़ों के लिये 1.50 करोड़ रुपया है जिसके अन्दर सारा स्टेट सेक्टर के अन्दर सर्व किया जायेगा । सारे स्टेट के लिये जो प्लान आउट-ले है वह 93 करोड़ 99 लाख है । इस वक्त जो हमारी स्थिति है वह यह है कि यू0 पी0 रोड फण्ड में 3 करोड़ 60 लाख, स्टेट ब्रिज फण्ड में 4 करोड़ 83 लाख ,सेन्ट्रल रोड फण्ड 1 करोड़ 9 लाख, रेलवे सेफ्टी वर्क्स में 86 लाख तथा दूसरे प्लान आइटम्स में 5 लाख का प्राविधान है ।

मान्यवर, यह आंकड़े मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं ताकि बहुत सी बातें साफ हो जायेंगीं और हमारे जो सीमित साधन हैं उनके संबंध में मैं इस सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं । मान्यवर, पिछले वर्ष हैवी मानसून की वजह से आपको ज्ञात होगा सड़कों को काफी नुकसान

हुआ उसका टोटल डैमेज कम्प्यूटर के जरिये से निकाला गया और जो 44 करोड़ रु0 का नुकसान था लेकिन 12 करोड़ 44 लाख रु0 सिर्फ हमें सेन्ट्रल एसिस्टेंट 81–82 में मिल सकी। हमने 83 करोड़ का व्योरा भेजा है। इसी तरह से 81–82 में 32 करोड़ 12 लाख रु0 जनरल रिपेयर्स आफ रोड्स के लिये दिया गया था। उनका जो रेट पिछले साल तक था वह 7100 पर कि0 मी0 था लेकिन बीटूमैन और मजदूरी की कास्ट बढ़ जाने की वजह से इसे 8 हजार कर दिया गया है साधारण रिपेयर्स के लिये 38 करोड़ 18 लाख का प्रावधान किया गया है और दो करोड़ रुपये स्पेशल रिपेयर के लिये किया गया है।

नेशनल हाईवे भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो सड़कों के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें दूसरे स्टेट्स के मुकाबले हमारे यहां नेशनल हाईवे बहुत कम हैं। नेशनल हाईवे जो हमारे राज्य से गुजरते हैं उसकी पूरी लम्बाई 2474 कि0 मी0 है और बाकी या तो स्टेट हाईवे हैं या फिर हमारे अन्दर की रोड्स हैं इसके लिये 1981–82 में 10 करोड़ 10 लाख रु0 केन्द्र ने हमें दिया था जब कि 20 करोड़ 50 लाख रु0 हमने मांगा था ताकि सही तरीके से रिपेयर की जा सके। 1980 के मानसून डैमेजेज के लिये हमने 6 करोड़ 75 लाख रु0 मांगा था और हमें सिर्फ 4 करोड़ 16 लाख रु0 अभी तक मिला है। 81–82 में 3 करोड़ 28 लाख डैमेज एसेस किया गया उसमें से 2 करोड़ 13 लाख सिर्फ हमें मिल सका है। इस बार हमारा प्रयास है कि 22 करोड़ 94 लाख रु0 हमें केन्द्र से मिलें जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। केन्द्र के माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई और उम्मीद है कि अच्छी धनराशि मिल जायगी लेकिन अभी तक कुल 5 करोड़ रु0 हमें वहां से नेशनल हाईवे की रिपेयर के लिये मिल सका है।

इंडिया पापुलेशन प्रोजक्ट जो स्वास्थय विभाग द्वारा संचालित होता है उसकी एक्जीक्यूटिव एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग है। इसमें जगह को आइडेंटिफाई करना स्वास्थय विभाग का काम है लेकिन उसमें बिल्डिंग आदि तमाम चीजों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसलिये एक एडीशनल चीफ इंजीनियर रखा गया है

इसी तरह से 5.7 करोड़ रु0 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के कार्य के लिये हमें इस साल मिला है जिसमें हमें ग्रामीण अंचलों में स्कूल बनाने हैं।

मान्यवर, मैं यहां पर कुछ शब्द यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन के बारे में कहना चाहूंगा आज इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज रेडियो और समाचार पत्रों में भी सुना होगा कि इन्टरनेशनल एशिया एवार्ड 82 जो भारत वर्ष में पहले केवल हैवी इलेक्ट्रिकल स को मिला है और किसी स्टेट को नहीं मिला है वह आपके राज्य के सेतु निगम को मिला है यह बैंकाक में मिला है उसमें मैं भी पहले जाने वाला था लेकिन सदन की जहह से नहीं जा सका तो मैंने प्रतिनिधि के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजा है यह यमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। यह भारतवर्ष में हैवी इलैक्ट्रिकल्स के आलावा किसी राज्य को नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि यह माननीय सदन के सदस्यों के लिये गौरव की बात है। मान्यवर, यह ब्रिज कारपोरेशन 30 मीटर से ऊपर के पुल बना रहा है और यह 5 लाख रु0 के धनराशि से शुरु हुआ था। और उसके बाद इसकी स्थिति ऐसी है कि आज हर हफ्ता एक पुल बनाने का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। अभी तक हम 15 दिन में एक पुल

[श्री अम्मार रिजवी--]

तैयार करते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब हर हफ्ता हम एक पुल ब्रिज कारपोरेशन के जरिये से बना सकेंगे। आज इसका काम केवल उत्तर प्रदेश की सीमाओं में नहीं देश की सीमाओं में चारों तरफ फैल गया है।

इस समय हिन्दुस्तान में जो "एशियाड" होने जा रहा है, उसके लिये नई दिल्ली में कई फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं और बन चुके हैं वह हमारे इसी ब्रिज कारपोरेशन द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। इन फ्लाईओवर्स पर लिखा हुआ है-उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन। इस कारपोरेशन के काम को सारे प्रान्त वालों ने सराहा है और वह इससे प्रेरणा ले रहे हैं और काम करने के लिये हमें हर जगह बुलाया गया है और वहां भी काम किया जायगा। 7 महीने पहले तक इसका काम भारत तक सीमित था, लेकिन अब इसका क्षेत्र कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन, टर्की, लीबिया और इजिप्ट आदि तमाम देशों में फैल गया है। बहरीन में हम इसका एक नया आफिस बनाने जा रहे हैं, ताकि आसपास के मल्कों में इसके कार्य को कन्ट्रोल किया जा सके। ब्रिज कापोरेशन का जो काम विदेशों में हो रहा है, वह यूरोपियन कंपनियों के साथ बड़े कम्प्टीशन के बाद हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे कार्य की क्वालिटी और स्तर कितना अच्छा है, जिनका मूल्यांकन वहां होता होगा।

श्री ऊदल--

आप इसका नाम बदलकर इन्टरनेशनल ब्रिज कारपोरेशन कर दीजिए ?

श्री अम्मार रिजवी--

मुझे तो गर्व है इस पर जो हम उत्तर प्रदेश शब्द कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग भारत में रहकर दूसरे मुल्क की तरफ देखते हैं, वह वहां से प्रेरणा लेते हैं, इसलिये उनको भारतवर्ष अथवा भारत कहने में लज्जा महसूस होती है। तो इससे बड़ा फायदा है, हमारे पास जो फारेन एक्सचेंज है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि मंत्री जी सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश की नाप-जोख करने के सर्वोच्च अधिकारी हैं। इनकी मुबारक जुबान से जो निकलेगा वही इस प्रदेश में मान्य होगा। मंत्री जी ने बार-बार भारत के बजाये भारतवर्ष कहा है। इस देश का नाम भारत है और भारतवर्ष नाम पुरानी किताबों में है। तो इस बात पर व्यवस्था चाहिये कि इस देश का नाम भारतवर्ष है या भारत है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर न मैं व्यवस्था दे सकता हूं न आप मांग सकते हैं और न आप व्यवस्था दे सकते हैं और न उसकी मान्यता हो सकती है। इसका जो नाम है वह है।

श्री अम्मार रिजवी--

जो मुद्रा हम इस प्रकार से बाहर से हासिल कर रहे हैं। अभी करीब दो करोड़ रुपया हमने ब्रिज कारपोरेशन का जो बाहर की इन्कम थी--उस फारेन एक्सचेंज को उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित किया है और 14 करोड़ रुपये का जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो इस समय उत्तर प्रदेश ब्रिज कापोरेशन का बाहर के मुल्कों में पड़ा है उसको हम अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं, जिससे हम अपने यहां पुलों और सड़कों का निर्माण उनकी सहायता से आधुनिक तरीके से करवा सकें। जैसे कि बाहर करते हैं। मैं एक बात बहुत सफाई से यहां रखना चाहता हूं कि बाहर हमारे काम करने का मतलब यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो संसाधन हैं, वह सीमित हैं, इसलिये बाहर से जो हमें मुद्रा मिलेगी, उससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश लाभान्वित होगा। जो पैसा वहां से आया है वह यहां के कार्यों और यहां की सड़कों पर लगेगा। यह मकसद है हमारे बाहर कार्य करने का। ताकि हम अपने संसाधन बढ़ा सकें और अपने प्रदेश व देश को हम आगे बढ़ा सकें।

मान्यवर, दूसरा हमारा राजकीय निर्माण निगम है जो इस समय उत्तर प्रदेश और देश मे बहुत सी इमारत बनाने में लगा हुआ है। इसका क्षेत्र लिबिया तक में सीमित नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैला हुआ है और बहुत जल्द ही हम इस निगम को भी उसी स्तर पर लाने में कामयाब होंगे जैसा कि हमारा स्टेट ब्रिज कारपोरेशन है। हमारे राजकीय निर्माण निगम, ब्रिज कारपोरेशन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो हमारी एक्स पार्टीज हैं वे तीनों ही जो ओवरसीज कन्सट्रक्शन का कार्य है, बाहर की सड़कें हैं, बाहर की इमारतें हैं और पुल हैं, उनके ठेके लेकर उनके काम को करें ताकि हम फारेन एक्सचेज पैदा कर सकें। जो हमारी कामयाबी है उससे हम बहुत आशा रखते हैं। जो हमने काम किया है उसके लिये जापान, इटैलियन और ब्रिटिश फर्म्स से टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे। पिछली मर्तबा जब मैं बगदाद गया और वहां के पी0 डब्लू0 डी0 के मिनिस्टर से मिला तो वे इस बात के लिये राजी हुये कि उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय स्तर पर जो एन0 बी0 सी0 कारपोरेशन है उसको मिले और इनसे वे टैन्डर्स आमंत्रित करेंगे ताकि वे भी टेन्डर्स दे सकें। जो हमारी कामयाबी है वह प्रदेश, देश और बाहर भी फैल रही है।

इसी प्रकार से जो हमारी इमारतें बनी हैं लिबिया में, हमारे मजदूरों, टैक्नीशियन्स ने और इंजीनियर्स ने बनायी है। हर जगह उनकी बहुत तारीफ हुयी है बमुकाबले उनके जो दूसरे मुल्कों और यूरोपियन कम्पनीज ने बनाई है। इस समय, मान्यवर, आपके द्वारा मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने वहां पर काम किया और प्रदेश का सिर ऊंचा किया, उनको मुबारकवाद भी देता हूं।

इसी प्रकार से जो हमने पी0 डब्लू0 डी0 में जो ठेके की प्रथा थी और जिस प्रकार से वहां बड़े-बड़े गिरोह बने हुये थे, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किये। अब यह किया है कि जो 1 लाख से ऊपर के ठेकेदार होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाय, अभी हम एक लाख से नीचे वाले ठेकेदारों की रजिस्टर कराने का कार्य नहीं कर सके। क्योंकि उनकी संख्या बहुत है। हमारे प्रदेश में स्टेट ब्रिज कारपोरेशन और राजकीय निर्माण निगम का बनाया जाना यह ठेकेदारी की प्रथा के बहुत विरुद्ध था क्योंकि बड़े-बड़े काम जो लाखों और करोड़ों रुपये के होते थे और जो प्राइवेट एजेन्सियों और प्राइवेट कम्पनियों द्वारा होते थे, अब ये काम इनके द्वारा हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि ठेकेदारी को कम से कम लागू करें और जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करायें।

इसी प्रकार से हमारे यहां पर एक टेक्नीकल आडिट सेल है जो सुदृढ़ीकरण का काम कर रहा है। वह शासन के नीचे कार्य करता है जिससे हम क्वालिटी कन्ट्रोल को दिखवा सकें। उसका सीधे शासन से सम्पर्क रहता है और बीच में किसी चीफ इंजीनियर का दखल नहीं होता है ताकि जो शिकायतें उनके विरुद्ध प्राप्त हों, उनकी अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच हो सके। पिछले साल हमने 181 अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया था मुख्तलिफ लैविल्स पर और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है। मान्यवर, हमारे जो संसाधन हैं, वे बड़े ही सीमित हैं और हमें इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हमने प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, हमने प्रयास किया है कि सीमेंट के बड़े-बड़े पुल न बनाकर पाइप ब्रिजेज बनायें। ताकि कम कीमत में उन लोगों को फायदा पहुंचा सकें जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो एक दूसरे से कटे हुये हैं। हम यह भी कर रहे हैं कि जो इलाके कटे हुये हैं और एक दूसरे से अलग हैं उनको जोड़ने के लिये ईट का खरन्जा आदि बिछाकर ही सड़क बना दी जाय और बाद में जब हमारे संसाधन हों तो उनकी ब्लैक टापिंग करा दी जाय।

[श्री अम्मार रिजवी—]

कुछ शब्द, मान्यवर, मैं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के संबंध में भी कहना चाहूंगा। आज मौजूदा परिस्थितियों में कुछ छुपी हुई शक्तियां इस बात की कोशिश कर रही हैं कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर जो एक सद्भावना और आपस में प्रेम का वातावरण बना हुआ है उस पर कुठाराघात किया जाय। उस चैलेन्ज को हमने स्वीकार किया है और इस बात का शासन ने प्रयास किया है कि झांसी में इसी साल एक आयोजन किया जायेगा जिसमें सन् 1857 के इतिहास को पुर्नजीवित किया जायेगा, जिसमें एक दूसरे से मिल कर सद्भावना का वातावरण तैयार किया जायेगा, जहां बिना मजहब का ख्याल किये सबको एक मंच पर लाया जायेगा और यह हम यहां पर करने जा रहे हैं जहां पर एक महिला ने उस समय अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चैलेन्ज किया था और बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया था। इसका हम लोग इसी साल से आयोजन करने जा रहे हैं।

इसके अलावा पूरे प्रदेश में एक राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह भी बनाया जाया करेगा। इसके अलावा उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जो जुबाने हैं उनको भी सीखने के लिये इन्टरमीडिएट कालिजों में व्यवस्था करायी जायेगी। इसके लिये अभी सिर्फ 8 इन्टरमीडिएट कालिजों में साउथ इंन्डियन लैंगुएज सिखाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अभी तक यह व्यवस्था यूनीवर्सिटी में ही थी और वहां से इसका डिप्लोमा आदि मिलता था।

उर्दू के विकास के लिये उर्दू एकादमी और दूसरी एजेन्सीज को काफी मदद दी गयी है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

उसको दूसरी भाषा बनाने के बारे में भी तो कहिये ?

श्री अम्मार रिजवी—

उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा कर चुके हैं। उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे दहराने से कोई लाभ होगा। फिर आप कहेंगे कि उसी को दोहराया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

उर्दू के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री का बयान तो आया लेकिन उसके खिलाफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय खाद्य मंत्री का भी तो बयान निकला है। पहले वाला आर्डिनेन्स विदड्रा हो गया ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसको हम रिप्लेस करेंगे और सीधे बिल लायेंगे। अब बनारस में माननीय खाद्य मंत्री का बयान छपा कि ऐसा कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं है। तो स्थिति स्पष्ट करें। कई मुंह से बोलने वाली इस सरकार का क्या विश्वास किया जाय।

श्री अम्मार रिजवी—

उसके लिये बेसब्री की जरूरत नहीं है। अखबार में कुछ निकला हो, उसमें माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा वह हिन्दी के पक्ष में कहा और अखबार में क्या चीज निकली, क्या हुआ उसके ऊपर टीका-टिप्पणी करना यहां पर उचित नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के मुसलमानों को सियासी रिश्वत देने के लिये उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का ऐलान किया था। 31 दिसम्बर, 1981 को लखनऊ में माननीय मुख्य मंत्री ने बयान दिया था कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे दिया

जायगा। लेकिन 1 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री का फिर बयान हुआ कि हमने अपने पिछले बयान को वापस ले लिया है और बजाय आर्डिनेंस लाने के बिल पेश करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ऐसा तो नहीं है कि उस उर्दू वाले बिल को चूहा लेकर कहीं अपनी बिल में तो नहीं चले गये ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, रियासत साहब को बिलों की ज्यादा जानकारी है। मैं तो नहीं कह सकता हूं। मान्यवर, सदन बुलाया जा चुका था, अगर उस वक्त आर्डिनेन्स ले आये होते, तो कहा जाता कि असंवैधानिक हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

अध्यादेश लाने के लिये तो विधान परिषद् का सत्रावसान किया गया, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलाम—

मान्यवर, उर्दू को सेकेण्ड लैंग्वेज बनाने की स्पष्ट बात कीजिए और यह बताइये कि किस तारीख को इसको सेकेण्ड आफिशियल लैंग्वेज बनाया जायगा ? सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया था कि 198 के आखिर तक उर्दू को सेकेंड आफिशियल लैंग्वेज डिक्लीयर कर दिया जायगा। आप अभी तक नहीं कर सके और बहुत से काम आर्डिनेंस के जरिये से कर लिये। इसके लिये क्यों नहीं आर्डिनेंस लाये। मैंने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जायेंगे, हम तुमको खबर होने तक।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह इस बात को कह दें कि उर्दू को दूसरी भाषा बनाने पर इनकी सरकार सहमत है। बस इतना ही कह दें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उर्दू के बारे में चर्चा किये थे, अगर चर्चा न किये होते, तो हम लोग न कहते, मगर माननीय मंत्री जी ने उर्दू के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा किया, जिसमें उन्होंने आर्डिनेंस वगैरह की भी बात लाई। तो क्या माननीय मंत्री जी की ज्वाइंट रिस्पांसिविलिटी को सामने रखते हुये, उर्दू के बारे में स्पष्ट रूप से इस वक्त कोई घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट है। क्या इसमें उर्दू के बारे में चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

सार्वजनिक निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के लिये अनुदान मांगा गया है। उसमें वह उर्दू के बारे में कोई बात कहना चाहें, तो कह सकते हैं।

श्री अम्मार जिवी---

मान्यवर, जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी कर चुके हैं और जिसकी चर्चा भी हो चुकी है, जो अखबारों में भी आ चुका है, उससे सरकार पूरी तरह से सहमत है।

श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, वह स्पष्ट नहीं है। उसे स्पष्ट कर दीजिए।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, अम्मार रिजवी साहब मंत्री ऐसे हैं कि ये अम्मार रिजवी हैं और सरकर को इनसे उर्दू पर भाषण कराना है।

श्री अध्यक्ष---

जब तक वह नहीं बैठते हैं, तब तक आप काहें को खड़े होते हैं।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जो पिछले वर्ष इण्टरकास्ट मैरिजेज 160 हुई हैं, उनको एक-एक हजार रुपया और 15 हजार का लोन इन्टरकास्ट फ्री दिया जाता है, ताकि वह अपनी कोई इन्डस्ट्री लगा सकें। माइनारिटीज कमीशन की स्थापना की गयी है और इस सदन की माननीय सदस्या श्रीमती कुदसिया बेगम उसकी अध्यक्ष बनाई गयी हैं। इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में यह प्रयास किया जा रहा है जितने भी सेन्टिव जिले है वहां पर एक राष्ट्रीय एकीकरण अधिकारी को पोस्ट किया जाय जो तमाम लोगों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता की भावना में प्रोत्साहन दे सके। इन्टीग्रेशन आफ नेशनल इन्स्टीट्यूट अगर कोई वालन्ट्री एजेन्सी खोलना चाहे या सरकार अपने संसाधन से कर सके तो बनाये जिसमें राष्ट्रीय एकता, आपसी प्रेम और सद्भावना प्रदर्शित होती हो, रखा जाय। इस प्रकार के प्रयास किये गये हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिये और दुश्मनी को कम करने की आपस मे जो खाई है उसको कम करने के प्रयास किये गये हैं। अन्त में मैं मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों के सुझाव इस सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग पर चाहूंगा ताकि हमारे विभाग का मार्गदर्शन हो सके और फायदा हो सके।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

माननीय मंत्री जी एक बात बता दें नैनीताल जनपद में.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय विष्ट जी, आप बैठ जायं।

*श्री हरगोविन्द वर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मा0 मंत्री महोदय ने अपना भाषण काफी विस्तृत दिया और अनुदान की राशि सदन के सामने पेश किया। मान्यवर, इस संबंध में आपके माध्यम से मेरा आलोचनात्मक विचार है। मान्यवर, मंत्री जी ने जैसा बताया कि सड़क हमारे देश और प्रदेश में एक प्रमुख स्थान रखती है। यदि हम देश और प्रदेश में चाहते हैं कि प्रगति हो, हमारे गांव बढ़ें तो मार्ग का होना अति आवश्यक है और जैसा मंत्री महोदय मानते हैं कि देश में हमारा प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे पिछड़ा है।

मान्यवर, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,94,413 वर्ग मील है। प्रदेश की जनसंख्या पिछले आंकड़ों के अनुसार 11,08,85,874 है और प्रदेश में गांव 1,12,561 हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। जो मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं उनको मान्यवर, आप देखें तो साबित होगा कि इन 34–35 सालों में हमारा प्रदेश कितना ज्यादा पिछड़ा। आंकड़ों से आपको मालूम होगा, जो पेश किये गये हैं, कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक लाख आदमी के ऊपर कवल 55 किलोमीटर सड़क बनी है। इसमें राज्य मार्ग, कच्चे मार्ग, पक्के मार्ग और गलियारे आदि शामिल हैं। मान्यवर, जो राष्ट्रीय मार्ग हमारे प्रदेश में हैं वह एक लाख आदमी के लिये 2.79 किलोमीटर बने हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि प्रदेश के अन्दर इतनी थोड़ी सड़क बनाने का कार्य किया गया है। इसलिये जो मंत्री जी ने अपनी प्रगति बतायी है उस पर विचार किया जाय कि जब देश आजाद हुआ था और उसके पहले 90 साल यहां अंग्रेज रहे, तो उनके समय में 15 हजार किलोमीटर सड़क हमारे प्रदेश में थीं और उसके बाद कांग्रेस के समय में हमारे प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण हुआ है वह लगभग 64 हजार किलोमीटर बनी हैं। इसमें ढाई साल जनता पार्टी के शासन काल में अधिक सड़कों के बनाने का काम किया गया है।

गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने किया और तमाम सड़कें जनता पार्टी और लोकदल के राज में बनायी गयीं। अगर औसत निकाला

[श्री हरगोविन्द वर्मा—]

जाय तो ढाई साल के शासन के दौरान जो काम किया गया है वह इनके 20 साल के शासन में नहीं किया गया है। जिस हिसाब से सड़कें बनाने का काम यह सरकार कर रही है उस हिसाब से 200 या 400 साल सड़कें बनाने में लगेंगे तब कहीं जाकर गांव सड़कों से जुड़ पायेंगे। जो गणना इन्होंने दी है उससे साफ जाहिर होता है कि मंत्री जी इस प्रदेश को अपनी धरोहर मानते हैं, कांग्रेस पार्टी इस देश को अपनी जागीर मानती है जिसकी वजह से देश पिछड़ गया। हमारे कांग्रेस के लोगों ने इसे चरने का काम किया नोचने का काम किया और इस गरीब देश को लूटने का काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से इन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ा है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 1 लाख 12 हजार 561 गांव हैं जिसमे से केवल 6 हजार गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। इन 34 सालों मे केवल 6 हजार गांवों को जोड़ा गया है लेकिन जनता राज में लगभग 3000 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। तो जनता पार्टी के राज में जितना काम हुआ है आप खुद ही देख लें। जनता पार्टी के राज्य में और लोकदल के राज्य में हमने खाद्यान्न योजना में गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा है लेकिन उसके बाद आज यह स्थित पैदा हो गयी है कि जिन सड़कों को पटवाने का काम हमारे राज में किया गया था वही सड़कें आज इनके राज में कट और बह गयी हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि इनके राज में उन सड़कों पर एक झउआ मिट्टी नहीं पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं आप गरीबों की बात करते हैं, हरिजनों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गांवों की बात करते हैं तो यह सब आपकी धोखा देने की बातें हैं, जब तक सड़कों को गांवों तक नहीं ले जाया जायगा तब तक गरीबों की तरक्की आप नहीं कर सकते हैं। आपके 34 साल के शासन के बावजूद ही हजारों गांव ऐसे हैं जहां जाने का कोई रास्ता नहीं है।

माननीय मंत्री जी अपने इलाके में चलकर देखें यद्यपि उन्होंने पूरे प्रदेश की पूंजी को अपने महमूदाबाद में लगाने का काम किया है लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि आज उनके इलाके मे कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जो दलदल बने हुए हैं। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह स्थिति इनके स्वयं के क्षेत्र की है। जो बजट आपने पेश किया है जो भी पैसा इनको दिया जायगा वह पैसा किस काम में खर्च होगा यह मैं बता देना चाहता हूं। यह आप निश्चित मान लीजिये कि वह पैसा इस प्रदेश के डेवलपमेंट पर खर्च नहीं होगा, गांवों की तरक्की पर खर्च नहीं होगा, सेतु बनाने पर खर्च नहीं होगा, भवन निर्माण पर खर्च नहीं होगा।

मान्यवर, अमृत प्रभात में छपा है कि माननीय मंत्री जी मंत्रित्व ग्रहण करने के बाद दो बार विदेश यात्रा पर गये हैं और जब वह यहां लौटकर आये तो वहां के राजनायिकों को जो टेलीग्राम दिया है उस पर 15 हजार रुपया मंत्री जी ने खर्च किया है। मान्यवर, सेतु निर्माण का जो कार्य विदेशों में चल रहा है उसका सारा का सारा खर्च वहां पर होता है उसका कोई हिसाब उत्तर प्रदेश में इनके मुख्य कार्यालय में नहीं आता है।

यही नहीं, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके सेतु निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, हवाई जहाज से उड़ने का काम करते हैं, जब कि यह दिया हुआ है कि 2000 रु0 प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले को ही हवाई जहाज से उड़ने की सुविधा दी जायगी, लेकिन सेतु निगम के अधिकारी जब विदेश जाते हैं तो 1120 रु0 रोज भत्ता लेने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है, जहां 5–6 रु0 रोज पर गुजारा करने वाले इन्सान अपनी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन सेतु निगम के अधिकारी जब विदेश जाते हैं तो 1120 रु0 रोज भत्ता लेने का काम करते हैं। यह पैसा काहे में जायगा, भत्ते में जायगा, हवाई जहाज से उड़ने में जायगा लेकिन गांव की तरक्की में नहीं लगेगा, लेकिन एय्याशी और मक्कारी में

जायगा। मन्त्री जी जानते हैं, आज हम लोग विधान सभा में बैठे हुए हैं, हम भी जानते हैं कि कितना करप्शन है। यहां पर जो आपका रिकार्ड रूम है, उसमें कूलर लगवाये गये, कूलर लगे नहीं फर्जी बिल बने हैं और पैसा पेमेण्ट हुआ है। जो पेमेण्ट हुआ है, उसकी मेरे पास फोटो स्टेट कापी भी है। मन्त्री जी इसमें भी जांच करा लें। यह फोटोस्टेट कापी है, दो कूलर इनके रिकार्ड रूम में लगे हैं। पहला 5300 रु0 में और दूसरा 5459 रु0 का पेमेण्ट हुआ है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री के कमरे में 3 राड लगवाने के लिये 3000 रु0 का बिल लिया गया है। जब इनके आफिस के अन्दर इस तरीके का करप्शन है तो कैसे कहा जा

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

सकता है कि यह फिजूलखर्ची को रोक सकते हैं। अगर इनमें रोकने की क्षमता नहीं है, जैसा कि साफ जाहिर है, प्रदेश के अन्दर इनकी पार्टी में करप्शन एक श्रेणी का है। अभी मैं बरेली गया था, बरेली के लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं क्योंकि [× × ×] मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर यह सारी परिभाषायें इनकी क्वालिफीकेशन में आती है।

श्री उपाध्यक्ष––

मेरा ख्याल है आज से दो दिन पूर्व इस सदन का ध्यान किसी नये नियम की तरफ आकृष्ट किया गया था और वह नियम आपको याद होगा कि कोई भी चार्ज लगाने के पहले जब तक आप मुझे दे न दें चार्ज नहीं लगा सकते हैं। इस संबंध में जो कुछ आपने कहा है, वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री हरगोविन्द वर्मा––

मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं अखबार के अन्दर है, सही है, अगर इसके बाद भी आप इसको कार्यवाही का अंग न बनायें तो.....

श्री उपाध्यक्ष––

आपने जो चरित्र हत्या वाली बात कही कि फलां मन्त्री का लड़का.....

श्री हरगोविन्द वर्मा––

लेकिन मान्यवर, मैंने किसी मन्त्री का नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं नियम से बंधित हूं, जब आप उसे तोड़ेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा।

श्री हरगोविन्द वर्मा––

एक किस्सा आपको बताता हूं। एक बार कुछ मुसाफिर जा रहे थे, गर्मी के दिन थे। लू चल रही थी, वह लोग गर्मी के कारण प्यास से व्याकुल थे, पानी के लिये प्यास से मर रहे थे। तो उन्होंने वहीं पास मे एक चौतरा देखा। यह चौतरा एक मन्दिर का था। तो वो लोग मन्दिर के चौतरे पर बैठ कर कुएं से पानी निकालने लगे और सत्तू निकालकर खाने

नोटः––[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री हरगोविंद वर्मा--]

लगे। इतने में क्या हुआ कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और वहीं खड़े होकर पेशाव करने लगा। उसके पेशाब की छींटें उनके सत्तू पर भी पड़ीं। उन लोगों ने कहा कि चलो इसकी शिकायत इसके बाप से चलकर करते हैं। गांव में पहुंच गये तो देखते हैं कि लड़के का बाप छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहना बेकार है, इसको कौन सुनेगा। यहां इन्हीं बातों का लड़कों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बरेली में लड़के लड़कियों को उठाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश की सरकार यहां भ्रष्टाचार कर रही है और दिल्ली में केन्द्र की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने जो पी0 डब्लू0 डी0 एवं राष्ट्रीय एकीकरण का बजट रखा है उसके संबंध में माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे--

श्री हर गोविन्द वर्मा--

जी हां, मैं कटौती का प्रस्ताव ही रख रहा हूं और व्यापक भ्रष्टाचार को बतला रहा हूं, अभी उसी पर आ रहा हूं।

श्री मुईद अहमद--

उपाध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव पर माननीय मोहन सिंह ने इनको डिक्टेट कराकर इनको यहां प्रस्ताव रखने के लिये भेजा है, वैसे ये इसे रखने के लिये तैयार नहीं हो रहे थे। तो ये डिक्टेशन लेकर अब पी0डब्लू0 डी0 के बजट भाषण में कटौती के संबंध में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कोई सुझाव तो ये दे नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। आप इतने बुजुर्ग मेम्बर होकर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं पी0 डब्लू0 डी0 का खर्च बताना चाहता हूं। अभी-अभी लखनऊ के अन्दर ही एक अधिकारी ने जिसने 300 बोरी सीमेन्ट चुराने का काम किया है ऐशबाग स्टोर से, उसको दबा दिया गया। यही नहीं, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ परेशान होकर उनके विभाग के एक अधिकारी ने नौकरी से अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है। मान्यवर, इसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है, इसे मैं आपको दे दूंगा। यह अधिकारी श्री महेश शंकर तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, पी0 डब्लू0 डी0, उ0 प्र0 राजकीय सेवा की त्याग-पत्र की कापी है इसमें लिखा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र राजकीय सेवा से प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि शासन ने भ्रष्टाचार को प्रिय माना है।

मान्यवर, यह सीधा-सीधा चार्ज श्री तिवारी का शासन के ऊपर है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि शासन भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है, उस शासन में मैं नहीं रह सकता हूं। मान्यवर, इसको मैं आपके सामने रखता हूं।

(1 बजकर 45 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

थोड़ा व्यतिक्रम कर दिया आपने। पहले कागज दे कर पढ़ना चाहिए। पहले पढ़कर कागज आप दे रहे हैं।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पैसे का कैसे लेन-देन हो रहा है। इनके विभाग में कुछ नियम हैं, कानून हैं, उसके तहत की, अमृत प्रभात ने छापा है 25 नवम्बर का है। यह कहता है....

(हंसी एवं व्यवधान)

श्री हर देव—

चौराहे का भाषण है मान्यवर, माननीय सदस्य का।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

घटिया कार्य के बावजूद बढ़िया तरक्की पाना हो तो जमकर इनके विभाग में पैसा चलता है और इसका प्रमाण तीन अधिकारियों को सुपरसीड किया गया, सीनियर को जूनियर और जूनियर को सीनियर किया गया। मेरा कहना है कि जहां पर पैसे के आधार पर अधिकारी को तरक्की देने का काम होगा तो किस तरह से वह विभाग आगे बढ़ सकेगा।

(श्री हरिवंश सहाय ने पढ़ने के लिये चश्मा दिया।)

श्री उपाध्यक्ष—

सहाय जी का चश्मा आपको ठीक लगेगा। पढ़ लीजिये आप।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

और जिनके पास अपेक्षित योग्यतायें नहीं थीं, 5 लोगों को सर्वश्री जान, लोबो, ओम प्रकाश सिंह, हरि शंकर सिंह, के0 डी0 श्रीवास्तव को सीधे अधिशासी अभियन्ता बना दिया गया....

श्री हर देव—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह अखबार के पढ़ने की जगह नहीं है...

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा—

10 साल तक इनके यहां जो कार्य कर लेगा तभी उसकी पदोन्नति हो सकती है उसको इन्होंने तोड़ दिया और पैसे के आधार पर पदोन्नति करने का काम इनके विभाग में पूरे तौर से हो रहा है। यही नहीं, जानकारी मिली है कि 60-60 हजार तक घूस लेने का काम किया है। वह भी पेश करना चाहता हूं। इनके यहां एक अधिकारी हैं श्री महेश्वर प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में बटलर पैलेस में संत हाउसिंग सोसायटी से 3 हजार वर्ग फीट जमीन खरीदी 80 हजार में और कागज में दिखाई 40 हजार। इनके विभाग में कानून है कि जब कोई आदमी सामान खरीदेगा तो सरकार से स्वीकृति लेगा, लेकिन उसने कोई स्वीकृति नहीं ली और गवर्नमेन्ट की चोरी करने की नीयत से कि रजिस्ट्री में पैसा बच जाये, केवल 40 हजार दिखाया।

[श्री हरगोविन्द वर्मा—]

उसी के ऊपर उसके जो बिल्डिंग बनाई उसको अगर आप देखें तो ताज्जुब करेंगे। इस तरह से इनके पी0डब्लू0डी0 विभाग का सारा का सारा पैसा इनके अधिकारियों के हाथ में जा रहा है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब मंत्री जी की कुर्सी के नीचे इस तरीके का भष्टाचार पनप रहा है तो मंत्री जी का हाथ उसमें जरूर हो सकता है।

आज इतने दिन हो गये अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री जी इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। यह भ्रष्टाचार केवल लखनऊ ही नहीं बनारस और इलाहाबाद सारी जगहों पर भष्टाचार ही भष्टाचार नजर आ रहा है तो मेरा यह कहना है कि मंत्री जी इन सारी चीजों को देखें और सख्त से सख्त कार्यवाही उन अधिकारियों के खिलाफ करें। सेतु निगम की बात मैंने कहा हो सकता है कि सेतु निगम से इनको कुछ आमदनी हो लेकिन जब वह पैसा विदेश में इन के अधिकारी और कर्मचारी और स्वयं मंत्री जी विदेश यात्रा में खर्च कर देंगे तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जिन हाथों में पैसा सुरक्षित हो उन्हें पैसा दिया जाय जब इनके पास पैसा सुरक्षित है ही नहीं तो ऐसे हाथों में अनुदान न दिया जाय और पूरे तौर से कटौती की जाय।

आज गांव के अन्दर प्रगति की बात कही जाती है। हमारे मंत्री जी जब ग्राम्य विकास में थे तो गावों की तरक्की की बात करते थे। गांव की तरक्की और सारी चीजें सड़क से जुड़ी हुई हैं। आप विदेश में मकान बनायें मुल्क में मकान बनायें लेकिन जब तक गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा जायगा तब तक उत्तर प्रदेश के गांवों की तरक्की नहीं हो सकती है और आपकी रिपोर्ट के हिसाब से तो यह जाहिर होता है कि आप इस काम को नहीं कर सकत हैं। एक अधिकारी ने मुझ से कहा कि वर्मा जी एक समय वह था कि जब हमारे विभाग में 5 फीसदी कमीशन के नाम पर पैसा लिया जाता था ठेकेदारों से और उसको हम लोग जब कोई मंत्री या उच्च अधिकारी आते थे तो खर्च करते थे लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि अगर हम 25 फीसदी लेते हैं ठेकेदारों से तब भी पूरा नहीं पड़ता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं आयेगा तो जब मंत्री जी हमसे मांग करेंगे तो हम कहां स देंग इसलिए आपक विभाग में मंत्री जी क नाम पर भी पैसा लिया जा रहा है। अगर आपकी करप्शन दूर करने की नीयत है तो आप इसकी जांच करवाइये लेकिन अगर आप यह चाहते हैं केवल किसी तरीके से कुर्सी बनी रहे पैसे के बलबूते पर तो जैसा कि मैंने पहले कहा था फाइनेंस बजट के सामनं कि केवल तीन लोगों का राज्य हो गया है। एक तो अधिकारी जो कुर्सी पर बैठा है, दूसरा जो पैसे वाला गद्दी पर बैठा है और तीसरा छविराम जैसे गुन्डा और चोर।

इनके विभाग में एक ठेकेदार हैं जो राइफल की नोक पर इनके यहां से गलत बिल पास करवाता है, उसका भी नाम मैं आपको देना चाहूंगा।

इसी लखनऊ के ऐशबाग का एक ठेकेदार है। उसके बारे में चर्चा है कि उसने उसी अभियन्ता से जिसने इस्तीफा दिया है कहा कि हमसे जबरदस्ती वाउचर्स और बिल्स पर दस्तखत कराये गये और जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो रिवाल्वर दिखला कर हमसे इस्तीफा लिखवा लिया गया। इस तरह से बन्दूक की नोंक पर आपके यहां काम किया जाता है। हमारे जनपद की जो नगरपालिका है उसके अन्दर सारे के सारे जो ठेकेदार हैं वे डकैत और गुन्डे हैं और आजकल ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सारे प्रदेश में जो कल तक डकैती करते थे गुन्डई करते थे आज ठेकेदार बने हुए हैं। आपके यहां अधिकतर अधिकारी लोग चोरी करने का काम करते हैं। यही नहीं, इसी विधान सभा से लगे जो रायल होटल है वहां पर आपके विभाग ने ट्रांसपोर्ट कम्पनी बना रखा है। वहां रात में तमाम ट्रकें और बसें आकर रुकती हैं।

आपको मालूम है कि प्रदेश में 50 हजार ट्रकें हैं, 8 हजार प्राइवेट बसें हैं, 5 हजार रोडवेज की बसें हैं। प्राइवेट बसें रोज रात में रायल होटल में आकर रुकती हैं लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। वहां पर जो प्राइवेट कैन्टीन थी उसकी दूकान को वहां से हटा दिया गया। यह बुरी बात नहीं हुई, ठीक ही हुआ कि सरकारी दूकान हो गयी लेकिन बिना नोटिस दिये हुए उसे हटा दिया गया। लेकिन वहीं पर दारुलशफा में एक व्यक्ति की दकान 30 फीट की दी गयी और रायल होटल वाले को 12 फीट की दूकान दी गयी। जब इस संबंध में अधिकारी स कहा गया तो उसने बतलाया कि दारुलशफा वाला व्यक्ति तो माननीय मंत्री जी का मित्र है, तुम तो उनके मित्र नहीं हो। क्या इस तरह से शासन में मित्रता चलेगी और भाई, भतीजावाद चलेगा और नौकरशाही चलेगी ? इस तरह स आपका विभाग कैसे सड़कों को बना पायेगा। यह सही है कि मंत्री जी हर तरह स सक्षम हैं, बड़े तिकड़म से काम करते हैं, बड़े रंगीले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं ह लकिन इसके बावजूद चाहे आप कहीं भी जायं इनके पूरे विभाग में नीच से ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। जैसे रसगुल्ले में से रस ही रस दाबने पर निकलता है उसी तरह से इनके विभाग में रस ही रस है जिसे विभाग अलग नहीं कर सकता है। यह खाऊ-पियाऊ विभाग है, इसके अलावा और कुछ यहां नहीं होता है।

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज क्षेत्र में एक लकड़ी के पुल की मरम्मत क लिये 52 स्लीपर लाये गये थे। उनमें से 32 स्लीपर इस्तेमाल हुए और बाकी स्लीपर वहां आफिस में रख दिये गये। रात में जे0ई0 श्री आजमी अपने आदमियों से उनको उठवाने का काम करने लग। लोकदल के विधायक ने और लोकदल के कार्यकर्त्ताओं ने उनको वहां पकड़ा लेकिन आज तक न तो उस जे0ई0 का ट्रांसफर हुआ और न उसे सस्पेंड ही किया गया।

एक और विचित्र बात यह है देवरिया में 1977 में एक सड़क बनी दिखला दी गयी जबकि वह सड़क बनी नहीं, ज्यों की त्यों रही और कागज पर लिखकर आ गया कि वह सड़क पक्की बन गई। इस पर कार्यवाही हुई। विभागीय जांच और सी0 आई 0डी0 जांच दोनों हुई। विभागीय जांच में लिख कर दे दिया कि सड़क बन गई है। सी0 आई0डी0 की जांच में यह कहा गया कि सड़क नहीं बनी है। नतीजा यह निकला सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट को जब उस अधिकारी को मालूम हुआ तो उस अधिकारी का हार्ट फेल हो गया। वह खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सस्पेन्ड किया गया। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि सड़क पक्की बन गयी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा कहना यह है कि मंत्री जी या और जो इस विभाग में अधिकारी हैं पूरी तौर से हर बात को छुपाने और करप्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब तक इस चीज को खत्म नहीं किया जायगा तब तक इस विभाग की तरक्की नहीं हो सकती।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि सही मायने में विभाग को ईमानदारी से चलाना है तो जैसा कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि चाणक्य ने पत्ते की गद्दी पर बैठकर देश को बनाने का काम किया मंत्री जी हम कम से कम खर्च में अपनी जिन्दगी गुजारें, कम से कम खर्च में अपने समय को बितायें और प्रदेश को बनायें। विभाग को जितना पैसा विदेशों में पुल निर्माण से, मकान निर्माण से और तरीके से मिलता है वह पैसा प्रदेश की गरीब जनता को तरक्की देने के लिये, गांवों को उठाने के लिए, उनकी तरक्की में लगायें। दृढ़ संकल्प से ही हम गांवों की तरक्की का काम कर सकेंगे जैसा कि लोकदल ने किया था कि

[श्री हरगोविंद वर्मा--]

हम सबसे प्रथम यह काम करेंगे कि गांवों की गरीबी दूर करेंगे' गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। अपन ढाई साल क समय में लोकदल, जनता पाटी की सरकार न गांवों में विकास का काम किया। मंत्री जी ने स्वयं विभिन्न इलाकों में देखा होगा और पता चला होगा कि जो सड़क वहां पर बनी हैं चाहे कच्ची रूप में हो चाहे पक्की हो वह सारी सड़कें लोकदल जनता पार्टी की हैं। मेरा कहना यह है कि जब तक इन विचारों को ग्रहण न किया जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता। जब तक तबादलों को बंद नहीं किया जायगा। यहां पर एक आदमी ऐसा है जो रिटायर हो गया। आपका कानून है कि रिटायर होने के बाद एक्सटेन्शन नहीं दिया जायगा। लेकिन दो बार एक्सटेन्शन उनको दिया गया।

(लाल बत्ती जलने पर)

पांच मिनट और चाहूंगा। एक्सटेन्शन दो बार दिया गया। क्या मतलब होते हैं एक्सटेन्शन के। एक्सटेन्शन के यही मतलब होते हैं कि उसके द्वारा करप्शन कराया जा रहा है। या तो ये अधिकारी पैसा लेते हैं या मंत्रि मण्डल पैसा लेता है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से इस मंत्रिमंडल ने जैसे कि सरेन्डर छबि राम के सामने कर दिया है, पूंजी-पतियों के सामने कर दिया है उसी तरह से अधिकारियों के सामने कर दिया है.....

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सम्मानित सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा व्यक्ति है उसका नाम बतायें जिसको दो बार.....

श्री हर गोविन्द वर्मा--

तिवारी जी हैं। त्रिभुवन प्रसाद तिवारी। यहीं सेक्रेटरिएट में हैं।'

मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। इसलिए मैं जल्दी चाहता हूं। अपनी बात खत्म कर समय से बाहर आपका समय न लूं। एक सुझाव है सड़कों के बारे में। यह हमारा सौभाग्य है कि मंत्री जी हमारे जिले के हैं। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि महमूदाबाद की तरक्की हो। जहां आप का सीतापुर, गोरखपुर और देवरिया आदि जिलों की तरफ आपका ध्यान है वहीं हम चाहेगें कि पूरे प्रदेश की तरफ भी आप निगाह रखें। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया-गोरखपुर को जोड़ने वाली राप्ती नदी के ऊपर कपरवार घाट पर जहां पीपे का पुल बना हुआ है उसको पक्का बनवा दिया जाय.....

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह पर्चा जहां से मिला है उसका स्रोत बता दें तो मैं उसके बारे में बता दूंगा।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लहरपुर से बिसवां रोड पर तथा जीतामऊ तालगांव परसेन्डी कसरेला रोड एवं जीतामऊ से अंगरोजा बेनी सराय और लहरपुर तम्बौर रोड जो हैं उसको पक्का किया जाय। इसी तरह से जो हमारे जिले के अन्दर कच्ची सड़कें हैं जिनमें खड़ंजे लगे हुए हैं उनमें डामर नहीं डलवाया गया है जिससे कि वे सड़कें खराब हो गई हैं। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इन खड़ंजे वाली सड़कों पर डामर डलवाने की व्यवस्था करा दें ताकि सड़कें मजबूत हो सकें। इसके अतिरिक्त गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उन पर

आप पहले काम शुरू करवा दें और उसके लिये दृढ़ संकल्पी बनें। आपने कहा कि सन् 1990 तक यह कार्य कर सकेंगे। मैं कहता हूं कि आपका यह ऐसा विभाग है जो कि सन् 2090 तक भी इस कार्य को पूरा करने वाला नहीं है। इस विभाग का सारा पैसा करप्शन में चला जाता है। इसलिये इसको आप रोकें। मैं समझता हूं कि मैंने जिन मुद्दों को उठाया है माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। तभी प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर सत्ता पक्ष की ओर से सर्व प्रथम बोलने का अवसर दिया, इसलिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, इस प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण, राज्य सम्पत्ति एवं राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री ने जो परिश्रम, प्रयासों और उपलब्धियों से भरा हुआ बजट इस माननीय सदन में रखा है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी हमारे माननीय हरगोविन्द वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने महमूदाबाद से लेकर लहरपुर तक की अपनी मन की भडांस निकाल दी लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि यह उनकी कहीं नूरा-मुस्ती तो नहीं है। मैं माननीय हरगोविन्द वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपके माध्यम से मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री कितने दूरदर्शी हैं, यानी प्रतिभा की परख हर व्यक्ति को नहीं हुआ करती है.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी, जरा ऐसा बोले कि मैं भी सुन पाऊं मैं आपके भाषण का रसास्वादन नहीं कर पा रहा हूं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर यह सारी व्यवस्था तो आपकी ही है, बाकी यह शरीर आपको अर्पित है।

श्री उपाध्यक्ष —

आपका शरीर मुझे अर्पित है पर ऐसी व्यवस्था करें कि मैं सुन पाऊं जरा माइक पर जोर से बोलें।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, अब तो सुनाई पड़ रहा होगा। तो थोड़ा मैं विषयांतर हो गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतिभा का वर्णन कर रहा था। यानी हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी जो हैं वह शिक्षा जगत की सुकुमारता को सजाने और संवारने वाले थे और ग्राम्य विकास की क्यारियों को लहराने वाले थे लेकिन वाह रे मुख्य मंत्री जी मेरा रोम-रोम आपको बधाई देता है कि इस सजीले और सलोने मंत्री को काली कंकरीट और डामर की सड़कों में रोलर लेकर दौड़ा दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी इसमें बधाई की बात यह है कि रौलर का सफल संचालन भी हमारे माननीय मंत्री जी ने किया ह हमारे विरोधी पक्ष के साथी धीरज रखें मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं गंभीरता से एक वर्ष की प्रतीक्षा करें और अगले बजट में उन्हें इसका परिणाम मिलेगा (हंसी) इसकी उपलब्धियां आपको देखने को मिलेंगी।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

मान्यवर, सर्वविदित है कि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ही सेतु निगम भी आता ह और निर्माण निगम भी आता है (व्यवधान) क्या कानपुर में निर्माण निगम ने कुछ नहीं बनाया है माननीय मंत्री जी यह बड़ी नाइंसाफी है वहां भी एक आध पुल बनवा दें। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जन्मे सेतु निगम ने आज प्रदेश का ही नाम ऊंचा नहीं किया बल्कि पूरे देश का विदेशों में नाम ऊंचा किया है। मैं उस विभाग और उस विभाग के माननीय मंत्री को हृदय से बधाई देता हूं।

मान्यवर, निर्माण निगम की जो स्थापना हुई वह भी उत्तर प्रदेश में हुई है उसके तहत उत्तर प्रदेश ने बहुत उपलब्धियां की हैं जो ठेकेदारी प्रथा थी वह समाप्त हुई हमारे टैकनिकल विशेषज्ञों के सम्मान का प्रदर्शन हुआ और एक विश्वास जमा कि निर्माण निगम के द्वारा कि हम इस प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं। उस आशा में मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि जरा इस रौलर को कसे रहे कि कही इस नाम पर बट्टा न लगे।

अब मैं आता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर। मेरा अपना विश्वास है मान्यवर, अगर इस धरती पर राजा राम भी उतर आये तब भी इस लोक निर्माण-सार्वजनिक निर्माण विभाग का सुधार नही हो सकता है। यह आलोचना का विषय नहीं है, इसमे न आप हर्ष समझे न विषाद समझे बल्कि मूल भूत बातों पर जायं। परन्तु व्यक्ति इतना प्रयत्नशील होता है कि वह धरती से चन्द्रमा तक पहुंच गया, अपने प्रयत्नों से पहुंचा है। बुद्धजीवी जगत से हमारे मंत्री जी आए हुए हैं, वह हर कलाओं में पारंगत हैं। मुझे विश्वास है कि अपने बिचार से वह इस विभाग में भी सुधार करने का प्रयास करेगें। मान्यवर यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, इस समय सार्वजनिक निर्माण नहीं बल्कि नेता गिरी का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सम्पूर्ण सदन से क्षमा चाहता हूं-एक बात कह रहा हूं, धैर्य से सुनिये, मेरा मन उससे बहुत दुखी था। इसी समय माननीय मंत्री जी के अधीन एक अधिकारी हैं श्री ओंकार प्रसाद वह विशेष सचिव हैं। यह पहले मुख्य अभियन्ता बनना चाहते थे (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

अफसरों की क्या बात है?

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

आप काशीनाथ जी जरा धीरज से सुनिये। आप मंत्री है, मैं पैदल हूं, फिर भी मेरी बात सुनिये। शिक्षा में मैं आपसे उन्नीस नहीं हूं। आप अध्यक्ष रहे हैं तो मैं डबल अध्यक्ष रहा हूँ। किसी के जज्बातों को आप नहीं रोक सकते हैं। मान्यवर, यह मुख्य अभियन्ता बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य की रेखाओं, ललाट की रेखाओं को कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा, परन्तु उनका ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ अपनी प्रतिभा पर विश्वास नही हुआ। मान्यवर, जिस समय सागर मंथन हो रहा था तो किसी को रमा मिली किसी को सुधा मिली और शंकर को केवल विष मिला। इसी से कवि बोल उठा था-"ओ नीलकंठ सन्तोष करो था लिखा गरल पान तुम्हें। उसकी भी एक महत्ता होती है। ओमकार प्रसाद जी ने धरती और आकाश एक कर दिया। जो इस समय के मुख्य अभियन्ता हैं जो पहले विभाग के मंत्री थे जगदीश प्रसाद जी और मुख्य मंत्री पर उन्होंने कोई ऐसा चार्ज नहीं था जो न लगाया हो। इस पर मैंने मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री को लिखा प्रशासन में हर जगह मेरे पत्र मौजूद है कि उसकी जांच कराई जाय लेकिन उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई।

मैं मंत्री जी से कहता हूं कि वह इस अधिकारी से साफ साफ कह दें कि उसे नेतागिरी का ज्यादा शौक है तो वह नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े तब फिर हमारे मंत्रियों और विधायकों के बारे में कोई आलोचना करे, वरना उसको कोई अधिकार नहीं है। किसी भी

देश को बनाने के लिये अनुशासन का बहुत महत्व होता है, अगर अनुशासन नहीं रहा विभाग में, अगर कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई, तो कोई देश और प्रदेश नहीं चल सकता है। आज कर्मचारियों ने रवैया बना लिया है कि मैं जैसा चाहूंगा देश चलाऊंगा, जैसे चाहेंगे विभाग को चलायेंगे। मित्रों याद रखें वैसे नहीं चलेगा। विरोध पक्ष की जो बात है वह है, लेकिन मैं सत्तापक्ष की ओर से विश्वासपूर्वक कहता हूं और सजगतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से, मान्यवर, मैं आपसे जरा समय की भी उदारता चाहूंगा, थोड़े और समय की आपसे याचना करूंगा। मान्यवर, पिछले साल मैं बजट पर नहीं बोला था....

श्री उपाध्यक्ष––

जो विद्यार्थी घड़ी देखता रहता है वह उत्तर नहीं लिख पाता है, आप उत्तर लिखते रहिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

मान्यवर, इस उदारता के लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, मैं नकलची नहीं रहा हूं। सब हवाई उड़ान उड़ाता रहा हूं और आपको देखकर ही प्रेरणा लेता हूं।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि मैं पिछले साल इस विभाग के बजट पर नहीं बोला था और उसके कुछ कारण थे कि इनको कुछ मौका दूं ताकि ये सुधरें लेकिन आज कुछ शब्द आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा डिवीजन फैजाबाद है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर एक श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता थे वे इतने प्रभावी व्यक्ति हैं कि आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है। कितने भूतपूर्व मंत्री उसके तबादले को रुकवाने में लग गये लेकिन मैं अपने प्यारे मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सारे मंत्रियों के प्रभाव को न मान कर एक साथी की बात को मानकर उनका तबादला कर दिया। इसलिये फिर बधाई के पात्र हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और संपूर्ण सदन जानता है कि जिस व्यवस्था में हम और आप जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, उसके अन्दर तबादला ही हनुमान का समुन्दर लांघने के बराबर है। आप देख लें कि विधायक अगर एक थानेदार का तबादला चाहता है, वह नहीं होता है और वह थाने में बैठे मूंछे मरोड़ता रहता है, उसका तबादला नहीं होता है।

दूसरी बात मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस दिन इस विभाग में वे ठेकेदारी को खत्म कर देंगे, उसी दिन विभाग में गुन्डागर्दी खत्म हो जायेगी। आज इस प्रदेश में जितने भ्रष्ट ठेकेदार हैं, वे ही आपके विभाग को चला रहे हैं। एक श्री स्वामीनाथ नाम के व्यक्ति हैं। वे बाराबंकी में दाने चबाते थे लेकिन लखनऊ में उनकी हैसियत कई लाख रुपये की है। वही ओमकार प्रसाद को गोद में लिये हुए घूमा करते हैं और कहते हैं कि इस मंत्री के खिलाफ इन्क्वायरी कराइये, इस मंत्री के खिलाफ कराइये। मान्यवर, बाराबंकी में 2 डिवीजन्स हैं वहां के अधिशासी अभियन्ता लखनऊ के छंटे गुन्डों को ले जाकर वहां पर ठेकेदारी करवाते हैं ताकि कोई उनके खिलाफ बोल न सके। आप इसको तभी रोक पायेंगे जब आप इस सदन के सम्मानित सदस्यों को विश्वास में लें

[श्री श्याम लाल बाजपेयी ---]

और सदस्यों की एक समिति बनायें या आपकी जो कमेटियां हैं उनमें अगर उस क्षेत्र के विधायक भी होंगे तो अधिकारी लोग बहुत कुछ डरेंगे भी और कुछ आंखें खोल कर काम करेंगे। जहां पर आपके टेक्नीकल एक्सपर्टस होते हैं, उनको अपने साथ लेकर तो दौरा करते हैं लेकिन अगर संबंधित विधायक भी हों तो ज्यादा कारगर तरीके से चीजें साबित होंगी।

मान्यवर, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसकी सफलता और असफलता हमारे इस सार्वजनिक निर्माण विभाग पर निर्भर करती है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने राज्य के इस विभाग को संभाला है और इसको आगे बढ़ाने का दम भरा है, वे कृपया इन अधिकारियों की लगाम को भी हाथ में रखें।

शहरों के विकास पर जो धन आप खर्च करने जा रहे हैं और कर रहे हैं अगर उसे ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में खर्च करें तो महात्मा गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी वह जल्दी साकार हो सकेगी।

माननीय मंत्री जी के अधीन राज्य सम्पत्ति विभाग भी है और राज्य सम्पत्ति विभाग के राज्य सम्पत्ति अधिकारी पिछले 11-12 सालों से वही चले आ रहे हैं। उस पद पर वही आज भी आरूढ़ हैं। मान्यवर, जब रावण का राज्य था तब भी मन्दोदरी रानी थी और जब विभीषण का राज्य हुआ तब भी वही रानी थी, इसी प्रकार पता नहीं कौन सी कला इन राज्य सम्पत्ति अधिकारी में है जो यह नहीं हट पाते। आज तक जो भी इस विभाग के मंत्री रहे वे इन्हें नहीं बदल सके। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज सम्मानित सदस्यों की तो कोई हैसियत नहीं है, अच्छे से अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर की भी आज यह हिम्मत नहीं है कि वह उन राज्य सम्पत्ति अधिकारी को कोई आदेश दे सकें। मैं कहता हूं कि ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति यदि आपको इतना ही प्रिय है तो उसको उत्तर प्रदेश से हटा दीजिये, चाहे किसी भी प्रदेश का आप उसे गवर्नर बना दें, हमें उसमें आपत्ति नहीं होगी, मगर यहां से मेहरबानी करके हटा लें।

मान्यवर, इस सचिवालय और इस सभा मण्डप के रख रखाव पर लाखों रुपया व्यय किया जाता है। मगर अगर आप इसी सभा मंडप के ऊपर जाकर देखें तो आपको 4 ट्रक कबूतरों की बीट दिखाई पड़ेगी। यह रख रखाव का नमूना है। 4 पेटियां बल्व और 4 पेटी ट्यूब लाइट हर माह जवाहर भवन से यहां सचिवालय के लिये आते हैं और यहां सचिवालय में केवल एक-एक पेटी आ पाती हैं, 3-3 पेटी रास्ते में ही गायब हो जाती हैं। मान्यवर, इसी पावन मन्दिर में, सदन में, आप देखें कि यह जो पंखे लटके हुए हैं यह पीतल की जंजीरों से लटके हुए दिखायी देंगे। मय पीतल की जंजीरों के कई पंखे गायब हो गये। मैं कहता हूं कि आपके जो अधिकारी हैं, ए0 पी0 सिंह है, जी0 पी0 श्रीवास्तव हैं या और जो महानुभाव हैं, जरा आप इनकी गुप्तचर विभाग से जांच तो करवाइयें, आपको सारी गड़बड़ घुटाले का पता चल जायेगा। एक अरोड़ा नाम के इंजीनियर हैं, आलमबाग में कई लाख रुपये की उन्होंने कोठी खड़ी कर ली है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश निवास और उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में, के बारे में मैंने सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के समय कुछ उल्लेख किया था। वहां की प्रबन्धक एक अभद्र श्रीमती मीरा कुमार हैं। उनको आपने प्रबन्ध अधिकारी बना दिया है। जो काम पहले एक प्रबन्ध अधिकारी करता था आज इनके अन्तर्गत कई व्यक्ति मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर बना कर रख दिये गये हैं। आप शैतान की आंख की तरह से स्टाफ को इस तरह से बढ़ाते जायेंगे तो आपके विभाग की कार्यकुशलता खत्म हो जायेगी।

मान्यवर, पहले एक आयुक्त हुआ करता था पहले काम एक आदमी चलाता था, अब मैनेजर सहायक मैनेजर हो गये, देशराज सिंह, आयुक्त , एच0पी0 शर्मा, सहायक आयुक्त और एक सहगल हैं। तीनों के नीचे एक-एक आदमी लगा हुआ है। एक-एक नौकर लगा हुआ है और एक-एक गाड़ी लगी हुई है। विधायक जाता है, तो उससे कहते हो कि 12 रुपया दो और आपके अधिकारी की ऐयाशी और रंगरेलियों में उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई का पैसा दरिया की तरह बहता है। मान्यवर, यह जो नियम बनाया है, यह बिलकुल दोषपूर्ण है और वहां पर नो-प्राफिट और नो लास पर खाने की व्यवस्था यू0 पी0 निवास में की गयी है। वह साढ़े तीन रुपये का दाम खानें का लेते हैं और बाहर भी मिलता है साढ़े तीन रुपये में, जब कि उसमें लाखों रुपया रख-रखाव में, उस कैन्टीन में खर्च हुआ है। सारा खर्च सरकारी है। उसके बावजूद भी साढ़े 3 रुपया वह खाने का दाम लेते हैं। एक मौलाना साहब, जिनका नाम हफीज था, उन्होंने बड़ी सेवा की हम माननीय विधायकों की।

मान्यवर, प्रबन्ध अधिकारियों का लूटने के लिये ऐसी व्यवस्था कर दी। आप इस पर पुनर्विचार करें। अब मान्यवर, जो हमारे माननीय जगदीश प्रसाद जी हैं, उन्होंने मेरे क्षेत्र को सड़कें दी थीं, उसका पैसा 3 फरवरी को स्वीकृत होकर बाराबंकी को पहुंचा है और तब पहुंचा है , जब मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय मुख्य अभियंता जी को पत्र लिखा, कारण यह है कि जो अधीक्षण अभियंता गया है वह श्री वी0 के0 श्रीवास्तव की आज्ञा का पालन करता है, वह कहता है कि माननीय बाजपेयी के क्षेत्र में काम नहीं होने दूंगा। मान्यवर, लखनऊ–सुल्तानपुर राज मार्ग पर सड़क चौड़ा करने वाला काम स्वीकृत है जितना भाग लखनऊ में आता है उसमें काम शुरु है जितना भाग सुल्तानपुर में आता है उसमें काम शुरु हैं परन्तु जितना भाग बाराबंकी का जितना क्षेत्र हैदरगढ़ में आता है, उस पर काम नहीं शुरु हो पाया। इस समय ए0 एन0 अग्रवाल आये हैं, वह भी विरोध कर रहे हैं। मुझे संरक्षण आप देंगे या माननीय मंत्री जी देंगे। मेरा टूटा-फूटा क्षेत्र हैदरगढ़ है। मान्यवर, आजादी के बाद में तीसरा कांग्रेसी विधायक है जो जीतकर वहां से आये हैं। बाबा उमा शंकर मिश्र, श्रीमती बेगम हबीबउल्ला, सेवक श्यामलाल चुनकर आये हैं।

अब मान्यवर, पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास के नाम पर मेरी झोली में तो कुछ है नहीं। अफसर मुझसे नाराज रहता है और जितने साहब लोग हैं वह भी नाराज ही रहते हैं। तो ऐसी हालत में आपसे मैं प्रार्थना करूंगा या जो मेरे सज्जन दोस्त हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक मकनपुर, मौलावाद, त्रिवेदीगंज, ब्लाक छदरौली, मंझूपुर, परेवां होते हुये तीन जिलों को मिलाती है। यह मार्ग ऐसा है कि जनता शासन में स्वीकृत हुआ था, 10 किलोमीटर बना और 6 किलोमीटर अपंग पड़ा हुआ है। सुबेहा, सुलेमानपुर, छोटा मार्ग है , उसमें भी मेरी बात रख ली। चौधरियों का वह गांव है। सुबेहा, शरीफाबाद, चकौरा होते हुए मार्ग डामर रोड बनना है। कादीपुर, मलौली, मिनौहा मार्ग सिद्धौर ब्लाक मेरे क्षेत्र में तीन ब्लाक आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय बाजपेयी जी, यह पूरी लिस्ट इनको चैम्बर में दे दीजियेगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मेरा गांव, शरीफाबाद है, मैं मसौली क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरे जिले के विधायक माननीय रिजवान साहब हैं। लेकिन जिस गांव में आदमी पलता है जन्म लेता है, उसके प्रति भी कर्तव्य होता है, मगर मेरे गांव की रेठ नदी का पुल पड़ा हुआ है। तीन बार प्रश्न कर चुका हूं मगर अतारांकित लगता है, तारांकित लगता ही नहीं है। मान्यवर, ये कहते हैं कि वित्त संसाधनों से पैसा कर्जा मांगा था, वह नहीं मिला। इसलिये बनाते ही नहीं यह पुल माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने स्वीकृत किया था। माननीय मंत्री जी, इस पुल को सीमेंट का न सही, तो पीपे का या नल वाला पुल बनाने की तो कृपा करेंगे। अशर-फियों की लूट में कोयले पर छाप। मान्यवर, सीमेंट का न बन सका तो पीपे का बना दें। बल्लियों का बना दें। इन शब्दों के साथ मैं मनभावन मंत्री जी द्वारा रखे बजट का खुले मन से समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने 2 अरब रुपये का बजट मांगा है और 2 बातों को आधार बनाकर मांगा है। ब्रिज कारपोरेशन के काम का जो एवार्ड मिला, जिसकी आज सुबह रेडियों पर घोषणा हुई और जिसको माननीय मंत्री जी दुहाई दे रहे हैं। मै जानना चाहता हूं कि उस ब्रिज कारपोरेशन को जो एवार्ड मिला उसमें आपका क्या है। उसमें दुआ दीजिये गंगा और जमुना को और बीच में सरस्वती भी है जिनसे यहां के इंजीनियरों को जिस जलवायु के कारण दिमाग मिला है कि उन्होंने डिजाइन के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपने जो नाम ईरान, लीबिया और ईराक का गिनाया जो काम वहां हुआ है उसमें आपका क्या है। जो कानून वहां पर है उस कानून के खौफ के बदले स वह काम कर रहे हैं। वहां पर चोरी की सजा 6 महीने की नहीं होती बल्कि वहां पर हाथ काट दिया जाता है।

मैं चाहता हूं कि जो ब्रिज कारपोरेशन को एशियाटिक एवार्ड मिला है आपको दुनिया का एवार्ड मिल जाय लेकिन जो सीमेंट और गिट्टी की चोरी होती है उसको आप नहीं रोक पायेंगे यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी बात सड़कों की है। 63 हजार 663 किलोमीटर सड़क बनी। माननीय मंत्री जी आप सड़क चाहे जितना बना लें लेकिन पिछले 5 वर्ष का एक्सीडेन्ट होने का आंकड़ा उठाकर देख लें कि कितने आदमियों का, बसों का, बैलगाड़ियों का ऐक्सीडेंन्ट हुआ है रोड चौड़ा न होने के कारण, सड़क के बगल धूल होने के कारण पटरियों की ईटों के उखड़ जाने के कारण। यह आप के पी0 डब्लू0 डी0 के कारण हुये है। अगर आप ज्यादा नहीं 5 साल के ऐक्सीडेन्ट के आंकड़े देख लें तो इस विभाग की सारी कलई खुलकर सामने आ जायेगी कि आपके वजह से कितनें ऐक्सीडेन्ट हुये हैं। श्रीमन्, अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद यू0 पी0 कांग्रेसी सरकार बनी तो सबसे बड़ा रेबोलूशनरी काम हुआ जमींदारी एबोलूशन। जमींदारों को समाप्त किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो आपकी नेता हैं, यह काम सरदार पटेल के जमाने में हुआ था। उसके बाद प्रीवी पर्सेज को आपके नेता ने समाप्त किया, उनसे आप सबक लें।

मान्यवर, जैसा श्री श्यामलाल बाजपेयी ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के जो केयर टेकर्स हैं, विधायक निवासों के वह चाहे दारुलशफा का ए ब्लाक या बी ब्लाक हो और चाहे रायल होटल हो, उनसे यदि विधायकों को आप मुक्ति दिला दें तो आपका एहसान इस विधान सभा के माननीय सदस्यों पर होगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन केयरटेकरों में रियासतें समाप्त होने के बाद आज हर केयर टेकर की जो शान शौकत है वह किसी भी नवाब और रियासत से कम नहीं है। आप उनको कभी जाकर देखें तो कलई सामने आयेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप उनको क्यों नहीं हटा पाते हैं। आपके कलकत्ता और बम्बई में हाउसेज हैं, इसलिये उनको क्यों वहां नहीं भेज पाते हैं। जो यहां बैठकर काम करते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाय तो शर्म से आपकी गरदन झुक जायेगी। इसलिये विधायकों को उनसे मुक्ति दिला दें जिससे विधायक आज अपनी हैसियत समझ सके कि वह भी प्रतिनिधि हैं। आज विधायकों का वह सौदा करते हैं और आप भी उसमें भागीदार होते हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आप इसमें कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करें। मान्यवर, 3 लाख रुपये होटलों में आपने दे दिया लेकिन वहां जाकर देखें कि कितना वहां खर्च हुआ है और कितना लोग खा गये। उनको आपने कितनी कितनी जगह दिया है किन्तु विधायकों के बैठने के लिये जगह नहीं है, वह चाय बैठकर नहीं पी सकते हैं और आपने कहा कि सब को रिहीबिलीटेट कर दिया, इसलिये जाकर इसको आप देखें।

मान्यवर, आप पहाड़ी क्षेत्र में जांय और वहां देखें कि कितनी पहाड़ी सड़कों के किनारे चाहे वह अलकनन्दा हो या राम गंगा के किनारे हो या कोसी नदी के किनारे हो वहां जो सड़कें जाती हैं उनके किनारे कहीं रोक नहीं लगायी है जिससे बसें और ट्रकें खड्ड में गिरती हैं, यदि उनके जरा से भी ब्रेक फेल हो जांय तो वह नदी में गिर जांय, जिनको आप जाकर देखें कि यह किसकी नालायकी की वजह से हुआ है। यह पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियरों के कारण हुआ है, यह उनकी जिम्मेंदारी है।

मान्यवर, आपने नेशनल इंटीग्रेशन की बात कही और आपने दोहाई दिया कि 19 तारीख से आपने नेशनल इंटीग्रेशन वीक मनाया, जो अच्छा था। 19 नवम्बर की तारीख थी। यह 19 नवम्बर क्यों रखा गया। इसलिये रखा कि उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिन था। वह दिन नेशनल इंटीग्रेशन के लिये रखा। मान्यवर, 18 नवम्बर को दिवली कांड हुआ जिसमें 24 हरिजनों का खून आपने पेश किया जन्म दिन पर। इस प्रदेश के कमजोर वर्ग हरिजनों के खून को थाली में आपने पेंश किया। तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। फिर उन हरिजनों के लिये जो एसेम्बली में रिजाल्यूशन आया दो तो आंसू यह नहीं बहाये और उनके बारे में चिन्ता नहीं व्यक्त किया और विचार की यह जरूरत नहीं समझी चूंकि आप उनके बारे में बड़े चिन्तित और हमदर्द हैं इसलिये चिन्ता करने की जरूरत नहीं समझी। मान्यवर, आप नेशनल इंटीग्रेशन की बात बड़ी करते हैं लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर सोसाइटी बैठने के लिये दफ्तर चाहती है, जिनका इस देश में प्रमुख रोल रहा है नेशनल इंटीग्रेशन में वह किसी से छिपा नहीं है। आप चाहते हैं लेकिन चूंकि आपका स्टेट अफसर और आपका केयर टेकर नहीं चाहता इसलिये आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बैठने के लिये उनको दफ्तर दे दें। आपने कहा है कि बहुत गुडविल क्रियेट हो गयी है नेशनल इंटीग्रेशन की वजह से। नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा गीत और गाना गाया जाने लगा है मुरादाबाद के वाकयात के बाद।

मैं पूंछना चाहता हूं कि जो नेशनल इंटीग्रेशन कांउंसिल की श्रीनगर की रिकमेंडेशंस हैं उनको किसी को आपने कार आमद किया है। जो काउंसिल नेशनल लेविल पर बनायी गयी थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनायी थी मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या उस काउंसिल ने जो रिकमेंडेशंस की थीं उनको कार्यान्वित किया गया है। उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है और आप गुडविल की बात करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि मुरादाबाद के अन्दर जो अल्पसंख्यकों का एरिया है उस एरिये की डेढ़ साल से सफाई नहीं हुयी है। मुरादाबाद में वह जानवर जिसकी वजह से 13 अगस्त, 80 को इतना सारा फसादात हो

[श्री रियासत हुसैन--]

गया आज जगह जगह पर वही जानवर आजादी के साथ घूमते फिर रहें हैं। वहां कदली सराय में केवल 2 दूकानें इस जानवर के गोश्त की थीं लेकिन आज गली कूचों में 24 दूकानें हो गयीं है। जब हर महीने के 8 तारीख को सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है तो म्यूनिसिपल बोर्ड के दफ्तर के बरामदे में बैठकर उसका गोश्त बेचा जाता है और आप गुड-विल की बात करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब यह चीजें होंगी तो कैसे गुडविल क्रियेट होगी।

आपकी प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा मुख्य मंत्री ने, गृहमंत्री ने एश्योरेंस दिया है लेकिन आजतक मस्जिद चार चांद और मस्जिद जरवाली मुरादाबाद में रेस्टोर नहीं हो पायी हैं। और आप सोच रहे हैं कि गुडविल क्रियेट हो गयी है। किस आधार पर आप कहते हैं कि गुडविल क्रियेट हो गयी है। मजबूरी कुछ भी करा दे वह बात दूसरी है। जिस शहर में चार पांच महीने कर्फ्यू लगा हो तो चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो या सिक्ख या ईसाई हो पेट की आग का मुकाबला करने की ताकत नहीं है जब काम होता है तो न कोई हिन्दू न कोई मुसलमान और न कोई सिक्ख न कोई ईसाई है लेकिन 10 घंटे के बाद जब पेट का काम पूरा हो जाता है तो मुरादाबाद का हिन्दू हिन्दू है और मुसलमान मुसलमान है। आपका नेशनल इंटीग्रेशन बिल्कुल नाकामयाब हो गया है। मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था और जावेद अली साहब ने एलान कर दिया कि 1500 मुकदमें वह चाहे झूठे हों या सच्चे हों वापस कर लिये जायेंगे लेकिन मुकदमें अभी तक वापस नहीं हुये हैं। हो गये हों तो बतला दें कि इतने मुकदमें वापस हो गये हैं।

हाजी अबरार जैसे आदमी पर 8 घंटे में 23 मुकदमें पुलिस वालों ने कायम किये। 302/436 वगैरह वगैरह सारी ताजीरात हिंद खत्मक करके 23 मुकदमें लगाये। पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी लेकिन इस बेचारे की आंखें खराब हैं, आंखों का मरीज है। उसका आपरेशन डाक्टर भार्गव ने किया है और उसके खिलाफ 23 झूठे मुकदमें हैं। तो यह आपकी गुडविल है। अब रही करप्शन की बात, आप मेरे मजहब के हैं जिसमें किसी की हकलतफी करना जुर्म है। आज रिश्वत रिश्वत नहीं रही। रिश्वत वह कहलाती है जिसमें मुझे मालूम न हो कि मुझे क्या मिलने वाला है वह रिश्वत कहलाती है। आज आपके जूनियर इंजीनियर से लगाकर चीफ इंजीनियर तक मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बजट आप पास करा रहे हैं तो उनके यह हिसाब बन गया होगा कि इतना परसेन्ट चीफ इन्जीनियर के हिस्से में आयगा, इतना परसेन्ट सुपरिण्टेण्डिग इंजिनियर के हिस्से मे आयेगा और इतना परसेन्ट जूनियर इंजीनियर के हिस्से में आयेगा। फिर यह रिश्वत कहां रही, यह तो मालूम हो गया कि साल भर के अन्दर इतना परसेण्टेज मिलना है, यह तो उनका हक हो गया। हक के अन्दर दखल देना हर धर्म में पाप है, हमारे यहां तो बहुत बड़ा महापाप है।

अम्मार साहब के यहां तो बहुत बड़ा पाप है। क्या मैं यह उम्मीद करूं कि इस हक को आप रिश्वत की स्टेज पर लाकर खड़ा कर देंगे? खत्म न करें इस हक को लेकिन अगर आप इसे रिश्वत की स्टेज पर लाकर खड़ा करें तो मैं बहुत समझूंगा। यह आपके पास जो महकमा है, मैंने कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश का जो भी विकास है, ग्रामों के विकास का ताल्लुक सड़कों से है। जनता पार्टी के जमाने में इसको "प्रायरिटी" दी गयी। आपने कहा कि अगर 410 करोड़ रु0 आपको मिल जाय तो आप सड़कों को पक्का करा देंगें। न करिये आप पक्का लेकिन जहां नाली और पुलिया बनाने की बात है, वहां नाली और पुलिया बन जांय। अगर सड़कों को पक्का नहीं करा सकते तो कम स कम सड़कों की मरम्मत ही हो जाय। इसमें तो कोई 410 करोड़ रु0 की जरुरत है नहीं।

यह मैंने 2–4 बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया है। मुझे आशा है कि इन बातों पर गम्भीरता से मा0 मंत्री जी जरूर विचार करेंगे और इसके साथ ही म कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(2 बजकर 52 मिनट)

*श्री चेत राम गंगवार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के अवसर पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, मैं तो इसे आपका सौभाग्यशाली दिन कहूंगा, जो इस प्रदेश के किसानों को ग्रामीण अंचलों में रहने वालों कोऔर मजदूरों को जो प्राप्त हुआ, वह अपनी प्रधानमंत्री माननीया इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में श्री अम्मार रिजवी जी के कुशल और सबल हाथों का ही फल है, जो इनके निर्देशन में सारी टीम ने मिलकर एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। यह आप और हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के लोग नहीं कह रहे हैं बल्कि विदेशों से इस बात के बहुत से सर्टीफिकेट प्राप्त हुये हैं। अगर आप अरेबियन कन्ट्रीज में जांय, सऊदी अरब, लीबिया और ईराक इत्यादि में तो बहुत सी जगहों पर हमारे इंजीनियर्स, टैक्नीशियन्स और बुद्धिजीवी वर्ग की मांग है और काफी लोग वहां पर काम कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से यह सर्टीफिकेट, जो लीबिया सरकार का है, उसको पढ़ना चाहता हूं, जो मेरे इस वाक्य की पुष्टि करता है।

एक सदस्य—

क्या इसे आपने बनाया है ?

श्री चेतराम गंगवार—

यह तो विदेशों से मिला है, जो आपकी सरकार को नहीं मिल सका।

श्री चेतराम गंगवार—

तो मान्यवर, मैं इसे पढ़े दे रहा हूं....

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कहीं लीबिया से लाया हुआ कोई प्रमाण-पत्र ये पढ़ना चाहते हैं और उसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इनका कहना है कि लीबिया से, मान्यवर, लीबिया एक कन्ट्री है, वहां से इन्हे एक प्रमाण-पत्र मिला है और उसे पढ़कर ये उसे सदन की कार्यवाही का अंग बनाना चाहते हैं। अभी यह भी मालूम नहीं है कि उसे आपने बनाया है या वो लीबिया से आया है। मान्यवर, नियम में प्राविधान है कि कोई भी डाकूमेन्ट पढ़ने से पूर्व उसकी कापी आपको देनी चाहिये। मेरा आपसे अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र लाया गया है उसे यहां न पढ़ने दें और उसे कार्यवाही का अंग न बनायें (इसी बीच माननीय चेतराम गंगवार कोई कागज लेकर पढ़ते रहे जो कि शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय चेतराम गंगवार जी, यह प्रमाण-पत्र है आपके पास ?

श्री चेतराम गंगवार---

जी हां, मान्यवर

श्री उपाध्यक्ष---

उसकी कापी आप पहिले यहां भेज दीजिये, उसके बाद पढ़िये।

(श्री चेतराम गंगवार ने फिर उस पत्र को पढ़ने का प्रयास किया।)

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, नियम में प्राविधान है कि पढ़ने से पहिले कापी आपके पास आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रमाण-पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रिफरेन्स दे रहे हैं।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, मैंने कोई व्यवस्था उठाई है।

उपाध्यक्ष---

माननीय चेतराम गंगवार जी, अगर आप पूरा प्रमाण-पत्र पढ़ रहे हैं तो उसके पहिले) उसकी एक कापी यहां पर भेज दीजिये।

(इस पर भी श्री चेतराम गंगवार द्वारा पत्र को पढ़ने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

श्री चेतराम गंगवार---

मैं पढ़ कर आपको कापी भिजवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, यह पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इन्होंने कापी इसकी आपके पास भेज दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपके पास नहीं चेतराम गंगवार जी इसे मेरे पास होना चाहिये।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, दे रहा हूं। इसकी हिन्दी में अनुवाद यह है--

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, अनुवाद कहां से कर रहे हैं ?

श्री चेतराम गंगवार––

[× × ×]

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा मेजों का थपथपाया जाना।)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय चेतराम गंगवार इसे आप कापी कहते हैं, यह कापी है क्या ?

श्री चेतराम गंगवार––

हां, है।

श्री उपाध्यक्ष––

नहीं। यह कापी तो है नहीं। इसे कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें तथा मेजों का थपथपाया जाना।)

श्री चेतराम गंगवार––

आप आश्वस्त हो जायेंगे मान्यवर, इसकी कापी विभाग से मिल जायेगी जो ओरिजनल सार्टिफिकेट है।

(व्यवधान)

एक सदस्य––

आप मंत्री जी को भी चेतावनी दे दें कि.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

जब बुजुर्ग मेम्बर ही इस तरह का काम करें तो मैं उनको क्या चेतावनी दूं। माननीय गंगवार, इसको छोड़कर इसके आगे बोलें।

श्री चेतराम गंगवार––

मैं मुख्य चीज की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें हमेशा-हमेशा के बजाये सर्वेक्षण कराये कि कौन जिला, ब्लाक पिछड़ा हुआ है, जिसमें भवनों, सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। विभाग की ओर से जो पुस्तिका बंटी है सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के पृष्ठ 61 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हरियाणा, पंजाब की बात नहीं करता, छोटे से प्रदेश कर्नाटक, नागालैण्ड को मंत्री जी देखने की कृपा करें। यहां पर कर्नाटक में 15 सौ से अधिक की जनसंख्या के गांवों में सड़कें बन गयी हैं और जो एक हजार से 15 सौ तक की आबादी के हैं उनमें 37.8 प्रतिशत बन गयी हैं। इसी तरह से नागालैण्ड में 15 सौ के ऊपर में सेंटपरसेंट बन गयी हैं और एक हजार से ऊपर हैं और 15 सौ तक 93 प्रतिशत बनीं। एक हजार से नीचे में भी 60.3 प्रतिशत बन गयी

नोटः––[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री चेतराम गंगवार---]

और उत्तर प्रदेश का हाल, बहुत बुरा है। यहां 15 सौ से ऊपर के जो गांव हैं वह 51.5 प्रतिशत और आज वह 15 हजार हो गये हैं। सर्वेक्षण हो रहा है कितने गांवों की आबादी ज्यादा है और उनका सर्वेक्षण आज तक नहीं हो पाया है। इसी तरह से एक हजार से कम की आबादी वाले गांवों में 13.3 प्रतिशत ही सड़क बनी है.....

(व्यवधान)

कुर्सी का बादशाह कौन, दलबदलुओं का सरताज कौन।

(व्यवधान तथा हंसी)

उस दिन मैंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि जलेबियों के रखवाले कुत्ते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जो आपने आंकड़े गिनाये यह क्या पी0 डब्लू0 डी0 का विश्लेषण है ?

श्री चेतराम गंगवार---

जिलों की बात कहता हूं। मान्यवर, आप देखें, हमारे बरेली जिले में कुल 1196 कि0मी0 सड़क है लकिन उसी वक्त गाजियाबाद में 1526, अल्मोड़ा में 1728, देहरादून में 1791, गढ़वाल में 1676, नैनीताल में 2574, इलाहाबाद में 2389, गोरखपुर में 1617 वाराणसी में 2214, तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री की ओर से घोषणा हुई कि निकट भविष्य में जो डिसेन्ट्रलाइजेशन हुआ है बजट का जिससे 30 प्रतिशत जिलों पर खर्च होगा, मैं उस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ब्लाक, तहसीलें, जिले पिछड़े हुए हैं, स्वतः वह धन उन पर खर्च हो यह नहीं कि सिफारिश करने पर जैसे हमारे सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी ने, श्यामलाल बाजपेयी ने बहुत-बहुत सड़कें बनवायीं इसलिए यह बजट स्वतः बैकवर्ड क्षेत्रों की ओर, धन जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। बरेली का स्थान 15 वें ब्लाक पर है। वहां विश्रामपुर और बाजार के बीच सड़क 12 किलोमीटर लम्बी है। वहां जिला परामर्शदात्री समिति होनी चाहिये जिससे वहां के गरीब लोगों को, हरिजन को राहत मिल सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नवाबगंज तहसील में पुल बनाना आवश्यक है। वहां पर अंग्रेजी शासन काल में 50-60 वर्ष पूर्व पुल बने थे जिनकी छत वगैरह टूट गई है, फर्श टूट गई है और आज वहां पर बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासन में उनके एक मंत्री सत्य प्रकाश अग्रवाल वहां गए थे और यह कहा कि यह पुल बनवाया जायेगा लेकिन आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जनता पार्टी ने सारा रुपया अपनी अक्षमता के कारण बर्बाद कर दिया और एक किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई उसी तरह से हमारी सरकार भी न करे। मैं चाहूंगा कि इन सब बातों की ओर मा0 मंत्री जी ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं बजट के प्रति और यह कहना चाहता हूं कि इन अनुदानों का पास होना स्वाभाविक और जरूरी है।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)---

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस मंत्रिमंडल की कारगुजारी सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने बता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी है, कलई खोल दी है। इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। 2 अरब 52 करोड़ रु0 का बजट माने केवल 50 करोड़ रु0 ही लग पायेगा और बाकी का रुपया इन भ्रष्ट अफसरों और शासन की जेबों में चला जायेगा। आज निर्माण निगम की जो इमारतें बनी हुई हैं अगर उनके मेटीरियल की लेबोरेटरी में जांच कराई जाय तो उसमें रेत 10 हिस्से होगी और सीमेंट 1 हिस्सा होगी। बुनियाद में कंकड़ी और चूने के बजाय मिट्टी और कंकड़ी डाली गई। आज विधायक निवासों की हालत देखने लायक है। कहीं पर पानी टपक रहा है। कहीं पर टोटियां चल रही हैं। कहीं फर्श टूट रहा है, कहीं छतें टूट रही हैं। यह ढाई अरब रुपये का बजट केवल जीप, कार, भत्ता और अधिकारियों की जेबों में जायेगा।

आप के माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हर जिले में जनता के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनायें और देखें कि कौन सी सड़क किस दिन बनी और किस दिन टूटी। मैं अपने जिले के इंजीनियर के पास गया। मैंने कहा कि यह सड़क बन गयी है मैंने बतलाया कि इधर बनी है और उधर टूटी है। उसने बतलाया कि मंत्री जी हमें रुपया ही नहीं आवंटित करते हैं इसलिये सड़कें नहीं बनायी जा रही हैं। यह दुर्भाग्य है कि हजारों की तादाद में इंजीनियर्स हैं लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं है कि किस आधार पर सड़कें बननी चाहिये। मैं आपको टेक्निकल जानकारी दे रहा हूं। आशा कि माननीय मंत्री जी अपने भाषण में उसका जवाब देंगे। हमारे क्षेत्र छार में 6 महीने पहले एक सड़क बनी जिसकी हालत यह है कि कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं इधर है, कहीं उधर है टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं।

मान्यवर, हरियाना प्रदेश में,पंजाब प्रदेश में शत प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। हमारे यहां जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के जिन गांवों को कच्ची सड़कों से जोड़ दिया है कम से कम उनको तो पक्की करावें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें 4 अरब 10 करोड़ रुपये चाहिए। ढाई अरब रुपया तो अभी आप ले ही रहे हैं, 4 अरब 10 करोड़ में से अब कमी ही क्या रह गयी है। मान्यवर, यह ठेकेदारी की प्रथा, फर्जी बिल्स की वजह से ही यह प्रदेश विकास की ओर नहीं जा रहा है। मंत्रिमंडल का अफसरशाही पर कोई कब्जा नहीं है। सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अपने ही दल की कलई खोल दी है और ऐसा लगता है कि उनके दल में बगावत होने ही वाला है और सरकार टूटने वाली है। इसलिये श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चाहिये कि वे स्वतः ही अपनी सरकार को भंग करके इस्तीफा दे दें। निर्माण निगम की बड़ी दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि प्रदेश में उसे प्रमाण-पत्र मिल गया है। मैं दावे के साथ माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निर्माण निगम ने जितनी भी इमारतें बनायी हैं उनमें 60 प्रतिशत घपला है। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी दफ्तर व कर्मचारियों के क्वार्टर्स बने हैं उनकी आज यह दुर्दशा है कि कहीं तो फर्श नहीं है, कहीं फर्श टूट रहे हैं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है और फिर भी उसे कम्पलिशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि काम कम्पलीट हो गया। कम्पलिशन सर्टिफिकेट देने पर ठेकेदार द्वारा 25 प्रतिशत कमीशन लखनऊ के सरकारी आफिसरों को मिलता है, जिले के आफिसरों को मिलता है और मंत्रिमंडल को भी मिलता है।

मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में विकास की हालत, सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि यह देखने में आ रहा है कि 6 माह पहले जो सड़क बनी वह टूट गयी और कहने पर भी उसकी जांच नहीं की जा रही है। रिपोर्ट करने पर भी उसकी तरफ कोई ध्यान

[श्री बलबीर सिंह, रामपुर—]

नहीं दिया जाता है। अगर इस बारे में प्रश्न किया जाता है तो मंत्री की तरफ से उसका जवाब ही नहीं आता है। तीन महीने बाद अगर उत्तर आता है तो उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु उसी आफिसर के पास भेज दिया जाता है जिसकी शिकायत की गयी होती है। फिर 6 महीने बाद साल डेढ़ साल बाद तक उसका कोई उत्तर ही नहीं आता।

मजबूर होकर विधायकगण प्रश्न करते हैं। प्रश्नों की हालत आप जानते ही हैं। मंत्री जी निकल कर इधर भागते हैं उधर भागते हैं, संरक्षण आपकी पीठ से मिल जाता है। मान्यवर, कोई उत्तर सही नहीं दिया जाता। आज माननीय सदस्य श्याम लाल बाजपेयी ने अफसरशाही की गाथा सुनाई। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कलई खोल दी सत्ता पक्ष की। अगर इन्हें शर्म हो तुरन्त त्याग-पत्र दे दें। एहसास हो। लेकिन एहसास इनका खत्म हो चुका है।

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि सड़कों पर मैटीरियल 6 महीने साल भर, दो साल तक पड़ा रहता है। ठेकेदारों को दो बार पेमेन्ट हो जाता है। लेकिन सड़क पर वह मैटीरियल नहीं पड़ता। वह मैटीरियल उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा उठा लिया जाता है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी स्वयं जानकारी करें क्योंकि नये मंत्री हैं। जानकारी करें ताकि मालूम हो जाय कि इसमें कितने करोड़ों अरबों का घपला है। दो अर 52 करोड़ में से 52 करोड़ ही लग जायं तो हमारा सौभाग्य होगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं जिनकी तरफ ध्यान देने का कष्ट करेंगे। जनता शासन के वक्त में बाकी रह गयी हैं। मान्यवर, माटखेड़ा, लतीफनगर, राम नगर सड़क पिछले दस साल से अधूरी पड़ी हुई है। यहां से पैसा भी जाता है। इसी प्रकार से रामपुर टांडा के दरमियान पुल टूट गया है। दस साल से पहले इसकी मियाद हो चुकी है। कोई इस पर विचार नहीं किया गया। कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। मंत्रीगण अपनी क्षेत्र बनाने में लगे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पुल को तुरन्त बनाया जाय रामपुर-टांडा टाउन एरिया को जोड़ता है। दोनों तरफ से टूट चुका है। कोसी नदी पर पुल आज तक नहीं बना। छेतरीया वाली सड़क पर दस साल पूर्व काम शुरू किया गया था लेकिन आज तक उस पर काम पूरा नहीं हुआ है। बहला नदी का पुल हमारे ब्लाक में पड़ता है बरसात में तमाम दिक्कत होती है। लेकिन आज तक यह पुल नहीं बनाया गया।

मैं चाहूंगा कि इस भष्टाचार को माननीय मंत्री जी समाप्त करेंगे। एक कमेटी हर जिले में विधायकगणों की होनी चाहिए। कमेटी है लेकिन वह सलाहकार कमेटी है उनसे कोई जवाब तलब नहीं कर सकते मौका निरीक्षण नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसे निरीक्षण का अधिकार दें। जो विधायकगण शिकायत करते हैं उनकी सुनवाई हो, भ्रष्टाचार को खत्म करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय हरगोविन्द वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट पर जो मुझे बोलने का अवसर मिला है इसके लिए आपका आभारी हूं।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने बड़े सूझ-बूझ के साथ यह बजट प्रस्तुत किया है जो कि पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा। इसलिये मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं।

इतना अवश्य कहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है विशेष रूप से हमारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बाहुल्य प्रदेश है और इसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल देश के अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक है....

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश होने के नाते इसका क्षेत्रफल दो लाख 94 हजार वर्ग किलोमीटर है। 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 1,109 लाख आंकी गई है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों की बहुत बड़ी कमी है। हमारे प्रदेश में केवल 2470 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग हैं जो कि क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भारत में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि पश्चिमी बंगाल और बिहार से जो उद्योग एवं खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे उत्तर प्रदेश के ही माध्यम से भारत के अन्य प्रदेशों में भेजे जाते हैं। इसलिये हमारे प्रदेश को भारत सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहिये कि जो भी यहां पर मुख्य-मुख्य मार्ग हैं उनकी स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय मार्ग की दी जाय।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो महत्वपूर्ण निगम हैं–एक राजकीय निर्माण निगम तथा दूसरा सेतु निगम। इन दोनों निगमों का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और उसके कारण हमारे प्रदेश को बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है। राजकीय निर्माण निगम के अन्तर्गत हमारे सभी तरह के निर्माण कार्य होते हैं जिनमें भवन, बांध, विद्युत् गृह आदि आते हैं। 12 करोड़ की लागत से आनपारा विद्युत् गृह बन रहा है। हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा कि यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ स्टेशन रोड पर ही पी0सी0एफ0 की 9 मंजिली बिल्डिंग देखें, सचिवालय अनेक्सी को देखें जो 6 मंजिल की है, पुराना विधायक निवास के पास जो 15 मंजिला भवन बन रहा है उसको देखें, दारुल सफा में जो विधायकों के लिये 4/5 मंजिला भवन बना है, उसको देखें, मैं कहता हूं कि क्या यह हमारे राजकीय निर्माण निगम की उपलब्धि नहीं है। जहां तक सेतु निगम का प्रश्न है यदि किसी को गोंडा जाने का अवसर मिला तो वह देखेंगे कि घाघरा का पुल निर्मित हो रहा है, वह किस तरह से बन रहा है। राजकीय निर्माण निगम को लीबिया में भी कार्य करने का मौका मिला है और उसके साथ इस विभाग का 3.54 करोड़ की निविदा हुई है जिसका प्रशंसा पत्र भी इसको मिल चुका है। इसके साथ ही साथ सेतु निगम का कार्य ईराक में भी चल रहा है। वहां पर भी इस निगम ने ख्याति प्राप्त की है। छठीं पंच वर्षीय योजना का यह तीसरा वर्ष चल रहा है और जो हमारे इस विभाग की तरफ से योजना दी गई थी उसमें 1,333 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था परन्तु राजकीय योजना के अनुसार यह प्रस्ताव घटाकर 923 करोड़ रुपया कर दिया गया और भारत सरकार ने इसे मात्र 415 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। इसमें यह बात बड़े दुख की है कि उसमें भी केवल 290 करोड़ रुपया मैदानी क्षेत्र के लिये और 125 करोड़ रुपया पर्वतीय क्षेत्र के लिये रखा गया है।

मान्यवर, यह विशेष ध्यान देने की बात है कि छठीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व 285 करोड़ रुपया पूर्व स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया गया है। यहां पर 415 करोड़ रुपया की योजना थी छठीं योजना के जो पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम हैं उन पर 285 करोड़ रुपया लग गया और अब 130 करोड़ रुपया अन्य कार्यों के लिये बचता है। मान्यवर, सन् 1980–81 और 1981–82 में लगभग 220 करोड़ रुपये के नये कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। जब कि हमारे पास केवल

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—]

130 करोड़ रु0 नये कार्यों के लिये बचता है । इसलिये मैं कहता हूं कि नये कार्यों क लिये जो 220 करोड़ रुपया चाहिये उसमें से केवल 130 करोड़ रु0 मिला है तो वह काम पूरे नहीं हो पायेंगे । 1980–81 में 85 करोड़ के स्थान पर 91.59 करोड़ रु0 व्यय करना पड़ा और 1981–82 में 84 करोड़ रु0 परिव्यय निर्धारित हो चुका है । इतनी जरूर खुशी की बात है कि हमारे जो अपने कार्यक्रम हैं उसमें 1,580 कि0मी0 नयी सड़कों और 1,080 कि0 मी0 जो पुरानी सड़कें हैं उनको ठीक करने पर खर्च किया जायेगा और 62 पुल हमारे बनेंगे लेकिन इसमें 43.65 करोड़ रु0 केवल मैदानी क्षेत्रों की योजना के लिये रखे गये हैं । हमारा प्रदेश ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र का है इसलिये ग्रामीण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे हमारे बेरोजगार युवकों को रोजी मिलेगी और गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जायगा । उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या 1,12,561 है । 1971 की जनगणना के अनुसार 15 सौ से अधिक की आबादी वाले गांव 10,889 हैं और 1000 से 1,499 तक की आबादी के 11,396 गांव हैं । तो हमारी सरकार के जो कार्यक्रम है वह 15 सौ से अधिक की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का है यह योजना जिला स्तर पर पहले ही भेज दी गयी हैं । इसके बाद 10 सौ से 1 499 तक की आबादी के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया जायेगा । (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं आपका समय समाप्त हुआ, बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिये 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

सिर्फ एक मिनट और चाहता हूं । हमारे गोंडा जनपद में घाघरा पर पुल का निर्माण कर दिया गया है जिससे हमारे जनपद का अन्य जिलों से सम्बन्ध हो रहा है लेकिन तहसील और ग्राम स्तर को भी मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम होना चाहिये और गांवों की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं अधिक समय न लेकर आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का सर्थन करता हूं और पूर्ण आशा रखता हूं कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अपने कार्यक्रम में दिनों दिन अग्रसर रहेंगे और हमारे विपक्षी भाइयों को सद्बुद्धि आयेगी कि वह हामरे प्रस्तावों का समर्थन करेंगे ।

श्री फखरे आलम—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (एक शेर हो जाय की आवाज)

नालये बुलबुले सैदा तो सुना हंस-हंस कर,
अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई ।

मान्यवर, हम यह उम्मीद कर रहे थे कि हमारे माननीय मंत्री जनाब अम्मार रिजवी साहब एक ऐसा पी0 डब्लू0 डी0 का बजट हमारे सामने इस हाऊस में लायेंगे जिसमें नयी बातें होंगी । मगर इस बजट को पढ़ने के बाद मायूसी हुई, मायूसी न होती अगर किसी और मन्त्री की तरफ से बजट आया होता, मगर ऐसे इनरजैटिक मन्त्री की तरफ से जिस पर तमाम उत्तर प्रदेश की निगाह लगी हुई है वे इस तरह का बजट लाये । माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में रोड्स के बारे में बहुत सी बातें कही यह देख कर अफसोस हुआ कि 68 करोड़ में से 43 करोड़ रुपया आप शहरों की सड़कों पर लगा रहे थे । जरूरत इस बात की थी कि देहात में आप जाइये, वहां सड़कें बनवाइये, गांव-गांव को जोड़ दीजिये और कोई ऐसा गांव उत्तर प्रदेश में न रहने पावे जो शहर से पक्की सड़कों से मिला हुआ न हो ।

आज इसकी जरूरत नहीं है कि कमिश्नर के बंगले के सामने पक्की सड़क बनी हुई हो, उसके बंगले के सामने फव्वारे लगे हुए हों और न आज इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेन्ट के सामने ऐसी सड़क हो, जिस पर आदमी फिसलता हुआ चला जाए । हमें जरूरत है कि हरिजन झोपड़ियों के सामने पक्की सड़क बनी हुई हो । हमें यह आशा थी कि हमारे मिस्टर अम्मार रिजवी साहब ऐसा ही बजट पेश करेंगे, लेकिन वह पूरी नहीं हुई । आज मायूसी इस बात से हो रही है कि आपके हाथ का लिखा हुआ बजट वैसा नहीं आया है । क्या आपने अपने सेक्रेटरी के ऊपर बजट छोड़ दिया था । मैं यह यकीन नही कर सकता हूं, फिर भी जब आपने बजट बाद में देखा तो आप उस वक्त कहां चले गये थे कि 43 करोड़ रुपया शहर की सड़कों पर लगाया जा रहा है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों ऐसा होने दिया । एक दफा गलती हो गई आईन्दा न हो, यही चाहता हूं—'डूब कर मैंने तूफां को दे दी खबर, नाखुदा न बेखबर हो तो मैं क्या करूं" । अब तो आपको यह बात मालूम हो गई होगी कि आपको शहरों को उतना देखना नहीं है जितना देहात को देखना है । हमारी 90 फीसदी आबादी देहात में रहती है ।

अभी दूसरी बात जो कही गई उसमें कहा गया है कि यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन ने बड़ा अच्छा काम किया है । इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बड़ी शोहरत हुई है । वह एक कामर्शियल कन्सर्न है, एक बनिये की दुकान है, लेकिन उसको आप बनिये की दूकान न बनाइये । मंत्री को भले आप कोई बनिया बना दीजिये, लेकिन ब्रिज कारपोरेशन को बनिये की दुकान न बनाइये । आपने उसको ऐसा कन्सर्न बना दिया है जैसे कि कोई बनिया की दुकान होती है । हमारे लोगों ने ब्रिज कारपोरेशन के द्वारा लीबिया, अल्जीरिया वहरीन आदि मुल्कों में काम किया है । किन्तु मान्यवर, ब्रिज कारपोरेशन ने जो यह काम किया है–हमारे सेतु निगम ने जो कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह मन्त्री जी को मालूम है । उसकी वजह यह है कि आपने यह ठेका उन मुल्कों, उन देशों में लिया है, जहां का पहला उसूल यह है–जियो और जीने दो । वहां का सिद्धांत है ईमानदारी से काम करो । मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनके सामने यह चुनौती है कि वह ऐसे मुल्कों में काम करके दिखायें, ऐसे देशों में ठेका लेकर कामयाबी से काम करके दिखायें जहां आज बेईमानी का बोलबाला हो रहा है । आप बदायूं में कोई काम करके दिखाइये तो हम समझें, जहां के एक बड़े मन्त्री हैं जो कि मुख्य मन्त्री होने का सपना देख रहे हैं । वहां आपका सारा माल गायब हो जाएगा और काम कुछ नहीं होगा । सब कागज पर पूरा हो जायेगा । आपका सारा सामान यों ही चला जायेगा और कवि सम्मेलन में चला जायेगा ।

दूसरी चीज जिसे मुझे कहना है वह यह है कि नेशनल एन्टीग्रेशन मिनिस्टर अम्मार साहब ने, उसके लिये भी एक छोटा सा बजट पेश किया है, एक मामूली सा बजट पेश किया है—एक बजटिया है और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मैं पूरे भारत को एक सम्पन्न परिवार बना हुआ देखना चाहता हूं । तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह सारे भारत को ऐसा परिवार बना देखना चाहते हैं जैसा आपकी पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने मुरादाबाद में दिखाया है या इलाहाबाद में आपकी पुलिस और पी0ए0सी0 ने बनाया है और दिखाया है या अलीगढ़ में जैसा नंगा नाच आपकी पुलिस ने किया, वैसा देखना चाहते हैं । या आप वैसा परिवार देखना चाहते हैं, जिसका सपना हिन्दुस्तान के नेता महात्मा गांधी ने देखा था । क्या आप महात्मा गांधी का हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं या पी0 ए0 सी0 या यू0 पी0 पुलिस का राज्य बनाना चाहते हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अलीगढ़ की ओर दिलाना

[श्री फखरे आलम—]

चाहता हूं जहां खूनरेजी हुई थी और बहुत मजालिम हुए थे और फिर आप नेशनल इन्टीग्रेशन की बात कह रहे हैं। ये उस चोर की तरह हैं जो हाथ पर चिराग रखकर चोरी करता है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने मुझे पार्टी के लीडर की हैसियत से बोलने का मौका दिया है, इसलिये आप मुझे और समय दीजिये। जहां आपने नेशनल इन्टीग्रेशन में झांसी का जिक्र किया है वहीं पर आप बदायूं का नाम नहीं लिया जहां पर मौलवी तफज्जुल हसन, आजादी के शूरमा पैदा हुए थे जिनको अंग्रेजों ने गोली से मारा था और उनकी लाश को उनके वारसान को न देकर जेल में ही दफना दिया था। जिसने 1857 में आजादी का झण्डा फहराया था, क्या आपने उसको भी याद रखा ?

मान्यवर, बदायूं में एक उसहैत का पुल है, तकराला से मुहम्मदगंज का एक पुल है और बरेली-बदायूं रोड पर राम गंगा का पुल बना है। उस पर आप महसूल लेना बन्द कराइये क्योंकि उस पर सूद दर सूद वसूल कर चुके हैं और जो काम अधूरे हैं उनको पूरा कराइये। मैं एक शेर अर्ज करता हूं:

आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब,
दिल का क्या रंग कहूं खूने जिगर होने तक।

इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर दिया .....

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो यह पुस्तिका छपी है। इसके पृष्ठ 34 पर बहराइच में जिन सड़कों और अन्य कार्यों का निर्माण हो रहा है उनको बहराइच में न दिखाकर गोंडा जिले में छापा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। जब आपको इन मांगों पर बोलने का मौका मिलेगा तो मंत्री जी से पूछ लें। यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

*श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, विरोध पक्ष द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसे एक बहुत ही शर्मनाक घटना समझता हूं। वह इसलिये कि यह विभाग वास्तव में प्रदेश के विकास के रास्ते को मजबूत करने का महत्वपूर्ण बजट है जो आज सदन के पटल पर रखा गया है।

माननीय वर्मा जी ने सड़कों के खराब होने और गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की बात कही है जिसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उनकी ओर से कहा गया कि जनता पार्टी और लोक दल की सरकार के जमाने में बड़े ही व्यापक पैमाने पर सड़कों का काम हुआ था लकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोक दल और जनता पार्टी के शासन के दरमियान जो खाद्यान्न योजना चलायी गयी थी, सही माने में अगर पूछा जाय तो वह "खाओ और चरो" की एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना थी। मैं मानता हूं कि सड़कों की हालत खराब है जो सुधरनी चाहिये थी, वह नहीं सुधरी है। आपका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि किस प्रकार से इस व्यवस्था को सुधारा जाय ? इसके ऊपर आप अपनी राय जाहिर करें। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे कृपया रोड नं0 34 जो राष्ट्रीय मार्ग है, को देखने का कष्ट करें। उसकी हालत बहुत ही खराब और दयनीय है। उसे ठीक कराने की कृपा करें। वैसे सारी ही सड़कों की हालत दयनीय है, पर इसे विशेष रूप से ठीक कराने की आवश्यकता है।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो भी रोड जिस इन्जीनियर की देख रेख में बनायी जाय उसके लिये एक अवधि निश्चित कर दें कि उस अवधि के पहले अगर वह सड़क खराब हो जायगी तो उसके लिये जिम्मेदारी उसी इंजीनियर की होगी। यह बात विरोध पक्ष को कहनी चाहिये थी, लेकिन इस तरह के उधर से सुझाव न आकर केवल राजनैतिक विचार ही यहां पर रखे जाते हैं। रचनात्मक सुझाव नहीं आते।

ब्रिज कारपोरेशन की चर्चा हुई। निश्चय ही वह प्रशंसा की पात्र है। हमारे देश के अन्दर विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है। सेतु निगम एक ऐसा निगम है जिसके द्वारा काफी विदेशी मुद्रा हमारे यहां आ रही है और इसके लिये यह निगम निश्चय ही बधाई का पात्र है। पुलों के बारे में एक बात माननीय रियासत हुसैन साहब ने कही कि जहां पर पुलों का निर्माण होना चाहिये वहां नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिये। बिहार प्रदेश से बलिया होते हुए अगर लखनऊ आयें तो एक माझी का पुल पड़ता है। मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में उस पार्टी के नेता चन्द्र शेखर ने उस समय उस पुल का शिलान्यास भी किया था, मगर वह केवल जनता को गुमराह करने के लिये था। उसके बाद आज तक वह नहीं बना। मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री जी उस पुल को बनवाने के लिये तत्काल कार्यवाही करें। बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिये इस पुल की बहुत आवश्यकता है। मुझे यकीन है इस पुल को बनाने की योजना पर आप अपने अधिकारियों से शीघ्र विचार विमर्श करेंगे।

एक बात यह कही गयी कि इस विभाग में नौकरशाही हावी है। ऐसी बात नहीं है। होता यह है कि अगर जूनियर इंजीनियर कोई गलती करता है तो उसकी जांच उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जाती है। इसकी जगह आप एक ऐसी कमेटी बना दें जो इस तरह की शिकायतों की जांच किया करें तो अच्छा रहेगा। जहां तक नौकरशाही के हावी होने की बात है, मैं जानता हूं, माननीय अम्मार रिजवी साहब के विभाग में उनके कारण आज नौकरशाही हावी नहीं हो पा रही है और न हो सकेगी भविष्य में। इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को और विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। यह भी कहा गया कि अधिकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो इसकी तह में अगर जायं तो पता यह चलेगा कि जनता पार्टी और लोक दल की सरकार के समय में उनके कारनामे ऐसे रहे हैं कि ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं गवाही दे सकता हूं कि उस माने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले काम किये गये।

(इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

[श्री भोला पाण्डेय]

राष्ट्रीय एकीकरण के काम के लिये जो बजट रखा गया है वह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। आज पूरे प्रदेश में जो प्रतिक्रियावादी ताकतें सर उठा रही हैं और जो सदभावना का वातावरण बना हुआ है उसे तोड़ने में लगी हुई हैं, इसे रोकने की जरूरत है। इस काम के लिये जो बजट में पैसा रखा गया है वह बहुत कम है।

विरोध पक्ष ने उर्दू की बात कही। उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने की बात कही गयी। मैं चाहता हूं कि आप उसकी तह में जाकर देखें कि कहीं इससे जो असमानता हम दूर करने की बात कर रहे हैं, प्रदेश को एक सूत्र में जो बांधने की हम बात कर रहे हैं, उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने से कहीं उस पर आघात तो नहीं पहुंचेगा ? इससे आगे चल कर कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(3 बज कर 45 मिनट)

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन और इस बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट से जनता को खुशी नहीं हुई है, बल्कि विभाग के अधिकारियों को बेहद खुशी हुई है, क्योंकि कम से कम आधा पैसा उनकी जेबों में चला जायगा। मान्यवर, जिस तरह से इस विभाग में ठेकेदारी की प्रथा है और अवांछनीय और गुन्डा तत्व मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इनके अलावा, इस विभाग में अच्छे ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाता है बल्कि गुण्डों और अवांछनीय तत्वों को ठेका दिया जाता है, जो बुरे काम करते हैं, उन्हीं को ठेका दिया जाता है। मान्यवर, इस विभाग में आम बात हो गयी है कि गन्दा काम करने पर भी बिल पास करवाना।

मान्यवर, मेरे जिला मथुरा में एक प्रान्तीय खण्ड है, उसमें आये दिन झगड़े होते हैं, कभी ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में, कभी अधिकारी-अधिकारी के बीच में, कभी क्लरिकल स्टाफ और अधिकारी के बीच में। बहुत ही शिकायत है, सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी भी चल रही है। मान्यवर, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मथुरा में रिफाइनरी बन जाने से उसका बहुत महत्व बढ़ गया है। रिफाइनरी में उत्पादन शुरू हो गया है। रिफाइनरी के अधिकारियों का कहना है कि जब पूरी तरह से रिफाइनरी में पूरी तरह से उत्पादन का काम शुरू हो जायगा तो मथुरा और आगरा में जो बाहर से आने वाले ट्रक हैं, उससे पूरा मार्ग भर जायगा और जो बहुत से विदेशी लोग भी इस रास्ते से आते-जाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जायेगी इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली, मथुरा, आगरा मार्ग को जोड़ने के लिये जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, उसे पूरा रिफाइनरी ट्रैफिक के लिये छोड़ दिया जाय और दूसरा मार्ग निर्मित करायें।

मान्यवर, मथुरा, वृन्दावन बहुत ही धार्मिक और रमणीक स्थान है, वहां पर हमारे केन्द्र के और प्रदेश के जो भी मंत्री जाते हैं, वह यह आश्वासन देकर आते हैं कि यमुना नदी पर एक पुल बनवाया जायगा। बहुत आश्वासन दिये जाते हैं, लेकिन अभी तक वहां पर पुल नहीं बनवाया गया। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वृन्दावन में यमुना नदी पर एक पुल बनवायें। शेरगढ़ में भी एक पुल बनवाने की कृपा करें। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में बतलाना चाहता हूं। मान्यवर, वहां पर जो सड़कें जनता शासन काल में बनीं, वह अधूरी पड़ी हुई हैं, उनका कोई निर्माण नहीं हो रहा है और जो बनी हुई थीं, वह भी बरबाद हो गयी हैं। मान्यवर, अधिकारी लोग यह कहते हैं कि अभी तक बजट नहीं मिला है, इसलिये सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर सड़कों की जो स्थिति खराब पड़ी हुई है, उसे सुधारें और अन्य अधूरी सड़कों को भी बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बिहारी लाल––

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र को मौका नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र को अवश्य मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय बिहारी लाल जी, आप बैठिये। आपको समय मिलेगा।

श्री सुन्दर सिंह––

मान्यवर, बहराइच जनपद के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं, वह सब गलत दिये गये हैं और बहराइच को मौका नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, बहराइच जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है, उसे मौका दने की कृपा की जाय।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका एहशानमन्द हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने मंत्री महोदय का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है, जो संतुलित है।

मान्यवर, यदि आप देखें तो लगभग 34 साल पहले इस प्रदेश में 15 हजार किलोमीटर के लगभग सड़क पक्की थी। 34 साल के बाद 63 हजार सड़क पक्की बन गई है। इससे अनुभव होता है कि इस विभाग में कितनी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त और भी सड़कें बनायी है जैसे कच्ची और मिट्टी डालकर बनाई गई है। मान्यवर, मैं जनपद बदायूं की ओर आपके माध्यम से माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं। वहां पर एक सड़क स्वीकृत हुई थी जिसके लिये सन् 1956 से प्रयास किया जा रहा है। यह सड़क पहले जिला परिषद् में थी और उसके बाद इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 3 साल पूर्व या ढाई साल पूर्व लिया। लेकिन अभी भी यह सड़क अपूर्ण है पूरी नहीं हो पायी है। यह मेरे क्षेत्र में सैदपुर–करेंगी सड़क है। मान्यवर- इस सड़क को आप बना दें तो लगभग 70–80 हजार जनता जो वहां रहती है उससे लाभान्वित होगी। यह जनहित में है। यह सड़क इतनी आवश्यक है कि अगर बना दी जाय तो वहां के 70–80 हजार जो कृषक है जो जमीन सोना उगल रही है वह कृषक सड़क न होने के कारण अपने अनाज को रोपनी उपज को सही तरह से मार्केट तक नहीं ले जा पाते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी इस सड़क को बनवाने का कष्ट करें।

दूसरा मान्यवर, एक सड़क हमारे यहां स्वीकृत हुई विनावर बिलहत कानना गला। यह भी पूरी नहीं है इसको पूरी करा दें। मान्यवर, एक सड़क हमारे यहां नौरंगाबाद–व्योर है इसको भी पूरी करा दें। यह भी अपूर्ण है। एक सड़क ग्राम नौरंगाबाद से विनावर बदायूं पक्की सड़क तक। यह भी अपूर्ण है इसको भी पूरा कराने का कष्ट करें। एक सड़क गुरुपुरी से रहेमा विनावर तक स्वीकृत है यह भी अपूर्ण है। इसको पूरा कराने का कष्ट करें एक सड़क लाईफरीपुर से पक्की सड़क तक इसको भी पूरी कराने की कृपा करें। एक सड़क ग्राम रहेमा मिजामपुर, नरीशमतपुर, लाइफरीदपुर, बदायूं कुंवर गांव पक्की सड़क तक इसको भी पूरा कराने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं और इसलिये दिलाना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस (ई) पार्टी एकीकरण में विश्वास रखती है। मेरे सामने के दोस्त उसमें विश्वास नहीं रखते

[श्री मोहम्मद अबरार अहमद---]
हैं इनके पास सिर्फ भाषण है । यह सिर्फ भाषण देने में अपनी खूबसूरती समझते हैं । लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं जो कहते हैं । मान्यवर, आज आपके सामने स्पष्ट है कि आज देश का जो लीडर है उनमें माननीय श्रीमती इन्दिरागांधी ही एक ऐसी लीडर हैं जो एलानिया कहती हैं और एकीकरण का जो कार्यक्रम बनाया है वह ऐसा है कि अपोजीशन के लीडर उसको देखकर दंग रह गये हैं । उनके दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है करना चाहते नहीं सिर्फ कहना चाहते हैं । हम तो जो कहते हैं वह करते हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मौलाना मोहम्मद अली जौहर सोसाइटी है उसके लिये मंत्री जी से अनुरोध है कि लखनऊ में बैठने के लिये एक दफ्तर उपलब्ध करायें । मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के लिये और देश की आजादी के लिये अपनी जान दे दी तो उनकी याद में जो सोसाइटी है उसको राष्ट्रीय एकीकरण विभाग कुछ आर्थिक मदद दे और लखनऊ में दफ्तर उपलब्ध कराये । मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि स्टेट आफिसर को तुरन्त तबदील करने का कष्ट करें क्योंकि यह तमाम सदस्यों की भावना है और सबने यही मांग की है कि अगर आप इनको अच्छा समझते हैं तो इनको कहीं का गवर्नर बना दें परन्तु हमारा छुटकारा इनसे करा दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री ऊदल---

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण कैसे होगा, इसकी एक पुस्तिका बांट रखी है । वह डाक्टर और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, मैं बताने लायक नहीं हूं लेकिन मैं एक ही लाईन में पूछना चाहता हूं कि इस देश में साम्प्रदायिक भाषायें बढ़ाई जा रही हैं, मजहबी स्कूल चल रहे हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से लोगों को शिक्षा दी जा रही है और राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में पहले जो विषय थे वह अब गायब हैं, इसलिये जब राष्ट्रीय एकीकरण को तमाम विघटनकारी शक्तियां नष्ट करने को तुली हुई हों तो राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हो सकता है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिज कारपोरेशन ने विदेशों में और बैंकाक में बड़ा नाम कमाया है । आपके प्रतिनिधि बैंकाक में गये होंगे तो वहां सड़क के ऊपर से ब्रिज जो बना है उसको देखा होगा कि ट्राफिक जाम न हो सड़क पर इसलिये बड़ी चौड़ी सड़कें बनायी जा रही हैं जिसको आपके प्रतिनिधि ने देखा होगा कि यह कैसे सड़क और पुल बन रहा है । मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि आप भी वहां जायं और उसको देखें और उससे कुछ नतीजा हमारे देश और प्रदेश की प्रगति के लिये निकाल सकते हैं ।

मान्यवर, जहां तक मंत्री जी ने अरब देशों की बात कही तो हमारे भाई श्री रियासत हुसैन ने कहा कि वहां गलत काम करने पर हाथ काट लिये जाते हैं और चोरी वहां नहीं होती हैं जिससे वहां अच्छा काम होगा । मान्यवर, ब्रिज कारपोरेशन ने हमारे यहां एक पुल कालका धाम 10 वर्ष पहले बनाया है । आज तक वह पुल खुला नही है क्योंकि वह नीचा बना दिया गया है । श्रीमन्, बाढ़ सन् 58 में आयी और 68 में आयी लेकिन वह पुल इतना नीचा बना दिया गया जिससे उसको खोला नही जा सका और 4-5 लाख रुपया खर्च हो गया । आप देखें यहां की बात, या आप अरब कन्ट्रीज को देखेंगे । मेरी आपके प्रमुख अभियन्ता से बहुत बातें हुई हैं । आपके विभाग में अरबों रुपयों के सामान का कलेक्शन किया जाता है । 10,10 सालों से सड़कों के किनारे गिट्टी पड़ी हुई है । कोलतार के ड्रम पड़े हुए हैं और वह ड्रम हजारों की तादाद में पड़े हैं । ड्रम फट गये हैं और तारकोल बह रहा है लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है । तो आपने कभी इसके ऊपर चेकअप किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि बाराबंकी महमूदाबाद मार्ग के सम्बन्ध में कितने लोग उसमें सस्पेंड हैं। ए0ई0,जे0ई0; ई0ई0 मैंने उस सड़क में खराब माल लगा दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसी शिकायतें बहुत बड़े पैमाने पर मिलेंगी। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे बटेश्वर में जमुना नदी है वहां पर पुल की आवश्यकता है। बदायूं में गंगा नदी पर पुल की आवश्यकता है। बिहार का आरा डिस्ट्रिक्ट बलिया से जुड़ा है वहां पर घाघरा नदी पर पुल की आवश्यकता है। तो कम से कम एक सर्वेक्षण हो जाना चाहिये और सर्वेक्षण के बाद प्राथमिकता के आधार पर यह तय होना चाहिये कि कौन सा काम प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा। मैं अब केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। श्रीमन्, जौनपु0 जिले में दरियांव–पवांरा सड़क पर बसुई नदी पर पुल की बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह से वाराणसी में चौकाघाट पर जो पुल था वह क्रेक हो गया है जिससे रास्ता जाम हो गया है ार इसी तरह से एक बाईपास बाबतपुर–जमालपुर पर निकल रहा है। आधे किलोमीटर ।क बाईपास बनना था। 120 फीट तो शारदा सहायक नहर में चला गया है। अब 4 कि0मी का बाईपास निकाला जा रहा है। तो इस बाईपास में तमाम जमीन निकल जायगी तो इनर गरीब किसानों पर दया कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं औ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राज कुमार राय––

मान्यवर.....

श्री सुन्दर सिंह––

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहराइच जिला पिछड़ा हुआ है हमको समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठें।

*श्री राज कुमार राय––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। डा0 अम्मार रिजवी साहब ने जिस सूझ-बूझ से यह बजट अपने राज्य मन्त्री, उप मन्त्री और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से बनाकर रखा है उसके लिये उनकी जितनी सराहना की जाय वह कम है। मान्यवर, एक शेर है :

नहीं मोहताज गहनों का जिसे सूरत खुदा ने दी,
कैसा खूबसूरत लगता है चांद बिन गहने।

जो खुद ही बहुत समझदार, प्रबुद्ध और विवेकी हैं, उसी सूझबूझ से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। बहुत कुछ हमारे विपक्ष के भाइयों नेभ्रष्टाचार और अन्य मामलों के बारे में कहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजकुमार राय—]

मेरा अपना ख्याल है कि अब इस देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार अनुपात की बात तो की जाय किन्तु भ्रष्टाचार कितना है, इस पर विचार किया जाय लेकिन यह इस तरह एक्सटेम्पोर कहना कि फलां जगह भ्रष्टाचार है, उचित नहीं है। हमारी सारी जनता जानती है कि भ्रष्टाचार देश की नस नस में चलता चला जा रहा है, हमारा मोरेल ही ऐसा होता चला जा रहा है। जहां एक तरफ हम किसी विभाग की खामियों की बात करते हैं तो यह दायित्व हो जाता है कि उसकी खूबियों अच्छाइयों को भी लें। अभी रियासत हुसैन साहब न दो चीजों पर बहुत बड़ी आलोचना की है। एक तो नेशनल इण्टेग्रेशन के नाम पर मुरादाबाद का मसला लेकर जैसा कहा है, मैं समझता हूं कि उनकी स्पीच के बारे में 'फ्रीडम आफ स्पीच' होने के नाते चाहे कुछ न कहा जाय लेकिन वह इतनी आग उगलने वाली है कि उससे नेशनल इण्टेग्रेशन को धक्का लगता है। ऐसे वरिष्ठ सदस्यों से जिन पर इस प्रदेश का बहुत बड़ा बोझा है और नेशनल इण्टेग्रिटी का बहुत कुछ दारोमदार है, बहुत सोच-समझ कर कहना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं वैसे बीच में नहीं बोलता लेकिन मा0 सदस्य ने मेरे नाम से कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, जिसमें मेरी स्पीच जो रिकार्ड हो चुकी है और मा0 सदन ने सुनी है, उस समय किसी ने न तो आपकी चेयर से और न और किसी प्रकार से उस पर एतराज हुआ, मैं चाहूंगा कि ज्यादा अच्छा हो कि मा0 सदस्य मेरी स्पीच के उन अल्फाज को, जिन्हें वे आबजेक्शनेबिल समझते हैं, दुबारा सदन के अन्दर बतला दें ताकि मालूम हो जाय कि कौन से हिस्से पर उनको एतराज है।

श्री राजकुमार राय—

जहां तक उसमें गड़बड़ी है कमियां हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्रिज कारपोरेशन और निर्माण निगम ने ऐसे काम किये हैं कि अगर हम एक-एक का लेखा-जोखा लें और विशेष ताओं का उल्लेख करें तो यह सेतु निगम और निर्माण निगम ऐसे नाम हैं, जिन्होंने इस प्रदेश की शान को बढ़ाया है।

मान्यवर, अगर हम माननीय रियासत हुसैन साहेब के इस तथ्य से इत्तिफाक करें तो चूंकि इस्लामिक कन्ट्रीज में कानून बहुत कड़ा है और इसके बावजूद भी हमारे इंजीनियर्स ने जाकर वहां पर अच्छा काम किया है। आप नैपाल को ले लीजिये, हमारे पड़ोसी जयपुर को, दिल्ली को और एशियाई खेलों के लिये आप क्या कहेंगे?

श्री रियासत हुसैन—

एशियाई खेलों के नाम पर ही तो सीमेंन्ट वहां लगाया जा रहा है, यह हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बात है।

श्री राज कुमार राय—

इसके लिये मान्यवर, इतने उदाहरण हैं कि ब्रिज कारपोरशन ने हमारे उत्तर प्रदेश की शान को बढ़ाया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिये।

श्री राज कुमार राय––

बस मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में नेशनल हाई वे 29 जाती है। उसके संबध में निवेदन यह करना है कि उसकी हालत बहुत खराब है। वहां पर हैवी लोड के कारण, जो रोड बनाने के लिये रोलर उस पर ले जाते हैं, मान्यवर, उनका लोड करीब 12–14 टन तक होता है। उस पर से ट्रकें जाती हैं जिनका वजन कम से कम 20–20 और 25–25 टन के होता है इसके कारण बड़ी जल्दी टूट-फूट हो जाती है, उसके मरम्मत की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में देवरिया, गोरखपुर तथा आजमगढ़ यह चीन के बार्डर से लगे हुए हैं। उनकी सड़क के मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है।

इसी तरह से चकउ–बस्ता रोड जो कि आजमगढ़ में है उसके मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। दुबारी की ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उस गांव में खड़ंजा बिछवाने का काम कराने का कष्ट करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, माननीय वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, लोक लेखा समिति के समक्ष आपका जितना लेखा-जोखा है श्रीमन्, आपने उसमें हिस्सेदारी की है। उसका लेखा-जोखा मैं यहां नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता––

आप केवल विषय पर ही बोलिये और समय के अन्दर ही अपनी बात को समाप्त कर दीजिये।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट––

उसके लेखे-जोखे को मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा और मैं मान्यवर, समय के अन्दर ही अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा और केवल दो-चार बिन्दुओं पर ही अपनी बात को सीमित रखूंगा क्योंकि आपने समय निश्चित कर दिया है।

मान्यवर, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने जनपदों की और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सड़कों के निर्माण के बारे में बल दिया है। जन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और अपने क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के बारे में बल दें। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से उस ओर दिलाना चाहता हूं, उस क्षेत्र के विकास के के लिये मंत्री जी से मांग करता हूं जो क्षेत्र बीहड़ है। उस क्षेत्र को जो बीहड़ है उसको ठीक से एप्रोच करने की नीयत से आप वहां पर सड़कों का निर्माण कराइये क्योंकि वहां पर सड़कों के निर्माण न होने कारण पूरे प्रदेश की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। साफ कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि पूरे प्रदेश के अराजक तत्व वहीं पनप रहे हैं, दस्युओं के गिरोह के गिरोह उस एरिया में जाकर पनाह लेते हैं। वहां पर पांच-पांच नदियों का संगम है और जिसके कारण बियाबान जंगल है और बीहड़ पड़ा हुआ है। जहां सभी डाकू जाकर विश्राम करते हैं। निवेदन है कि उस एरिया को आप एप्रोचेबिल बनाइये। आप ही हेलीकाप्टर

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट--]

से वहां गये थे तो आपके हेलीकाप्टर को ही लोगों ने वहां पर घेरने का प्रयत्न किया था--- तो श्रीमन्, आपके शासन का यह हाल है कि हैलीकाप्टर से नहीं देख सकते तो अगर वहां पर डकैती, मर्डर हो जाये तो कैसे उम्मीद करते हैं कि पुलिस उस घटना की सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंच जायेगी।

उस भिण्ड की धरती की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू जिसकी एक-एक बस्ती कच्ची, पक्की सड़कों से लिंक्ड है और उसी के पास सिंडौस, लेलूपुरा, चौरेला गढ़ीमंगल, कचेहरी, आदि, आदि जो गांव हैं वहां कोई घटना घट जाये, चाहे जितना प्रयास करें आपका जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने विधिवत् 3-3, 4-4, 5-5 पन्नों में मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है कि जमुना पर, चम्बल पर, क्वारी पर, जहां कच्ची और पक्की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है, निर्माण करायें। पक्के पुलों के स्थान पर, यदि सम्भव न हों तो, पैटूनब्रिज ही बनावायें। आपने दुहाई दी और आपने अपना सर ऊंचा करते हुए उनको बधाई दी ब्रिज कारपोरेशन के लिए, मैं भी अपने आपको आपसे सम्बद्ध करता हूं, लेकिन जो विदेशी मुद्रा इस देश, प्रदेश को प्राप्त होती है, क्या सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट को प्रेस नहीं कर सकते कि अपर्याप्त बजट जो मिलता है, उसमें बढ़ोत्तरी की जाये ? आपके पास आधार है कि आप से ब्रिज कारपोरेशन इतना पैसा लेता है, उसी आधार पर पैसा मिलना चाहिए। ऊदल जी ने भी इशारा किया,मैं उनसे भी अपने को सम्बद्ध करता हूं, जो कारपोरेशन विदेशों में नाम कमा रहा है, वही उत्तर प्रदेश में 5-5, 10-10 वर्षों में पुलों को पूरा करे, मैं समझता हूं यह लज्जाजनक बात है। और भी बातें कहनी थी मान्यवर, लेकिन जैसा अभी लाल बत्ती दिखाई, इसलिए राष्ट्रीय-एकीकरण पर अपने को सीमित करता हूं। मैं इस दिशा में कुछ अधिक नहीं कहूंगा लेकिन समाज के दबे, पिसे, गरीब लोगों को भी यदि इंसान की जिन्दगी देना चाहते हैं गरीब, हरिजनों, मुसलमानों, दूसरे लोगों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठायें, तभी राष्ट्रीय एकीकरण कर सकेंगे नहीं तो श्रीमन्, उनके इंकार की एक आवाज पूरे प्रदेश को समाप्त करके रख देगी जिसे आप बन्दूक से बन्द नहीं कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा, फसीले आतिशेआहन बहुत बुलन्द सही, बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा, नये ख्याल की परवाज रोकने वालों, नये आवाम की तलवार कौन रोकेगा।

श्री मुईद अहमद--

आज पी0 डब्लू0 डी0 और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग पर जो बजट हमारे मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव को ध्यान से सुन रहा था, वह एक निन्दा का प्रस्ताव था या बिल्कुल हवाई भाषण था, इसमें सुझाव के रूप में एक बात नहीं मिली। जो बजट मंत्री जी ने रखा, उसकी जो आवश्यकता महसूस हो रही है, उसको देखते हुए इस तरह की बातें रखीं उससे लगता है कि जो धन आवंटित किया गया है वह प्रदेश की व्यवस्था, तरक्की, सड़कों के मामलों को देखते हुए बिल्कुल नगण्य है, बजट इसका दोगुना होना चाहिए तभी प्रदेश का हित हो सकता है। पी0 डब्लू0डी0 विभाग एक ऐसा विभाग है जो चाहे सड़क हो, चाहे इमारत हो, चाहे पल हो,चाहे पुलिया हो सबका निर्माण इस पर निर्भर है मगर प्लानिंग कमीशन ने इसे अनप्रोडक्टिव कहकर इसके बजट में कटौती करता चला जा रहा है। पी0डब्लू0डी0 विभाग

द्वारा जो पुल बनते हैं, जो इमारतें बनती हैं सब पर पी0 डब्लू0 डी0 विभाग का योगदान रहता है। सड़क से आय रोड टैक्स के रूप में आती है। पी0डब्लू0डी0 विभाग का एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में मा0 मंत्री जी पर नैतिक दायित्व केवल सात माह से आ रहा है। इससे पहले इसके कारनामे के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। इसको काजल की कोठरी कहा जाता रहा है और इस कोठरी में जो भी घुसता है उस पर कालिख लगती है। जैसा कि मा0 बाजपेयी जी ने कहा कि एक अधिकारी को तरक्की नहीं दी गई तो उसने किस तरह से राजनीतिक दांव-पेंच लगाये, किस तरह से एक दूसरे का चरित्र हनन किया यह एक ऐसा विभाग है इसमें यह काम अच्छा किया गया कि एक लाख से ऊपर की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके उसको राजकीय निर्माण निगम को सौंपा जा रहा है मगर जो ठेकेदारी की प्रथा है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा जूनियर इन्जीनियर और एसिस्टेन्ट इन्जीनियर पहले से अपने लोगों को बुलाकर टेंडर भरवाते हैं। वही रेट भरवाते हैं और दूसरे आदमियों को मना कर देते हैं कि आप मत भरिए। जब इस पर अंकुश लगता है। तो यह लोग जबरदस्ती टेंडर भरवाते हैं और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के सीने पर कट्टा रख कर पेमेंट करवाते हैं। अगर कहीं कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी मिल गया जो ऐसा नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर करवाते हैं उसको बेइज्जत करते हैं उसको गाली दिलवाकर, उसको मरवाकर यह उस कार्य को करवाना चाहते हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस तरह की बातों को और ठेकदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए। यदि इस पर मा0 मंत्री जी द्वारा ध्यान दिया जायगा तो निश्चित रूप से इससे सुधार होगा इससे एक डिपार्टमेंट स्टेट और उस स्टेट आफिसर के बारे में सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के मा0 सदस्य जानते हैं कि वह किस तरह का आदमी है। आज विधायक निवासों की क्या हालत हो रही है उसमें दीवालें गिर रही हैं, चूना गिर रहा है, पपड़ी गिर रही है। छत चू रही है, उसकी लिपाई पुताई नहीं हो रही है। मान्यवर, दरवाजों में जंजीर है। परन्तु उसमें पता चला कि दरवाजों में ताला लगा है उसकी एक चाभी उनके पास है और एक चाभी मेरे पास भिजवाई गई तो मैंने रजिस्टर पर लिख दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं चाभी नहीं लूंगा।

मैंने रजिस्टर में लिख दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिये मैं चाभी नहीं लेता। जो आलमारी भेजी गयी है उसमें आज तक चाभी नहीं लगती। इस तरह की आलमारियां और चाभियां भेजी जाती हैं। जब बल्व की मांग की जाती है तो दूसरे दिन बल्ब मिलता है। यहां पर सर के नीचे स्टेट आफिसर की यह हालत है तो देहातों में कहां तक सुधार आयेगा। इन शब्दों के साथ माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम नारायन तिवारी––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण देते हुए इस विभाग में ठेकेदारी प्रथा के उन्मूलन और उस पर अंकुश लगाने की बात कही है। उससे उत्साहवर्द्धन तो हुआ और यह बात मान्यवर, इस पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान कही। ठेकेदारी प्रथा से ठेकेदारों, राजनेताओं और विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के पास इतनी ज्यादा सम्पदा हो गयी है कि अब उनके सामने सवाल यह है कि उसको कैसे खर्च करें। दूसरी तरफ पूरे बजट भाषण में छोटे-छोटे कर्मचारी जो 15, 20 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम नारायन तिवारी–]

उनको नियमित करने का, उनको स्थायी करने का, उनकी देनदारी कम करने व उनके वेतन में समानता लाने के लिये कोई चर्चा नहीं की गयी। यद्यपि 27–28 हजार कर्मचारियों को नियमित किया गया है लेकिन अभी भी इस विभाग में कई हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो 20 वर्ष से लगातार काम करते रहने के बाद भी अभी तक नियमित नहीं किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने भाषण में इस बात का आश्वासन अवश्य देंगे कि उनको यथाशीघ्र स्थायी व नियमित कर दिया जायेगा।

दूसरी बात यह कि हमारा प्रदेश एहसान फरामोश नहीं है। माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो काम किया है उसके लिये उनकी तारीफ भी होनी चाहिये। एक बार की बात है कि एक सज्जन मेरे साथ जा रहे थे उनसे मैंने पूछा कि आपकी तारीफ क्या है तो पता लगा कि वे अधीक्षण अभियन्ता थे। मैंने पूछा कि आप कृपा करके बतलायें कि आपने कितने पुलों का निर्माण किया। उन्होंने बतलाया कि 5 पुलों का। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें आपको कितना रुपया मिला तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। मैंने कहा कि दो ढाई परसेंट से कायदे से लिया ही होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमारा देश और प्रदेश इस बात के लिये माननीय मंत्री जी का एहसानमन्द है कि उन्होंने हमें 5 पुल दिये। हमारे प्रदेश को सड़कें भी मिली, इसके लिये भी हम एहसान-मन्द हैं लेकिन इसके बाद छोटे कर्मचारियों का क्या होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस सिलसिले में अपने उत्तर में बतलायेंगे।

अब मैं राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गुडबिल क्रिएशन करने की बात कही जाती है इसका मतलब है धर्म-निरपेक्षता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना। जाति-पांति के नाम पर झगड़ा फिसाद करना, हिन्दू राष्ट्र के नाम पर महा गठबंधन की योजना बनाना और तमाम तरह की साजिश करना, यह देश का इंटेगरेशन नहीं बल्कि डिसइंटेगरेशन है। हमारे राष्ट्र और प्रदेश को इस बात को समझना चाहिये। हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय परम्परा एक शानदार परम्परा रही है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारा देश राष्ट्रीय एकीकरण धर्म-निरपेक्षता में आगे बढ़ा है। गुडविल क्रिएट करने का मतलब है धर्म-निरपेक्षता के प्रति संवेदनशील होना और दृढ़ प्रतिज्ञा होना। इसके लिये हम इतनी सतर्क हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर महा गठबंधन बनाने की जो साजिश चल रही है और जो इस तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं उनसे हम सतर्कता से देश की रक्षा करेंगे और सतर्क होकर के इस साजिश का मुकाबला करेंगे।

एक सुझाव पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, सड़कों की चर्चा हुई। मान्यवर, एक राष्ट्रीय मार्ग है लखनऊसे होते हुए गोरखपुर नौतनवां से लासा तक तथा पैकिंग तक चला जाता है। चीन से मान्यवर, दो–दो टैंक एक साथ काठमांडू पहुंचे होंगे लेकन इस राष्ट्रीय मार्ग से एक टट्टू अगर चला जाय तो यह टूट-फूट जायगा। इस राष्ट्रीय मार्ग को ठीक करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जितने सार्वजनिक निर्माण मंत्री हुए एक मरतबा आजमगढ़ की सारी जिला परिषद् की सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ले ली गयी और एक बार इलाहाबाद में ले ली गयी। मान्यवर, इस तरीके से सड़कों के निर्माण में समता नहीं है विषमता है। इस विषमता को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि कम से कम पांच किलो मीटर, दो किलोमीटर निर्धारित करके मिट्टी सड़कों पर डलवा दें। यह बड़ा काम होगा।

श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग क अनुदानों तथा राष्ट्रीय एकीकरण के अनुदानों पर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पहला ही अनुदान राष्ट्रीय एकीकरण का है। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं। हमार विरोधी पक्ष से विरोध में कुछ बातें आयीं विशेष रूप से दो बातें एक उर्दू की समस्या और एक बात माननीय रियासत हुसैन साहब ने कही मुरादाबाद में हरिजनों से संबंधित। उर्दू की समस्या पर हमारा व्यापक दृष्टिकोण है और उस व्यापक दृष्टिकोण पर मैं चार पंक्तियां पेश करना चाहता हूं--

हरसाना को खमदार गेसू से मतलब
मुसलमां से मतलब न हिन्दू से मतलब
ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी
न हिन्दी से मतलब न उर्दू से मतलब

हम इस भावना से हिन्दी उर्दू के बीच सेतु निर्माण कर रहे हैं। दोनों तरफ से बीच में सेतु निर्माण कर रहे हैं। यह हमारी भावना है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण का मुख्य कार्य मार्गों से संबंधित है। बहुत से और भी खंड हैं लेकिन हमारी सारी जनता और गांवों के निवासी मार्गों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब से मानव ने झोपड़ी बनानी शुरू की होगी तब से रास्ते का निर्माण भी शुरू किया गया होगा। इसका ऐतिहासिक महत्व है और इतिहास में शेरशाह सूरी ने एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कराया था। उसके नाम पर माननीय मंत्री जी ने एक सड़क का नामकरण भी किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने समय में कुछ ऐसे परिवर्तन, ऐसे कार्य करें, कि उनका नाम भी अमर रहेगा। बहुमुखी प्रतिभा के हैं। हर एक चीज को बड़ी सूझ-बूझ की ढंग से सुनते हैं। मैं एक शेर माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत कर देना चाहता हूं--

चमन में तुम से रौनक है, बहारें तुम से जिन्दा हैं,
तुम्हारे सामने फूलों को मुरझाया नहीं जाता।

तो ऐसे हमारे जनप्रिय मंत्री हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अवश्य ही ऐसा काम होगा। इन मार्गों से हमारे देश की प्रगति जुड़ी हुई है। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ अनियमिततायें हैं। मैं दोनों तरफ इशारा करना चाहता हूं। मजबूरियां तो यह हैं कि इस विभाग को अन्य कई दैवी आपदाओं का सामना करना पड़ा, जैसे पिछले दो साल में भयंकर बरसात हुई और सारी सड़कें पानी में डूब गई।

दूसरी बात यह है कि ये सड़कें पुराने ढंग से निर्मित की गई थी, उनका डिजाइन पुराना था और उनके ऊपर भारी भरकम ट्रकें और बसें चलने लगीं जिससे वे खराब होती गई। तीसरा कारण नहर हैं। जो नहरों का डिजाइन किया गया, वह सड़कों के ऊपर से किया गया। सुल्तानपुर-लखनऊ मार्ग पर मान्यवर, आप देखेंगे कि सड़क तीन फिट नीचे हैं और नहरें ऊपर हैं, इनसे भी सड़कों का नुकसान हुआ है। इन सब बातों के साथ ही साथ अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र दो नदियों से घिरा हुआ है। मढ़हा-बिसुई मार्ग पर 40 गांव आते हैं। उनमें कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। पिछली सरकार ने इसके बारे में कोई भी काम नहीं किया है। उसमें केवल एक पुल मंजूर किया गया है जब कि वहां पर पांच पुलों की आवश्यकता है। इन पूलों के लग जाने से वहां के गांवों के लोग अपनी दवा वगैरह के लिये बाजार जा सकते हैं। दूसरा नारायणपुर का पुल है, जिसको मैं चाहता हूं कि सरकार अतिशीघ्र बनायें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो माननीय वर्मा जी ने देवरिया जिले में रुद्रपुर देवरिया मार्ग पर सन् 77 में जांच हुई थी विभाग द्वारा और इन्टैलिजेंस द्वारा। उसके बारे में विभाग ने कहा था कि यह सही है कि सड़क बनी है लेकिन इन्टैलिजैन्स ने कहा था कि सड़क नहीं बनी है। उसका असर यह हुआ कि उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई लेकिन जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की गई थी, उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और वह विषय आज तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ है।

दूसरे हमारे यहां खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो मार्ग बने हुए हैं और जैसा कि शासन के आदेश हुए हैं कि हर दो हजार की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जायेगा, वह भी नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उस कार्य को पूरा किया जाय। मान्यवर, देवरिया गोरखपुर रोड पर एक नकटा नाला है उस पर जो पुल बना हुआ है, वह बहुत ही संकरा है, वह बाढ़ के कारण आधा टूट गया था उसको बनवाने के लिये 2/3 सालों से रुपया भी मंजूर है लेकिन वह पुल नहीं बन रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वह पुल बनाया जाय। देवरिया में सड़कों की जांच के लिये यहां से दो बार पी0ए0 सी0 भी गई थी, लेकिन वह भी वैसे ही लौट आयी। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से देवरिया—महवारी मार्ग पर सन् 52 से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उस पर रोडवेज की बसे चलती हैं। इसी तरह से खुखुन्दू से भट्टी की सड़क है, वह भी नहीं बनी है इसी तरह से मैधरनाघाट से भवनी का इलाका है।

रुद्रपुर का इलाका इतना बीहड़ इलाका है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर 4 नदियां आकर बहती हैं और उस इलाके से भूतपूर्व मंत्री डा0 सीताराम निर्वाचित होकर आते थ उसमें तब से लगातार प्रयास हो रहा है कि पीड़ाघाट पर पुल बनाने की कार्यवाही हो लेकिन वह नहीं बन पाया है। अगर यह पुल बन जाय तो गोरखपुर और देवरिया का विकास हो जायेगा।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

भटना से मीनारी एक सड़क बनी है उसकी सोलिंग हुई है लेकिन उसमें इतने रद्दी ईंटे लगी कि वह सब टूट गयी हैं। इसकी जांच मैं चाहूंगा सी0आई0डी0 से करायें। मैं चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े गांव हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ने का काम होना चाहिये। हमारे यहां एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शर्मा हैं जो बूढ़े हो गये हैं और रिटायरमेंट के नजदीक हैं वह बहुत घपला कर रहे हैं इसलिये उनके कार्यों की जांच कराने की कृपा करें।

पुर्नवा नाला पर बना पुल जो था पिछले साल की बाढ़ में उसका एक हिस्सा धंस गया लेकिन वह नहीं बन पा रहा है उसके न बनने से आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहां तीन आदमियों की मृत्यु हो गई है इसलिए उस पुल को बनाया जाय।

1976 में जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी तो हमारे यहां एक सड़क गौरी-बाजार से 7 कि0 मी0 लम्बी है उसके लिए ईंटे मंगाई गयी लेकिन वह बन नहीं पायी और जो ईंटे थे वह गायब हो गये। पूर्वी जोन का अधिकारी बनारस में बैठता है मैंने उसको बार-बार लिख कर दिया एक बार उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं लेकिन 6 साल हो गये न वह आये और न सड़क बनी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठेकेदारी प्रथा जो है उसमें गुन्डे किस्म के लोग ठेका ले पाते हैं। वहीं दो तीन आदमियों के नाम ठेके दिलवा देते हैं और अपने रिश्तेदारों को ठेका दिलवाते हैं अगर कोई दूसरा ठेका लेता है तो उनका काम चलने नहीं देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बिहारी लाल--

(डा० बृज किशोर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र से किसी आदमी को बोलने का मौका नहीं मिला। हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मौका मिलेगा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री डा० अम्मार रिजवी साहब निश्चित रूप से सादगी और सौम्यता के प्रतीक और विद्वता के सागर हैं उन्होंने जो 204 करोड़ का बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह रकम बहुत छोटी है इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसलिए मान्यवर, इस 204 करोड़ की रकम पर जो हमारे उधर के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे उन्होंने तमाम अधिकारियों के ऊपर छींटाकसी की। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस भयावह स्थिति में यह बजट प्रस्तुत हुआ है, तमाम बजट का पैसा विभागों में बटेगा तो जिस अधिकारी को जितना पैसा दिया जायेगा वह उतना ही खर्च कर पायेगा। हमारे सम्मानित सदस्य जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि अधिकारी बहुत खराब हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ज्यादा धनराशि देने की कृपा करें तो अधिकारी विधायकों के सुविधा के अनुसार सीमेंट क्या लोहे की सरिया लगा देंगे।

मान्यवर, कुछ कहने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा "वह गांव का पनघट हो या शहर का मयखाना, तूफाने हवादिश में गुम है, सभी अफसाने"। मैं अपने एक सम्मानित सदस्य के बारे में कहना चाहूंगा कि कोई उसका काम होता होगा तो वह छबिराम का रूप धारण कर लेता है। मैं जो कह रहा था-तूफाने हवादिश में गुम हों सभी अफसाने, आगाज तो जाहिर हैं, उजड़े हुए चेहरों से। इस दौरे तरक्की का अंजामे खुदा जाने। सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश का प्रमुख विभाग है, प्रमुख विभागों का एक माना हुआ अंग है और किसी भी देश और प्रदेश को शक्तिशाली बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि उस देश में परिवहन के चलने के लिये अच्छी से अच्छी सड़कें हों। मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य से यह आग्रह करना चाहूंगा जो कि निश्चित रूप से स्वस्थ है, बुद्धि के विषय में मैं नहीं जानता, वह जनता के बीच से आए हैं, जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीद और आशा लगाकर भेजा है कि वह माननीय मंत्री जी से और कटौती न करवायें बल्कि उनसे और अधिक धन की मांग करवाइये, ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके। यहां की जनसंख्या 10 करोड़ कुछ लाख है यानी 11 करोड़ के करीब है। 204 करोड़ का इसका बजट केवल है। अब कितना अधिक काम इससे करना है। सन् 73 में सेतु निगम का निर्माण हुआ है और उसके बाद कितनी बुद्धिमत्ता इस विभाग की है, कितने इन्टलीजेंट लोग इसमें हैं कि आज उत्तर प्रदेश में ही केवल नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह तरक्की के

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र---]

रास्ते पर दिन प्रति दिन आगे बढ़ता जा रहा है। 75 में निर्माण निगम का जन्म हुआ था। जबकि पहले प्रदेश के 6 पूर्वांचल के जिलों में जनसंख्या संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अब आप देखे वह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया है। इसमें भारत सरकार का भी योगदान है।इसलिए दिया गया है कि पहले स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर और टेक्नीशियन उस काम को करने में सक्षम नहीं पाये जा रहे थे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इतनी बखूबी से इस काम को किया है कि वह बराबर तरक्की के रास्ते पर चला जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग नें 13 राष्ट्रीय सड़कें हैं- यह सड़के लखनऊ से दिल्ली जाती हैं, लखनऊ से गोरखपुर जाती हैं, यह सड़क लखनऊ से सुलतानपुर होते हुए वाराणसी को जा रही हैं,इसी प्रकार की अन्य सड़के हैं।देश को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, उत्तरप्रदेश का उत्थान करना है,यहां इन्क्लाब पैदा करना है,नई क्रांति पैदा करनी है तो उसमें यह 204 करोड़ रुपये का बजट निश्चित रूप से कम है।

अतः मैं अपने मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस बजट में संशोधन करके कुछ पैसा और इसमें खर्च करने की कृपा करें, ताकि देश और प्रदेश की तरक्की और उत्थान हो सके।

एकीकरण के बारे में तमाम साथी बोल रहे थे। इसके बारे में, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक तरफ राष्ट्र को एक रूपता में ढालने की कोशिश की जा रही है और जब हिन्दुस्तान की नेता, श्रीमती इंदिरागांधी, जिसने कभी किसी जाति किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं रखा है, उस देश में वहां पर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अंत में मैं एक शेर अर्ज करता हूं :

ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी।

इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट का जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

(घोर व्यवधान)

(श्री हरगोविन्द वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जो सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग कृपया बैठ जाइये।

(श्री मित्रसेन और श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

माननीय मित्रसेन जी आप बैठें जाइये।

(इस बीच श्री जसवन्त सिंह विष्ट बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

मान्यवर, मैं इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का घोर विरोध करता हूं। (इसके उपरांत श्री जसवन्त सिंह विष्ट ने बजट की एक पुस्तिका फाड़ दी।)

(व्यवधान)

(श्री हर गोविन्द वर्मा का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

कई सदस्य––

आप कृपया समय बढ़ा दीजिए? यह पहले से प्रथा रही है कि माननीय सदस्यों की प्रार्थना पर समय बढ़ाया गया। (घोर व्यवधान)

श्रीअध्यक्ष––

आप कृपया बैठ जायं।

[4 बजकर 54 मिनट]

*श्री हर गोविन्द वर्मा––

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि इनडायरेक्ट रूप में सत्तारूढ़ पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है क्योंकि माननीय श्याम लाल बाजपेयी और अन्य साथियों ने एक तरीके से जो बातें मैंने कहीं थीं कि इस विभाग के अन्दर जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उसका समर्थन किया है। सभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस विभाग को और धन दिया जाय लेकिन अगर अधिक धन किसी पात्र को दिया जाय तो ठीक है। ये तो ऐसे पात्र हैं जिसमें आज बदबू आ गयी है। इसलिए पैसा अधिक देने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने आज 34 वर्षों के शासन काल में इस प्रदेश के गांवों की तरक्की का कोई काम न किया गया है। गरीबों को उठाने का काम नहीं किया गया।

एक बात यह कही गयी कि सेतु निगम ने बड़ी ख्याति पायी है और फारेन एक्सचेंज प्राप्त किया है। 2 करोड़ रुपया बहुत मामूली रुपया है। अगर इस सरकार ने अपनी 34 साल में साढ़े 31 वर्ष जो शासन किया, उसमें विदेशी मुद्रा को बचाने का ही काम किया होता तो आज करोड़ों रुपयों की बचत हो गयी होती। अगर देश और प्रदेश में पैदावार को बढ़ाया गया होता तो विदेशों से अनाज मंगाने की जरूरत न पड़ती। आप इस 2 करोड़ की विदेशी मुद्रा के लिये सेतु निगम को बधाई देते हो और करोड़ रुपया बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च करते हो। यह कितने शर्म की बात है। अगर आपने गांवों को शहरों से जोड़ दिया होता सड़कों के द्वारा, अगर किसान आज सक्षम होता, अगर उसको अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकता होता, तो आपको विदेशों से गेहूं मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज करोड़ा रुपया आप गेहूं विदेशों से खरीदने पर खर्च कर रहे हैं और इस 2 करोड़ की विदेशी मुद्रा का ढोल पीट रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द वर्मा–]

आज जरूरत इस बात की है पहले गांवों की सड़कों द्वारा शहरों से जोड़ा जाय । गांव में पहले सड़के बनाई जायं ।

जहां तक रास्ट्रीय एकीकरण की बात की गयी है मेरा निश्चत मत यह है कि राष्ट्रीय एकता की भावना अगर इस सरकार में रही होती तो आज देश की यह स्थिति न होती । आज देश इस हालत में न होता । इन 34 सालों में राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम इस सत्ता कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है,पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है ।आज जगह-जगह हरिजन मारा जा रहा है । राष्ट्रीय एकता को तोड़नेका काम आप कर रहे हैं ।जो पैसा आपने इस विभाग के लिये मांगा है वह केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और उनके कार्यों पर खर्च होगा ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि यह प्रस्ताव जो है मंत्री जी का, उसका विरोध जिन माननीय सदस्यों ने किया है और जो हमारा कटौती का प्रस्ताव है, उसके समर्थन में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । मान्यवर, मैं अपने उन साथियों को भी बधाई देता हूं जिन साथियों ने इनडायरेक्ट रूप में मंत्री जी के साथ बैठकर हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है। मान्यवर, हमारे बाजपेयी जी ऐसे लोगों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन भी किया इसलिये अन्त में उन्हे याद आई दिल्ली के तानाशाह की । परन्तु उन्होंने अपने भाषण में प्रस्ताव बदल दिया और मक्खन लगाने का भी काम कहीं-कहीं पर किया है कि कहीं हमारे ऊपर डंडा न चल जाय । प्रदेश की जनता ने आपको विधायक और मंत्री बनाने का काम किया है । गरीबों की उठाने में, लोगों को गांव से शहर से जोड़ने का काम करें और राष्ट्रीय एकता के लिये जो विचार आपने रखे हैं, अगर सही माने में विचार हैं, जैसा कि कुछ हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि उर्दू के बारे में आपकी नियत साफ नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री का हवाला देकर कतराने का काम आपने किया । अगर राष्ट्रीय एकता की तरफ रुझान है, तो किसी तरफ झुक कर काम नहीं करना चाहिए । एक संकल्प लेकर काम करें । जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि हमारे मंत्री जी बहुमुखी हैं, बहुत तरफ हाथ मार देते हैं। यह आदत अच्छी नहीं है।

आज आप प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण के मंत्री हैं और उसके माध्यम से प्रदेश को बहुत कुछ दे सकते हैं और राष्ट्रीय एकता की बात आपने कह दी, राष्ट्रीय एकता के अन्दर उर्दू को भी आपने लाकर रख दी, मगर नियत साफ नहीं है । इसी दिन के अन्दर घोषित करो कि इस विचार के द्वारा काम करना चाहते हैं । आपने शहरीकरण और सुन्दरीकरण का बहुत सा काम किया । अभी गोमती के किनारे तमाम उत्सव मनाया जा रहा था,जबसे हमारे मंत्री जी आये हैं, तब से यह काम कर रहे हैं, जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का जो स्मारक बना है, उसमें काम हो रहा था कि मंत्री जी बहुत ही रंगीले मंत्री हैं । पिछले वर्ष महमूदाबाद में कोई काम हो रहा था, दिसम्बर या जनवरी का महीना था, उस समय इन्होंने पैसा पानी जैसा बहाया था । उस इलाके के जितने मुर्गे थे, वह सब कट गये । लखनऊ से मुर्गे वहां पर गये ।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, मुर्गे की बात इन्होंने कही कि वहां के मुर्गे सब कट गये । लेकिन मान्यवर, वास्तविकता आपके सामने है ।

(हंसी)

श्री हरगोविन्द वर्मा––

मान्यवर, मैंने इसलिए कहा कि उन मुर्गों को आपने किस तरह से काटने का काम किया । मान्यवर, मैं आपकी दृढ़ता के बारे में और योग्यता के बारे में जरा सा

भी सन्देह नहीं करता हूं। वहां पर आपकी फिलनलवादी प्रवृत्ति प्रवेश कर गयी है, जिससे कि आप निश्चित रूप से फिसल जाते हैं और यही कारण है कि इतने दिन से आपके पास वह विभाग है। आपकी निगाह उस पर जाती ही नहीं है। लेकिन विधान भवन के अन्दर जो आपके विभाग में करप्शन है, अगर उसी को देखकर सुधार हो जाता, तो बहुत अच्छी बात होती। मान्यवर, जो अनुदान का प्रस्ताव रखा है, यह तो अपने बाहु-बल के बूते, यह तो जनसमूह के बूते तो पास करा ही लेंगे। लेकिन मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसको पास हो जाने के बाद आप पूरे रूप से निगाह और कान खोलकर अपने विभाग के करप्शन को देखें और उस पर काम चलाने का काम करें। आपकी कलम नौकरशाही के हाथ से न चले आपके ऊपर गुण्डों की बन्दूक न रहे, बल्कि आपकी बन्दूक गुण्डों की पीठ पर रहे। मान्यवर, गृह मंत्री के पास कैसे गुण्डे पलते हैं, इसको आप जानते हैं। मान्यवर, आप जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जवाब दीजिये।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष —

वर्मा जी, आप बैठ जायं, व्यवस्था का प्रश्न है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके संरक्षण में संसदीय प्रणाली का गला घोटा जा रहा है और गृह मंत्री के लिये गुण्डा पालने का शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मान्यवर, यह असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव के उत्तर के बाद आप उत्तर दे रहे हैं आप नई बात न जोड़े।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री की पीठ पर किसी गुण्डे का रिवाल्वर न रहे जिससे फर्जी बिल और फर्जी बाउचर मंत्री क अधिकारी से पास कराने का काम करते हैं। यह गुण्डों के पालने का काम गृह विभाग का है इसलिये उनकी तरफ इशारा किया वैसे गृह मंत्री जी की कोई बात नहीं है। मान्यवर, आज जो प्रस्ताव हमने कटौती कर रखा है माननीय सदस्यों ने जो उसका समर्थन किया और इनडायरेक्ट वे में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने समर्थन किया उनको धन्यवाद देता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर दृढ़ हूं।

*श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने साथी, दोस्त एक जिले के रहने वाले और एक क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र के विधायक माननीय हरगोविन्द वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसपर जो माननीय सदस्यों ने राय दी है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी--]

माननीय वर्मा जी ने कहा कि श्याम लाल बाजपेयी ने सही बात कही और जब दिल्ली की बात याद आई तो एकदम रुख मोड़ दिया। आप उस वक्त सदन में तसरीफ रखे थे। जबरदस्ती कटौती का प्रस्ताव इनको रखने के लये कहा गया यह कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहते थे। मोहन सिंह और तमाम सदस्यों के कहने पर और जब इनको दिल्ली के तानाशाह का ख्याल आया तो खड़े हुये और पेश कर दिया। वरना 3 मिनट तक यह कटौती का प्रस्ताव नहीं ढूंढ़ पाये।

मान्यवर, यह योग्य व्यक्ति है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इनको तीन मिनट लगेगा एजेन्डे में कटौती का प्रस्ताव ढूंढ़ने में मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत इन्होंने की और बाजपेयी ने तो हृदय से और रोम-रोम से हमारे बजट का समर्थन किया है। माननीय वर्मा जी ने मेरे प्रति कुछ राय जाहिर की है उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेरे पड़ोसी है पुराने साथी है कुछ न कुछ असर आयेगा। जो मेरे बाहर जाने की बात कही गई मैं आपके माध्यम से सदन को और वर्मा जी को सूचित करना चाहूंगा कि ब्रिज कारपोरेशन के खर्चे पर मैं 2 बार नहीं एक बार गया हूं। एक बार मेरी धर्मपत्नी बीमार थी उनके इलाज के संबंध में गया था और लौटने पर ब्रिज कारपोरेशन का जितना काम हुआ उसको मैंने किया। अफसर जो हैं वह हवाई जहाज पर सफर करते हैं और यह कहा गया कि यह प्रदेश बहुत गरीब है। मैं समझता हूं कि यह प्रदेश बहुत गरीब है लेकिन हम लोगों को भी जो फर्स्ट क्लास में चलते है प्रथम श्रेणी में सफर नहीं करना चाहिये। तो मान्यवर, एक आदर्श इस तरफ शुरु करना चाहिये। कैसे मान्यवर, उन दूर स्थानों पर जाया जायेगा, मा0वर्मा जी इसमें कोई रास्ता बता दें कि ऐसी कौन सी बैलगाड़ी है जो तेजी से पहुंचा दे वरन् एक महीना सफर में ही गुजार कर दूर स्थान पर पहुंचे तो यह कौन सा सफर करने का तरीका होगा। इसलिये इसमें मैं उनका मार्ग दर्शन चाहता हूं। यदि अभी नहीं तो बाद में ही वह बता दें तो मैं उसको मान लूंगा।

मान्यवर, दूसरी बात कही गयी कि 1,120 रुपये वहां अधिकारियों को भत्ता मिलता है। मान्यवर, मैं कलकुलेट कर रहा था तो 1,120 रुपये का 31 दीनार होता है। वहां 24 दीनार का कम से कम होटल मिलता है और 80-85 दीनार तक सिंगिल रूम मिलता है बगदाद में 65 दीनार है, नया होटल 85 दीनार का है और 24 दीनार होटल का मिनिमम किराया है, उसके बाद 5 दीनार खाना और नाश्ते के लिये बचते हैं जबकि किसी में खाना 3 दीनार से कम में नहीं मिलता है जिसको श्री रियासत हुसैन और जो जाते हैं वह जानते हैं। तो मान्यवर, वहां हमारा जो मजदूर जाता है वह भी हवाई जहाज से जाता है, अधिकारी ही नहीं, हमारा मजदूर, टिक्नीशियन और मिस्त्री जो जाते हैं वह सब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। वहां वेतन 60 दीनार के करीब मिलता है, मेस, मेडिकल और ट्रान्सपोर्ट को मिलाकर 100 दीनार हो जाता है जो 3200 रुपये होता है और यहां चीफ सेक्रटरी या सीनियर आफिसरों का इतना वेतन है, यह वहां मजदूर को दिया जाता है। इसलिये जब हम कीमतों को देखते हैं तो जो बाहर का इंडेक्स है, मजदूरी का रेट है, उसको देखकर मा0 वर्मा जी बात करें या ऐसा कोई मार्ग दर्शन दें कि जिससे वहां 10 रुपये मजदूरी देकर काम चला सकें।

मान्यवर, इंडियन लेबर सबसे सस्ता है। बाहर की कंपनीज हिन्दुस्तान के लेबर को जानती हैं और यह भी जानते हैं कि 100 दीनार में किसी देश का लेबर नहीं मिल सकता है। मान्यवर, 15 हजार रुपये कहा गया कि टेलीग्राम्स में खर्च किये गये, तो उनको 15 हजार रुपये की सूचना गलत मिली है क्योंकि कहीं इससे ज्यादा रकम टेलीग्राम्स, डायरीज, कलेन्डर्स आदि के ऊपर, जो बिजनेस प्रोमोशनल एक्टीविटीज हैं, उन पर खर्च हुये है। इसलिये यदि किसी जगह 30-35 करोड़ रुपये का हम काम करते हैं तो 10-12 लाख रुपये बिजनेस प्रोमोशन में खर्च करते हैं तो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है।

मान्यवर, उसके बाद कुछ क्षेत्रों की बातें कहीं गयी और मैं माननीय हरगोविन्द वर्मा जी का भाषण गौर से सुना रहा था और यह भाषण जनता तक पहुंचेगा कि वह पुल और सड़कें जिनसे डाइरेक्ट पहले इनके क्षेत्र को लाभ होगा और उसके बाद दूसरे के क्षेत्र को लाभ होगा, लेकिन वह भी बात इनको पसन्द नहीं आयी और उन्होंने टीका टिप्पणी किया। मान्यवर, सड़कों के संबंध में बताया गया कि सड़कें जनता पार्टी के शासन काल में जो खाद्यान्न योजना में बनी थीं उन पर ईंटा लगा दिया जाय। यह क्रम 1977 में शुरु हुआ था और बराबर काम होता आया है। जिस समय खाद्यान्न योजना चलाई गयीं उसमें जहां-जहां बाढ़ और सूखा था, यह बात दूसरी थी कि सारी बाढ़ और सूखा जनता पार्टी के 3 साल के शासन काल में हुआ और सड़कें उसमें बनीं।

मैं समझता हूं कि मरम्मत और इन सड़कों का बाकी रहना जरूरी है। पूरे प्रदेश में जो सड़कें बनीं है वह किसी के जमाने में बनी हों मैं फीगर्स देना चाहता हूं कि खाद्यान्न योजना में 35,467 कि0 मीटर सड़कें बनी हैं। अगर हम इनको पक्का करें और पुलिया वगैरह बनायें तो मिनिमम 460 करोड़ रुपया खर्च होगा। हम इसका प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सड़कों की मरम्मत कर सकें और उन पर ईट या खड़न्जे बिछवा सकें। मान्यवर, इसके बाद माननीय रियासत साहब ने एक बात सड़कों के ऊपर रोक लगाने की बात कही थी। यह काफी गम्भीर समस्या है पहाड़ों में और कहीं कहीं प्लेंस में भी सड़कों के अगल बगल खड्ड हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब सड़क के निर्माण के लिये जो बजट प्राविधान किया जाता है वह बगैर रोक के किया जाता है। अगर कोई जगह विशेष पता चलता है तो उसको दिखवाया जाता है। माननीय ऊदल जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं कभी उनकी नीति पर और किसी चीज पर शुबहा नहीं करता वह उन लोगों में से हैं जो बड़े कांस्ट्रक्टिव सुझाव देते हैं। उन्होंने कुछ बातें बाई पास वगैरह के बारे में कही हैं। मान्यवर, मैं उनको देखूंगा और जो कुछ भी हो सकेगा उस सिलसिले में करवाया जायगा।

माननीय श्यामलाल बाजपेयी जी ने कुछ अधिकारियों के संबंध में और कुछ व्यवस्था के संबंध में बातें कहीं तो मैंने जैसा आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूं कि इस बजट में है मैं पूरे सदन का मार्गदर्शन चाहता हूं। यह क्लेम नहीं किया गया है कि जो कुछ रखा गया है वह लास्ट वर्ड है या विभाग के अन्दर टीका टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है या इसमें सब हरिशचन्द्र हैं। चाहे कोई भी सरकार हो चाहे यह पक्ष हो या वह पक्ष हो यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि एक विभाग में सब चीजें एकदम से आ गयीं। 108 साल पुराना यह विभाग है। सबसे पुराना यह विभाग है इसका एक इतिहास है। इतने बड़े विभाग में कुछ चीजें जरुर आयेंगी जनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जो कुछ सदन में कहा गया है मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान दूंगा और करुंगा।

मान्यवर, यह कहा गया है कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार है सरकार और मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। यह अजीब बात है कि आप इलेक्शन लड़कर सरकार हासिल नहीं कर सके और अब इस्तीफा देकर हासिल करना चाहते हैं। मुकाबला हुआ और जनता ने फैसला कर दिया है। "आसमां डूबे हुये तारों का मातम कब तलक"। मान्यवर, ठेकेदारों के संबंध में हमारे दोस्त ने कहा है। मैंने शुरु में ही कहा है कि निर्माण निगम और ब्रिज कारपोरेशन बनाने का मकसद यह था कि ठेकेदारी की जो प्रथा है वह समाप्त किया जाय। रियासत साहब ने कहा कि सबसे बड़ा कार्य जो था जमींदारी उन्मूलन था, प्रिवीपर्स का समाप्त करना था। माननीय रियासत साहब को कुछ बातें हमारी पसन्द आती हैं बहुत दिनों से पसंद आती हैं उनकी वह तारीफ कर दिया करते हैं।

श्री मसरूर जाफरी--

अधिकारियों के कमीशन के बारे में कह दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैं जरूर कह दूंगा । मैं कह भी दूंगा और मा0 मसरूर साहब समें आपको बड़ी जानकारी है कमीशन के बारे में आप सूचित कर दीजियेगा, उस पर भी कार्यवाही होगी । ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करना सही है । आज यह होता है कि सिण्डीकेट से बन गये हैं, गैंग से बन गये हैं , जो कि अधिकारियों की आलोचना करते हैं । कई मामलों में उनको धमकी दी गयी है और हत्यायें भी हुई हैं । हम देखते हैं कि किसी प्रकार से ठेकेदारी की प्रथा समाप्त की जाय ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जी ने गुस्से में आकर यह कहा कि एनुअल जरनल है, हिन्दी में भी है, अंग्रेजी में भी है , यह पार्टी आफिस में भिजवा दिया गया है, इसे सदन में नहीं दिया गया है । उन्होंने गुस्से में आकर उसे भी फाड़ डाला । उसे अंग्रेजी में इसलिये किया गया कि साउथ में और दूसरी जगहों पर टेक्निकल इनफारमेशन में आदान प्रदान हो सके ताकि हमारा रिसर्च इन्स्टीट्यूट क्या कर रहा है, दक्षिण में क्या हो रहा है, इसलिये यह मैगजीन है ।

इस तरह बहुत से दोस्तों ने बहुत सी चीजें रखीं । एक देवरिया की तरफ पुल का मामला मा0 हरगोविन्द जी ने उठाया । आज अजीब बात थी कि यह सीतापुर छोड़ते हुये चले गये और एक पुल की बात कही । मैंने लिखा है , जो कुछ मुझे याद है । जो बात यहां आयी है, मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है । अगर महत्वपूर्ण न होती तो इतने महत्वपूर्ण सदन में इतने महत्वपूर्ण सम्मानित सदस्य उसको न कहते । शासन और विभाग इस पर पूरी तरह से विचार करेगा और सीमित साधनों को देखते हुये, जो कुछ भी हो सकेगा, किया जायगा । राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा । फखरे आलम साहब ने मौलाना मुअज्जल साहब के बारे में कहा । 1857 की क्रान्ति में उनका बड़ा योगदान रहा है । उनकी डायरी वगैरह भी बनायी जायगी और अगर कोई योजना वगैरह प्रस्तुत करेंगे तो शासन उस पर विचार करेगा ।

यह भी कहा हमारे दोस्त ने कि लाखों रुपया राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ने पानी की तरह बहा दिया, तो 19 लाख 60हजार रु0 का शायद बजट है और कितना महत्वपूर्ण यह बिन्दु है । कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की बात होती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है । मैं कोशिश कर रहा हूं समझ जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों तकलीफ होती है । कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करेण्ट सा लग जाता है राष्ट्रीय एकीकरण के नाम से। शायद यह लोग कुछ मार्गदर्शन दे सकें । हमारा दृढ़ संकल्प है कि चाहे कोई खुश हो या नाराज हो जहां तक लोगों में आपस में सद्भावना पैदा करने का प्रश्न है, सरकार पूरी तरह से उसमें कटिबद्ध है । एक बात माननीय ऊदल जी ने कही थी कि शिक्षा संस्थाओं में जिस वक्त शुरू में बच्चा जाता है तो उसके दिमाग में जो जहर भर दिया जाता है उसका इलाज क्या है ? यह एक मौलिक प्रश्न है जो कि ऊदल जी ने कहा है । यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे भारतवर्ष की बात है । इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि वह कौन सी ऐजेन्सीज हैं, वह कौन सी संस्थायें हैं जो कैश डम्प वाली बात करती हैं उनके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हमारा भविष्य अन्धकार में न डूब जाय ।

माननीय रियासत हुसैन जी ने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि ब्रिज कारपोरेशन को जो मेरिट मिली है वह दोआबे की मिट्टी की सिफत है । उनकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं परन्तु मैं पूरी तरह से उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता जो कि उन्होंने कहा कि वहां के कानून सख्त होने की वजह से इंजीनियर्स नें काम अच्छा किया नहीं तो शायद वे न करते ।

मैं अपने इंजीनियर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में एक ही मिनट बाद दूसरी बात कही लेकिन जिस जगह वे काम कर रहे हैं वहां पर सजायें बहुत सख्त हैं इसलिये उन्हें वहां ईमानदार होना पड़ता है। उन्होंने इंजीनियर्स के आनेस्टी पर उनकी ईमानदारी पर ऐतराज किया है कि जहां पर 100 मिलियन लोग रहते हैं उनकी ईमानदारी पर इन्हें शुबहा है, इस बात पर मुझे ऐतराज है।

श्री रियासत हुसैन--

यह आप उल्टा कैसे समझ गये। मैंने यह कहा कि हमारे मिडिल ईस्ट की कन्ट्री में हमारा कारपोरेशन काम कर रहा है वहां कानून कड़े हैं जिसके कारण कोई चोरी नहीं कर सकता। यहां चोरी के कारण स्टैण्डर्ड आफ वर्क गिर जाता है। यह सही है कि उन मुल्कों में चोरी के लिये सख्ती है इसलिये वहां के वर्क का स्टैण्डर्ड अच्छा है।

श्री अम्मार रिजवी--

मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने खुद अपनी बात की पुष्टि कर दी कि वहां कोई चोरी नहीं कर पाता। कहना चाहते है कि करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। जहां 100 मिलियन लोग इकट्ठे हों तय है कि वे लोग ईमानदार हैं उनके सोचने का एक तरीका है, एक कोड आफ कन्डक्ट है, एक तालीम है जो उन्हें ईमानदार होना सिखाती है। हमारे इंजीनियर लोगों ने इसकी वजह से अच्छा काम नहीं किया है।

श्री रियासत हुसैन--

वे लोग अपनी तालीम की वजह से ईमानदार हैं इससे मैं इत्तिफाक करता हूं लेकिन आपके इंजीनियर्स भी उसी मिट्टी में रह कर वहां के कानूनों के अन्दर अच्छा काम कर सकते हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यदि उस देश में जांय जहां पर ऐसे कानून नहीं हैं। मान्यवर, आप दिल्ली में देखिये कि तीन फ्लाई ओवर एशिया 82 के लिये बना रहे हैं, उसका कंस्ट्रकशन दिल्ली में हुआ है, उसका कोई कम्पटीशन है क्या? केवल कंस्ट्रक्शन को ले लीजिये क्या कर्नाटक हुआ, गुजरात हुआ, दिल्ली हुई, यह इस देश के बाहर नहीं है जहां पर ब्रिज कारपोरेशन ने, उसकी एजेन्सियों ने काम किया है और कर रहे हैं।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

तभी तो नैनीताल में पुल टूट गया, जिसकी यह तारीफ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

बैठ रहा हूं परन्तु जो पुल टूट गया है तो क्या उसके बारे में न बताऊं?

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, कानून की सख्ती की वजह से यहां ईमानदारी आयेगी तो क्या यहां ईमानदारी के लिये हाथ काटने जैसा कानून बनना चाहिये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। ये तानाशाही चाहते हैं परन्तु मैं तो केवल इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी आप अपनी बात कहें।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक....

एक सदस्य—

मान्यवर, नैनीताल के पुल के संबध में 2 मिनट मुझे दे दें.....

श्री अम्मार रिजवी—

जो पुल की बात कही है उसकी सूचना मेरे पास है, उस पर कार्यवाही हो रही है। विधायकों की समस्या पर भी बात हुई, रियासत साहब ने, जो वहां का सिस्टम है, कहा कि केयर-टेकर वहां से हटाया जाय, तो जो शिकायत आयी हैं उन पर पूरी तरह से मैं एक कमेटी घोषित करूंगा और अपने इस सम्मानित सदन के सदस्य भी उसमें रहेंगे और उन तमाम बातों पर जांच करेगी ताकि सही बात सामने आ सके। श्याम लाल जी ने बात कही कि जिन क्षेत्रों में जो कार्य चल रहा है वहां के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हमरे विभाग के, वहां के सम्मानित विधायक को जहां पर कार्य चल रहा है, इन्सपेक्शन कराने ले जांय तो जब वे जायेंगे तो सारे अधिकारी जायेंगे। इस तरह से जो घटनायें आयी हैं उन पर पूरी तरह से, एक-एक बात बतायी जाये, यह संभव नहीं है....

श्री रियासत हुसैन—

मुरादाबाद में फर्जी मुकदमों के संबंध में, जो चल रहे हैं, कुछ कहें।

श्री अम्मार रिजवी—

सब चीजों की न तो घोषणा करना और न बताना ही संभव है क्योंकि समय की कमी है लेकिन आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिन समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया है, मैंने लिखा है, हमारे अधिकारियों ने वर्बेटिम नोट किया है, मान्यवर, आपके यहां तो लिखा ही गया है, पूरी गम्भीरता से, जिस पर यह हाउस डिजर्व करता है, विचार होगा। इन शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है मान्यवर, चले गये, कहीं हैं नहीं, देख लें मान्यवर, दिल से रखना नहीं चाहते थे, उनसे अनुरोध करता हूं और उपनेता, विरोधी दल से भी कि उसको वापस ले लें।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मंत्री जी एक बिन्दु पर रोशनी डालना भूल गये। शासक दल के विधायक ने यहां के स्टेट आफिसर के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप लगायें, उस पर प्रकाश डाल दें; हम लोग अभी अन्धेरे में हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

रोशनी तो बहुत सी उधर से आ रही है लेकिन मैंने एक बात कही कि जिन अधिकारियों के खिलाफ बातें कही गयीं हैं, उन पर गम्भीरता से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत स पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,63,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,66,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,30,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,21,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,21,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में 7 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक सूचना श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द और श्री अकबर हुसैन की दिनांक 22—2—82 की ग्राम विकाली, जनपद बुलन्दशहर में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में है वह वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है । शेष अस्वीकृत हुई ।

इस पर आप वक्तव्य कब देंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इस पर 4 तारीख को वक्तव्य दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इस पर 4 मार्च को वक्तव्य होगा ।

हल्द्वानी में एक हरिजन बस्ती पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा हमला करके क्षति पहुंचाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मद संख्या 13 पर माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिये पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री वक्तव्य देने जा रही है। कल हम लोगों ने यह घोषणा की थी कि गृह विभाग से सम्बधित जब भी कोई वक्तव्य होगा माननीया गृह मंत्री द्वारा उसको माननीय सदन के अन्दर हम लोग नहीं सुनेंगे जब तक कि माननीय मुख्य मंत्री यहां मौजूद न हों। इसके बावजूद आज भी माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं इसलिये माननीया गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य को हम लोग सुनने के लिये तैयार नहीं हैं इसलिये हम जनता पार्टी के सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री अकबाल हुसैन भी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री विद्या सागर नौटियाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद नैनीताल के हल्दवानी नगर के बाहरी।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

कल हम स्पष्ट कह चुके हैं कि....

(व्यवधान)

(श्री थम्मन सिंह गहलौत सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोती लाल देहलवी--

यह कहने के बावजूद कि माननीया गृह मंत्री सदन के सामने उत्तर नहीं देंगीं, आपके आदेश की अव हेलना हो रही है। कल हम लोगों ने कहा था कि अगर माननीय मुख्य मंत्री यहां नहीं रहेंगे तो हम लोग माननीया गृह मंत्री के वक्तव्य को नहीं सुनेंगे। इसलिये हम लोग माननीया गृह मंत्री के विरोध में सदन का त्याग करते हैं (श्री मोती लाल देहलवी अपने के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)।

(श्री केदार नाथ सिंह भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद नैनीताल के हल्द्वानी नगर के बाहरी क्षेत्र बरेली रोड पर स्थित कब्रिस्तान के पास की भूमि पर पिछले लगभग 14 वर्षों से कुछ हरिजन झोपड़ियां बनाकर चमड़े का कार्य करते आये हैं। वे लोग दिन में ही वहां पर कार्य करते थे और उनके स्थान पर समीप में ही नई बस्ती मोहल्ले में हैं। कुछ समय पूर्व वहां पर कुछ अन्य लोगों ने भी अपनी झोपड़ियां बना ली थी। उक्त भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुये लगभग 300-400 व्यक्तियों की भीड़ ने दिनांक 12-2-82 को सायंकाल लगभग ढाई-तीन बजे उक्त भूमि पर बनी कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप 5 झोपड़ियां जल गयीं। इस घटना में जली झोपड़ियों में से 3 झोपड़ियां हरिजनों की, एक झोपड़ी मुस्लिम व्यक्ति की तथा शेष एक झोपड़ी सिक्ख व्यक्ति की थी। उक्त घटना

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तथा फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर जाकर आग पर काबू पा लिया। उपरोक्त घटना के संबंध में 13 नामजद तथा 300-400 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/436 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध में 6 नामजद अभियुक्त दिनांक 13-2-82 को गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। शेष 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट न्यायालय को भेजी गयी। विवेचना प्रचलित है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

उक्त घटना से स्थानीय जनता में कोई असन्तोष अथवा उत्तेजना व्याप्त नहीं है तथा नगर में शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यह बात सही नहीं है कि हरिजन बेघर-बार होकर सड़कों पर पड़े हैं और शीत में ठिठुरते हैं। हरिजन अपने घरों में रह रहे हैं। उक्त घटना से प्रभावित परिवारों को तात्कालिक आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जा चुकी हैं।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, आप के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस घटना की रिपोर्ट किसने और कब की गई और किस क्राइम पर दर्ज हुई और फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग मौके पर कब पहुंचे ? कब्रिस्तान की कोई निशानी मिली ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह घटना 15.30 बजे की है। 15.50 बजे यह सूचना थाने पहुंची। उसी समय फौरन फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गया और आग बुझाई गई दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है कि इसकी एफ0आई0 आर0 किसने लाज करायी, उसी दिन 12-2-82 को यह घटना हुई है ढाई, तीन बजे की। समय है 15.50 बजे की जब सूचना लिखाई गई। नाम वादी का बुल्ले राम पुत्र झूम्मे राम, नई बस्ती, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। तीसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा कि वह जमीन कब्रिस्तान की है या नहीं, मान्यवर, यह विषय विवादास्पद है। जब हरिजनों को यहां बसाया गया 14-15 वर्ष हुए तो नगरमहापालिका के तत्कालीन चेयरमैन श्री अब्दुल्ला ने वहां उनको बसाया था। जिस दिन यह घटना हुई उसके कुछ दिन पहले से यह विवाद पैदा किया गया कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। यह विवादास्पद हो गया है। इसकी जानकारी की जा रही है कि यह जमीन असल में नगरमहापालिका की है या कब्रिस्तान की।

श्री बिहारी लाल--

अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि 18 तारीख को जिलाधिकारी के साथ मैं उस स्थान पर पहुंचा। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई भी हरिजन बाहर बैठा नहीं है। मैं उसके फोटोग्राफ माननीय मंत्री जी को पेश कर दूंगा। अभी भी वह हरिजन बाहर बैठा हुआ है। मैंने प्रार्थना की जिलाधिकारी से कि जो जमीन कब्रिस्तान की है उसकी कितनी लिमिट है और कितना उसका रकबा है उसे साफ कराया जाय और जो जमीन म्यूनिसिपल बोर्ड की है उसको अलग किया जाय। जिलाधिकारी की सूझ बूझ से बड़ी ईमानदारी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना टली नहीं तो ऐसा प्लान था कुछ विपक्षी लोगों का। ऐसा लगता था कि जिस तरह से मुरादाबाद की कहानी बनी उसी तरह यहां भी बनाना चाहते थे। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करें और कितना मुआवजा उन हरिजनों को दिया गया यह बताने की कृपा करेंगे ? जैसा आप ने कहा हरिजनों की व्यवस्था की जा रही है, मैंने खुद देखा कि हरिजन बाहर बैठे हुये हैं। हमारी सरकार है। हमारे मंत्री जी हैं। अगर इस में कदम नहीं उठाये जायेंगे.....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न पूछिये आप तो भाषण करने लगे। प्रश्न पूछिये। कितना मुआवजा दिया गया यह प्रश्न है।

श्री बिहारी लाल--

माननीय मंत्री जी मुआवजा कितना दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

350 रुपये प्रति परिवार दिया गया है और अगर आप आज्ञा दें तो यह भी बता दूं कि 1200 रुपये टोटल लास आग से जलने से सामान का हुआ है। उस सामान में चमड़ा और झोपड़ी है। कुछ वहां पर लकड़ी रखी थी जलाने के लिये उस में आग लगी।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई है, वह बहुत कम है इसलिये क्या मंत्री जी उसको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपने यह सुझाव दिया है कि इस धनराशि को बढ़ा दिया जाय। यह एक कन्स्ट्रक्टिव और सुन्दर सुझाव है, इसलिये इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जिन हरिजनों का नुकसान हुआ है, वह कितना हुआ है, अनुमानित ही बताने की कृपा करेंगे ? दूसरे यह कि क्या उनके रहने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं माननीय सदन को यह भी सूचित कर दूं कि वही पर एक "नई बस्ती" मोहल्ला है जहां पर उनके अस्थायी घर हैं वहां पर वे चमड़े का कारोबार करते थे। इसलिये यह कोशिश की जा रही कि वे कहीं पर बस जांय। इसके बारे में वहां के लोगों और अब्दुल्ला साहब से बातचीत चल रही है कि उनको कहीं पर भूमि दे दी जाय। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है अवश्य इन्तजाम किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 49 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
25 फरवरी, 1982।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 437 पर)

खरीफ वर्ष 1981–82 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, द्वारा देवरिया जिले में स्थापित किये गये धान खरीद केन्द्रों के नाम

क्र0-सं0	तहसील का नाम	नाम ब्लाक	क्रय केन्द्र का नाम
1	देवरिया ..	देवरिया ..	1—डी0सी0डी0एफ0, देवरिया
		बैतालपुर ..	2—सहकारी संघ, पलिपवां
		देवरिया ..	3— ,, पैकोली
		गौरी बाजार ..	4— ,, गौरी बाजार
	(सलेमपुर)	भलुवनी ..	5— ,, भलुवनी
2	पड़रौना ..	तमकूही राज ..	1— ,, तमकूही रोड (सेवरही)
		रामपुर कारखाना	2— ,, तरफुलवा
		फाजिल नगर..	3— ,, फाजिलनगर
		कसया ..	4— ,, कसया
		रामकोला ..	5— ,, राम कोला
		सुकरौली ..	6— ,, तुरपट्टी महुअवां
		पड़रौना ..	7—क0 वि0 पड़रौना
3	हाटा ..	देसही देवरिया (देवरिया तहसील)	1—सहकारी संघ हेतिमपुर
			2— ,, देसही देवरिया
		सुकरौली ..	3— ,, बखुवारामपुर
		कप्तानगंज ..	4—डी0सी0डी0एफ0, कप्तानगंज
		खड्डा ..	5—सहकारी संघ, खड्डा
		सुकरौली ..	6— ,, महुअवा
		कप्तानगंज ..	7—डी0सी0डी0एफ0, भैसही, बाजार
		कसया ..	8—सहकारी संघ, अहिरौली बाजार
		कप्तानगंज ..	9— ,, दोदरवार
		हाटा ..	10— ,, हाटा
		हाटा ..	11— ,, दाढा बुजुर्ग
4	सलेमपुर ..	सलेमपुर ..	1—क0 वि0स0 सलेमपुर
		बरहज ..	2— ,, बरहज

वर्तमान खरीफ मार्केटिंग वर्ष 1981–82 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु जनपद देवरिया में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गये धान क्रय केन्द्रों की सूची:—

1—हाटा 2—रामपुर कारखाना 3—देवरिया (प्रापर)

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 445 पर)

देवरिया जनपद में 1-1-81 से 31-12-81 के मध्य की गयी नियुक्तियां		नियुक्त किये गये कर्मचारियों में से				जनपद देवरिया में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		कायरत कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या				कार्यरत कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत			
तृतीय श्रेणी कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या		तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
		अनुसूचित जाति की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या			अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	12	9 14.29%	16 25.4%	6 50%	3 25%	1331	527	168	246	268	137	12.62%	18.84%	50.83%	25.99%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 453 पर)

महामन्द जलाल नगर, भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना जनपद शाहजहांपुर

क्रमांक	काश्तकारों का नाम व वल्दियत	पता	विवरण
1	श्री हमीदउल्ला खां, पुत्र अहमद उल्ला खां शफायत उल्ला खाँ पुत्र श्री अजमत उल्ला खां।	निवासी महामन्द जलाल नगर शाहजहांपुर।	
2	श्री हमीद उल्ला खां, पुत्र श्री अजमद उल्ला खां।	निवासी महामन्द जलालनगर शाहजहांपुर।	
3	श्रीमती मुराद बेगम पत्नी हिब्मू खां व श्रीमती नियाज बेगम पत्नी हसायत उल्ला खां नि0	निवासी महामन्द जलालनगर, शाहजहांपुर।	
4	श्रीमती यूफीज बेगम बेवा मो0 शफी खां	निवासी महामन्द जलालनगर, शाजहांपुर।	
5	इसरार हसन खां, पुत्र अब्दुल हसन खां	तदैव	
6	श्री रफामत उल्ला खां व अहमद उल्ला खां पुत्र गण अजमत उल्ला खां।	तदैव	
7	श्री कशीलाल लीलाधर, बृजकिशोर व रामकिशोर पुत्र गण शम्भू दयाल।	बीवी जई हदक, शाहजहांपुर	
8	श्री चेता पुत्र शिव सहाय, राम प्रसाद व श्रीकृष्ण पुत्र गोविन्द।	महामन्द जलालनगर, शाहजहांपुर।	
9	श्री बृजकिशोर व राम किशोर, पुत्रगण शम्भूदयाल व केशी लाल पुत्र लीलाधर।	बीवी जई हदक शाहजहांपुर	
10	श्री मकसूर खां मकबूल खां, अब्दुल हमीद खां व अब्दुल जलील खां, पुत्रगण विधायत उल्ला खां।	निवासी महामन्द, जलालनगर शाहजहांपुर।	
11	श्री बालकराम पुत्र सुल्थ	तदैव	
12	श्री मोहम्मद खां पुत्र विद्यायत उल्ला खां	तदैव	
13	श्री छोटे व पुत्तू पुत्रगण अम्मर	तदैव	
14	श्री मोंदा खां पुत्र नियामत उल्ला खां	तदैव	
15	श्री हवेलीराम पुत्र मोहन लाल	नि-बहादुर गंज	

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 456 पर।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 158 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक संशोधनों का विवरण ।

प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 456 पर।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 तथा 158 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधनों एवं मुद्रण की त्रुटियों के शोधन का विवरण।

नियम 147 के अन्तर्गत

खण्ड 2 — (1) मद (ख) की पंक्ति 1 के अन्त में "--" (डैश) के स्थान पर चिन्ह ":—" (कोलन तथा डैश) रख दिये गये हैं।

(2) मद (ख) की पंक्ति 8 में शब्द "अधीन" और शब्द "विज्ञापित" के मध्य चिन्ह "1" हटा दिया गया है।

खण्ड 3 — (1) प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (1) की मद (ङ) की पंक्ति 1 में चिन्ह तथा "(क)" तथा "(ख)" एवं चिन्ह तथा शब्द "(ख)" तथा "(ग)" के मध्य "," (कामा) रख दिया गया है, और इसी मद (ङ) की पंक्ति 2 में शब्द "द्वारा" तथा शब्द "बिक्री" के मध्य मुद्रित चिन्ह "," (कामा) निकाल दिया गया है।

(2) उपखण्ड (2) की पंक्ति 1 में शब्द "धारा" तथा शब्द "अधीन" के मध्य मुद्रित अक्षर "क" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया गया है।

खण्ड 6 — मद (क) की पंक्ति 4 में शब्द "हो गी" तथा चिन्ह "," (इन वर्टेड कामा) के मध्य चिन्ह ";" (सेमीकोलन) के स्थान पर चिन्ह "," (कामा) रख दिया गया है।

खण्ड 13 — पंक्ति 2 के अन्त में चिन्ह "–" (डैश) के स्थान पर चिन्ह ":–" (कोलन तथा डैश) रख दिये गये हैं।

खण्ड 16 — प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) की पंक्ति 1 में शब्द "लिये" तथा शब्द "उपधारा" के मध्य मुद्रित चिन्ह "," (कामा) निकाल दिया गया है।

अनुसूची — (1) मद 12 की पंक्ति 1 में शब्द "विटयूमिन" के स्थान पर शब्द "बिटयूमिन" रख दिया गया है।

(2) मद 24 में शब्द "कोको" तथा शब्द "और" के मध्य मुद्रित चिन्ह "," (कामा) को हटाकर यह चिन्ह शब्द "काफी" तथा शब्द "को" के मध्य रख दिया गया है।

(3) मद 40 की पंक्ति 3 में शब्द "प्रवलित" के स्थान पर शब्द "प्रबलित" रख दिया गया है।

खण्ड 20 — पंक्ति 3 के अन्त में चिन्ह "–" (डैश) के स्थान पर चिन्ह ":–" (कोलन तथा डैश) रख दिये गये हैं।

खण्ड 22 (1) उपखण्ड (1) की पंक्ति 1 के अन्त में चिन्ह "," (कामा) निकाल दिया गया है।

(2) उपखण्ड (6) की पंक्ति 5 में शब्द "व्यापारी" के स्थान पर शब्द "व्यापारी" रख दिया गया है।

खण्ड 24 उपखण्ड (2) के अन्त में शब्द "थे" के बाद चिन्ह "।" (पूर्ण विराम) जोड़ दिया गया है।

नियम 158 के अन्तर्गत

प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 24 वि0 सभा—30—7—83—(1581)—1983—813(प्रो0)।